General Discussion on the Union Budget (2024-25), General Discussion on the Budget of Union Territory of Jammu And Kashmir (2024-25) and Demands for Grants in respect of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2024-25

माननीय अध्यक्ष**:** आइटम नंबर 14 से 16 एक साथ लिए जा रहे हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तंभ में मांग संख्या 1 से 36 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों का भुगतान करने के निमित्त अथवा के उद्देश्य से, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी रकमों से अधिक न हों, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से राष्ट्रपति को लेखे पर प्रदान की जाए ।?

<image: image001.gif>

<image: image002.gif>

<image: image003.gif>

माननीय अध्यक्ष**:** कुमारी सैलजा ।

कुमारी सैलजा **(**सिरसा**) :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी बतौर महिला वित्त मंत्री जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कि इन्होंने छ: बार बजट पेश किया है । साथ में बतौर कांग्रेस एमपी मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसे बड़ी मेहनत के साथ हमने तैयार किया । हमने कोई गारंटी इनकी सरकार की तरह, मोदी जी की गारंटी की तरह नहीं कहा, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जा-जाकर, लोगों को गले लगाकर, उनके दुख-तकलीफ समझकर

इस मैनिफेस्टो को सबके साथ मिलकर तैयार किया । इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, अपनी गारंटी को साइड में रखा और हमारे मैनिफेस्टो को लागू किया । मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूं । अब मैं इस बजट पर क्या बोलूं?, कुर्सी बचाओ बजट बोलें, बजट नहीं, लेकिन विचलित बजट बोलें या फिर एक और जुमला बजट बोलें, क्योंकि बार-बार हमें इसमें जुमले नजर आते हैं । आपने चार लोगों की बात की, लेकिन ये 4 कौन लोग हैं? गरीब, महिलाएं, युवा, हमारा अन्नदाता किसान । लेकिन इनकी गिनती कैसे हो? क्या मालूम पड़े कौन क्या है? क्या मालूम पड़े कि ये योजनाएं किसके लिए बनाएं? क्या मालूम पड़े कि टारगेट ग्रुप कौन है? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, अगर आप सेंसस को सार्वजनिक नहीं करेंगे, राहुल जी, हमारे नेता ने मांग की कि कास्ट सेंसस किया जाए, लेकिन यह सरकार चुप्पी साधे हैं । And I wonder, कि इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे कास्ट सेंसस के बारे में? उन्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन यह बजट है किसके लिए यह भी तो पता चले? क्या केवल दो राज्यों पर ही मेहरबानी हुई है या पूरे देश पर भी नजर डाली गई है? ऐसा नजर नहीं आता कि दो राज्यों के अलावा कुछ दिखा हो या फिर भाजपा शासित प्रदेशों के अलावा कुछ नजर आता हो ।

सर, मुझे याद आता है कि जब माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी, मुख्य मंत्री होते थे और उस समय हमारी सरकार थी और वह एनडीसी की मीटिंग में आते थे । अब एनडीसी नहीं रहा । वह हमेशा को-ऑपरेटिव फेडरेलिज्म की बात कहते थे । अब शायद वह शब्द पूरी शब्दावली से निकल चुका है । कम से कम भाजपा की और सरकार की शब्दावली से निकल चुका है, लेकिन दो राज्यों को भी मैं थोड़ा आगाह करना चाहूंगी । नीतीश जी तो हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं । ये 10 वीं लोक सभा में थे । सब समझते हैं । नायडू जी भी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं । इनकी बातों पर न जाएं । आज बेशक लगता हो कि बहुत-कुछ दिया है, लेकिन नजर फेरते देर नहीं लगती । इसलिए उनको भी मैं आगाह करना चाहूंगी, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगेगी । पेश किए गए बजट में इन्होंने गारंटी की बात की, शायद लोगों को विश्वास नहीं हुआ । इसीलिए 303 से लेकर 241 पर आ गए । विश्वास पैदा करना इनका काम है । इन्होंने विश्वास खोया, तभी यह डाउन स्लाइड हुआ । आज के दिन भी जब बातें होती हैं, बजट में हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पर मेहरबान और बाकियों को दरबान बना दिया गया । दरवाजे के बाहर खड़े रहो । अगर मेहरबानी होगी, तो शायद आपको कुछ मिल पाएगा ।

सर, प्राकृतिक आपदा की भी बात होती है । भाजपा शासित प्रदेशों के लिए तो सेंट्रल असिस्टेंस की बात की गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जब बात हुई तो एक्सटर्नल एजेंसीज की बात आ गई कि उनके माध्यम से मदद की जाएगी । ऐसा भेदभाव क्यों? यह नहीं होना चाहिए । इसकी हम घोर निन्दा करते हैं । आप सबके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? एक बात और है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और शायद जम्मू-कश्मीर चुनाव की ओर जा रहे हैं । लेकिन, ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली है । इन तीनों राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ है । उनको कुछ दिया तक नहीं और दु:ख इस बात का है कि केंद्र में आज तीन-तीन केंद्रीय मंत्री हरियाणा से हैं । इनमें से एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला । मुझे मालूम नहीं कि इनकी अंदरूनी क्या बातें होती हैं । खैर वह तो सार्वजनिक नहीं हो सकती है । लेकिन, दुर्भाग्य मेरे राज्य हरियाणा का है कि तीन-तीन केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हरियाणा को ये कुछ नहीं दे पाए हैं और नाम तक लेना भी मुनासिब नहीं समझा ।

सर, जहां तक किसान की बात है तो किसान की आय दुगुनी करने की बात कही गई थी । स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है । कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है । वर्ष 2019-20 में जहां यह 4.97 प्रतिशत था, इस बजट में आपने 2.74 प्रतिशत करके छोड़ दिया है ।

अब हम एमएसपी की बात करते हैं । एमएसपी के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बार बहुत से उपजों को एमएसपी दिया है । लेकिन, क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सी-2 प्लस 50 प्रतिशत का फॉर्मूला अपनाया है? आपने बिल्कुल नहीं अपनाया है, क्योंकि आप उसे भूल चुके हैं । मैं उसे थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी । यह बढ़ाने के बावजूद, जब हमारी यूपीए सरकार थी, उस समय हमने गेहूँ की एमएसपी 119 प्रतिशत और धान की 134 प्रतिशत बढ़ाई थी । लेकिन, मोदी जी की सरकार ने केवल 47 प्रतिशत गेहूँ की और 50 प्रतिशत धान की बढ़ाई है । इसमें पीठ थपथपाने जैसा कुछ नजर नहीं आता है । आज के दिन इतनी एग्रेरियन क्राइसेज है, खासकर हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है । किसान एक साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया । ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों । ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ।

ये पूंजीपतियों के मित्र हैं, यह दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं । किसान अपने दु:ख को समझते हुए यह जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा ।

सर, हमारी सरकार ने किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था । लेकिन, आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपये माफ किया है । आपका किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है । शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो वे आलसी हो जाएंगे, वे पैदावार नहीं करेंगे और वे काम नहीं करेंगे । शायद यही शंका है, मैंने कहीं पर पढ़ा है । नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपये के कर्जे में है । यह नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं है । साथियों, ऐसी बात नहीं है, फिर से वही बात आ गई, ?मित्रों पर मेहरबानी और किसानों तथा मजदूरों से बेईमानी? ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, क्या यह नाबार्ड का फिगर है?

कुमारी सैलजा **:** जी सर, यह नाबार्ड का फिगर है । मैं यह इसलिए कह रही हूं, क्योंकि आपने किसानों के साथ समझौता किया, लेकिन आपने वादाखिलाफी की । हर बात में आपने वादाखिलाफी की । कौन-सा साल था? वह वर्ष 2021 था । आज कौन-सा साल आ गया है, कौन-सा समय आ गया है? किसान अपना दु:ख लेकर अभी भी बैठा है । आप किसान को उग्रवादी मत कहिए । आप किसान को उग्र होने पर मजबूर मत कीजिए । आपने किसान और मजदूर को मजबूर और मजदूर दोनों बना दिया है । आपका किसी ओर ध्यान नहीं है ।

इसके ऊपर एक फसल बीमा योजना की बात है । मैं अपने प्रदेश की बात कर सकती हूं । फसल बीमा योजना से, आप किसान से प्रीमियम का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वह सालों-साल बैठा रहता है । मेरी अपनी कांस्टिट्यूएंसी नरवाना में किसान तीन सालों से मुआवजे के लिए बैठा है । उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है । बीमा कंपनियों को 3,40,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला है, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है, तो वह दर-दर भटकता रहता है । कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान धरने पर बैठा रहा । 736 किसान शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया और न ही उन्हें कुछ देने की बात की गई । आज भी हरियाणा और पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वे मजबूर हैं । लोगों को आने-जाने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते हैं, जो उस बॉर्डर पर बैठे हैं ।

किसान क्या मांग रहे हैं? आप एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है । इस वायदे को क्यों नहीं याद करते हैं? जब तक आप किसान को उसकी एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देंगे, तब तक आप

किसान के साथ इंसाफ़ नहीं कर सकते हैं । आप किसानों से पूछ लीजिए । आपने जिस अन्नदाता की बात की है, अगर अन्नदाता कमजोर होगा, तो ये देश कभी भी पनप नहीं सकता है, न ही किसी का विकास और न ही विकसित भारत बनेगा, अगर इस तरह से किसान और मजदूर मजबूर हो जाएंगे ।

हमने अपने मैनिफेस्टो में किसानों को लीगल गारंटी देने की बात कही है । अगर आप हमारे मैनिफेस्टो का ये बिंदु भी पढ़ लेते तो, बहुत अच्छा होता । मजदूरों की दयनीय स्थिति और खास तौर से ग्रामीण मजदूरों की जो स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में मजदूरी वृद्धि हर साल केवल एक प्रतिशत की गई है, उससे भी कम है । अगर मनरेगा की बात करें, मुझे इस बात का दुख हुआ कि पूरे बजट में मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया । मनरेगा तो वह है, जिसे आप पहले नकारते थे । फिर आपने समझा और उसको अपनाया । बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम पर कटाक्ष करके मनरेगा को अपनाया, लेकिन उसको अपनाया । अगर कोविड-19 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सेवियर था, तो वह मनरेगा था । आप आज मनरेगा को भूल गए हैं । मनरेगा के बजट को याद ही नहीं रखते हैं ।

जब आप गरीब और मजदूरों को याद ही नहीं रखेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है । किसान और ग्रामीण-खेतिहर मजदूर का चोली-दामन का साथ है । आपने इन दोनों को भुला दिया है । देश कहां आगे जाएगा? आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों को घुसा दिया है । वहां पर साइलोज लग गए, मंडियों में मजदूरों का बुरा हाल है । आज वे बेरोजगार हो गए हैं । आज उनको 2,000 या 3,000 रुपये महीने के मिलते हैं । मजदूर और दयनीय हो गए हैं । आपको इसका ध्यान रखना चाहिए । प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन 400 रुपये होने चाहिए, ये पूरे देश की डिमांड है । हम कहते हैं कि जब हमारा समय आएगा, तब हम 400 रुपये जरूर करेंगे और यह होना चाहिए । सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को मानना चाहिए । आप न्यूनतम वेतन 400 रुपये करें ।

कृपया आप गरीब को 5 किलो अनाज देकर लाइन में न खड़ा करें । उसे उसका हक दें । उसको ऊपर उठाने की बात करें । आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो क्या 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे? क्या वे हमेशा गरीब रहेंगे? अमीर, अमीर होता जाएगा, जीडीपी बढ़ती जाएगी, किसके लिए? केवल आंकड़ों के लिए ।

महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है । सुषमा स्वराज जी बहुत ही सम्मानित नेता थीं । हम सभी उनको मानते थे । वह भाजपा की वरिष्ठतम नेताओं में से एक थीं । मुझे याद है कि जब एक बार बजट पेश किया जा रहा था, तब प्रणव मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे । उन्होंने कहा था कि दादा, आंकड़ों से पेट नहीं भरता है । मैं सत्ता पक्ष को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आंकड़ों से पेट नहीं भरेगा, गरीब और युवा को रोजगार चाहिए, गरीब को वेतन चाहिए । आप गरीब को केवल 5 किलो अनाज देकर आखिरी पंक्ति में खड़ा मत करिए । आप महंगाई पर नियंत्रण लाइए । आप महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आप आम उपभोक्ता को कोई राहत देते हैं? क्या किसानों तक कोई राहत पहुंचती है? क्या गरीब तक कोई राहत पहुंचती है?

आज इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है? फूड इन्फ्लेशन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने पासिंग में कहा था कि हम इसका इंतजाम करेंगे, लेकिन कैसे इंतजाम करेंगे? दाल, सब्जियां, सब चीजें इतनी महंगी होती चली जा रही है तो क्या केवल अनाज रहेगा? क्या गरीब आदमी सब्जी न खाए, प्याज न खाए, आलू न खाए, कोई सब्जी न खाए? ये सब्जियां उस तक नहीं पहुंचती हैं । अगर ये चीजें पहुंचती भी है तो महंगी मिलती हैं । ? (व्यवधान)

यह तो अपने-अपने खाने का अलग टेस्ट है, वह कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब आदमी तो प्याज और आलू खाता है, उसको कुछ और नहीं मिलता है । आपको आटे और दाल का भाव पता होना चाहिए ।

महोदय, आपने एलपीजी के द्वारा आंसू पोंछने की बात कही थी, लेकिन आज आपको महिलाओं और बहनों के आंसू नजर नहीं आते हैं । हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर इस कदर गिरता चला जा रहा है कि मेरे अपने राज्य में प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की संख्या में बंद होते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार का उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है । सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं पढ़ते हैं । हमारे मां-बाप सरकारी स्कूलों में पढ़कर ऊपर आए थे और उन्हीं के कारण आज हम यहां पर खड़े हैं । अगर आप सरकारी स्कूल इस तरह से बंद करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा?

यहां पर नीट की बात कही गई । हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया । उन्होंने जो कहा था, उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता है? आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप सरकार में है । अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो देश आपको दिखा देगा, हमारा युवा आपको दिखा देगा । बेरोजगारी की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है । आईएलओ के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में यूथ की अनएंप्लॉयमेंट हमारे यहां 23 प्रतिशत थी, चीन में 13 प्रतिशत, पाकिस्तान में 11 प्रतिशत थी । सीरिया, जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पर 22 प्रतिशत है तो हमारे यूथ की यह बदहाली क्यों हो रही है?

महोदय, आप स्किलिंग की बात करते हैं । क्या आपने पहले प्राइवेट सेक्टर से बात की? क्या वह आपकी बात और आपकी स्कीम मानेगा, जिसको आपने इतने विस्तार से अखबारों, मीडिया में दिखाया? मीडिया आप कंट्रोल करते हैं । उसे मीडिया में इस कदर दिखाया गया है, लेकिन क्या आपने उन कंपनियों से बात की है? इस बात की क्या गारंटी है कि वह एक बार आपकी स्कीम का फायदा उठाकर इन बच्चों की दो-तीन महीनो में छुट्टी नहीं करेंगे, जिनको रोजगार मिल रहा है? ऐसे कैसे बात बनेगी? अगर आप हमारा मेनिफेस्टो पढ़ते तो पहली नौकरी पक्की का वायदा हमारे राहुल जी ने किया था । आप उसको सुन लेते । केंद्र में 10 लाख वैकेंसीज़ खाली हैं, हरियाणा में दो लाख वैकेंसीज़ खाली हैं, उनको भरने की बात क्यों नहीं की जाती है? इसके अलावा एससी, बीसी का बैकलॉग है । आप उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं । आप बैकलॉग को भी भरिए । प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा आएगा तो क्या आपने वहां पर आरक्षण दिया है? हमारे लोग कहां जाएंगे? रेलवे और डिफेंस में रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने सारी नौकरियां बंद कर दी है? हमारा युवा कहां जाएगा और स्किल इंडिया का क्या हुआ? आज के दिन बेरोजगारी इस कदर आपके सामने मुंह बाए खड़ी है, मगर आपको नजर नहीं आता है । अगर आपको नजर नहीं आता है तो आने वाले राज्यों के चुनाव में नजर आ जाएगा । वैसे, अभी जो उप चुनाव हुए थे, उनमें भी आपको नजर आ गया होगा ।

साथियो, जब बेरोजगारी इतनी बढ़ती है तो गलत आदतें भी बढ़ जाती हैं । मेरे अपने राज्य में सिरसा, हिसार, अम्बाला और पूरे हरियाणा में नशा बढ़ता चला जा रहा है । हरियाणा कहां था? हमारे यहां बोलते हैं कि ?देशां में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना?, लेकिन आज के दिन हरियाणा ऐसा देश हो गया है, जो अपराध और नशे का ठिकाना बन गया है ।

मैं एक-दो बिंदुओं पर नजर और डालूंगी । अग्निवीर की बात है । अग्निवीर के खोखलेपन का पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया है । सरकार कितने ही टॉल क्लेम्स करे, लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो आपको असलियत पता चल जाएगी । आपने दो कैटेगरीज़ बना दी हैं । एक अफसर और जो साधारण जवान है, वह शहीद हो जाएगा तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी । जो गरीब का बेटा है, वह गरीब का बेटा केवल

अग्निवीर कहलाएगा, उसे केवल नाम मिलेगा । उसको और क्या मिलेगा? वह कैसे जाएगा? आप सेना के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे युवा के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं और हमारे जवान के साथ भी आप नाइंसाफी कर रहे हैं ।

14.00 hrs

सर, हरियाणा की आबादी देश की लगभग दो प्रतिशत है, लेकिन सेना में हमारा हिस्सा दस प्रतिशत के करीब है । आज के दिन आपने हमारे युवाओं के लिए क्या इंसेंटिव छोड़ दिया है? कुछ नहीं छोड़ा है । यह योजना पूरी तरह से युवा विरोधी है, जवान विरोधी है और सेना विरोधी है । हम डिमांड करते हैं कि आप अग्निवीर योजना को इमिडिएटली खत्म कीजिए और ?जय जवान, जय किसान? के नारे को फिर से बुलंद कीजिए । किसान को भी खुशहाल कीजिए, जवान को भी खुशहाल कीजिए ।

सर, एससी-बीसी की बात मैंने कही । न बैकलॉग खत्म किया जा रहा है और न ही नई नौकरियां मिल रही हैं । प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए कुछ नहीं है । इनकी प्री-मेट्रिक और पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप के साथ नाइंसाफी की जाती है, समय पर बच्चों को नहीं दी जाती है । हरियाणा में मेडिकल दस हजार के करीब स्टूडेंट्स थे । उनको तीन-चार साल से स्कॉलरशिप नहीं दी गयी । जब चुनाव आया, तब आपने रिलीज़ की । इसमें भी गरीबों के साथ राजनीति! क्या आप हमारे एसी-बीसी के साथ भी राजनीति करेंगे? क्या पैसे की इतनी किल्लत है कि आप गरीब से गरीब को उसकी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते? डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप से ही आगे पढ़ पाए थे । डॉ. अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे । लेकिन अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे तो वे कहां से आगे निकलेंगे?

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्या, यह संसद है, हरियाणा विधान सभा नहीं है । इसका जवाब माननीय मंत्री जी कैसे देंगी?

कुमारी सैलजा **:** सर, यह बजट है । इसमें हरियाणा राज्य की अनदेखी हुई है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** यह बजट तो है, लेकिन राज्य के विषय पर माननीय मंत्री जी कैसे जवाब दे सकती हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** सही बात कहनी चाहिए ।

? (व्यवधान)

कुमारी सैलजा **:** सर, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन आप राजस्थान से हैं और आप राजस्थान से प्यार करते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं राजस्थान विधान सभा में बोलूंगा ।

कुमारी सैलजा **:** आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान खत्म कर दिया । सब प्लान बंद कर दिए और सारे फण्ड्स डायवर्ट किए जाते हैं । एकाध दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट थी कि मध्य प्रदेश में फण्ड्स डायवर्ट कर दिए गए । किस चीज के लिए गए- गऊशालाओं के लिए । गऊशाला और एससी-एसटी का क्या लेना देना है? लेकिन एससी-एसटी के फण्ड्स आप गऊशालाओं में दे रहे हो । यह डायवर्जन हो रहा है और सरेआम हो रहा है । क्यों आप गरीबों के बजट पर, एससी-एसटी के बजट पर डाका डाल रहे हैं?

सर, जहां तक हेल्थ की बात है तो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर गिरता चला जा रहा है । पिछले दो साल में बजट एस्टिमेट्स और बजट एक्सपेंडिचर में दो प्रतिशत का फर्क आ गया है । आगे यह और गिरता चला जाएगा । हेल्थ सेक्टर में आपकी कमिटमेंट कोविड के टाइम तो दिखी थी, लेकिन उसके बाद भूल गए ।

सर, यह बुरा मनाने की बात नहीं है, क्योंकि अपना राज्य तो अपना ही होता है, इसलिए मुझे बोलने दीजिए । हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आयुष यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा था । लेकिन आज तक एक पत्थर नहीं लगा है । माननीय वित्त मंत्री जी पता करें । सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने रखा था, लेकिन वहां अभी तक टेंडर तक नहीं हुआ है ।

आपने बच्चों के बारे में एक शब्द नहीं कहा है । कुपोषण सबसे ज्यादा हमारे यहां है । ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 के मुताबिक 125 देशों में इंडिया की दर 111 है । पिछले साल 107 थी, इस साल 111 पर हम आ गए हैं । भुखमरी, कुपोषण और बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? महिलाओं की जहां तक बात है तो हमारी बात सुन लेते, राहुल जी ने प्रोमिस किया था कि हर गरीब परिवार में हम एक महिला को एक लाख रुपये देंगे । अगर आप यह दे देते तो महिलाओं का अपने आप उद्धार हो जाता । आप हमारी बात मान लें । इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, हमारे पास हैं । आप हमारे आइडियाज़ ले लें, सुझाव ले लें तो देश का भला हो जाएगा ।

हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब यहां मंत्री हैं । उनके पास बहुत बढ़िया मंत्रालय है । आपको नाम बदलने का बड़ा शौक है । जेएनयूआरएम, राजीव आवास योजना के नाम से आपको थोड़ी दिक्कत है, शायद नफरत है तो आपने नाम बदलकर स्मार्ट सिटी रख दिया । फरीदाबाद दिल्ली से दो कदम दूर है । It is an overgrown urban slum. वह कहां से स्मार्ट सिटी है? हर जगह कचरे के ढेर हैं । मिलेनियम सिटी गुरूग्राम से मंत्री और एमपी का दो दिन पहले इंटरव्यू छपा था कि वहां कचरा प्रबंधन की क्या बदहाली है? आप उनकी बात ही सुन लें । वहां पर क्या हो रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ कि यहां पर जो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री हैं, वे अपनी कुलीग की बात सुनेंगे । दूसरे, फरीदाबाद के एक और केन्द्रीय मंत्री हैं, उनकी बात सुनेंगे । आप इन शहरों का थोड़ा कल्याण कीजिए । मैं जानती हूँ कि आप हरियाणा की तरफ से हताश हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा की जनता के लिए आपको 10 सालों का मौका मिला तो आप कुछ तो कर दीजिए । हरियाणा के लिए कुछ तो कर दीजिए ।

स्वच्छ भारत का कहीं पर जिक्र ही नहीं है । शायद आप भूल गए हैं । वह ऐनक भी फेड हो गई, जो आपने गांधी जी की ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी । वह ऐनक भी अब नजर नहीं आ रही है । पता नहीं क्या हुआ, शायद उस कचरे में ही आपने उसको भी लिप्त कर दिया है ।

सर, यहां पर अभी माननीय रेलवे मंत्री जी थे । चलिए, रेलवे की बात मेरे कुलीग्स कर लेंगे । मैं सिर्फ एक-दो मिनट लेकर अपना भाषण खत्म करूंगी । हरियाणा में रेलवेज़ का भी जो हाल है, उसे मेरे कुलीग डिटेल में बता देंगे, लेकिन मैं एक-दो बातें जरूर कहूंगी कि उस समय जो मुख्य मंत्री थे, उन्होंने गुडगांव-फरीदाबाद के लिए जनवरी, 2016 में कहा था और ट्विट किया था, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ । बल्लभगढ मेट्रो सैंक्शन हुई थी, लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं है । उसके लिए न कोई प्रावधान किया गया, न ही एनसीआर का ध्यान रखा गया और न हमारे राज्य का ध्यान रखा गया ।

सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ष 2019 में प्रॉमिस हुआ था । हिसार में वर्ष 2021 तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है, न ही उसके बारे में कुछ मालूम है । इसके अलावा मैं न्युक्लियर प्लांट, गोरखपुर के बारे में बताना चाहूंगी । हिसार के पास गोरखपुर है । आपने एनर्जी के बारे में

काफी कुछ कहा है । हमें काफी खुशी है, लेकिन उसका क्या हुआ? आप उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें कि वह किस स्टेज पर है, कब शुरू होगा? हम उसे कब देखेंगे और हमें वहां से बिजली कब मिलेगी? अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया उस न्युक्लियर प्लांट के बारे में भी बता दें तो उसके बारे में हमें पता चलेगा ।

सर, आज के दिन कुछ और बचा नहीं है । यूथ ने आपको पनिश कर दिया, महिलाओं ने आपको पनिश कर दिया । आपने हमारे किसानों की इंसल्ट की । उन्होंने भी आपको पनिश कर दिया । अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया । यह बहुत दुख की बात है कि आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं । अगर माननीय प्रधान मंत्री जी इंटरवीन करें तो हम देश के लिए केवल यह चाहते हैं कि आप देश को बताइए कि देश आपको जो दिशा दिखा रहा है, क्या आप उससे कोई सीख ले रहे हैं? आप उससे कुछ सीख लें । आप अग्निवीर को स्क्रैप कीजिए । एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए और फार्म लेबर के लिए, हर लेबर के लिए 400 रुपये प्रतिदिन कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा, जो बाकी देश ने आपको दिखाया है ।? (व्यवधान)

यह स्लोगन की सरकार है इसलिए आपका आखिरी स्लोगन यह है कि ?कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ ।?

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे राज्य से सांसद के नाते चुनकर आया हूँ । वहां के सिर्फ दो ही एमपी हैं । सिक्किम के बाद वह सबसे छोटा राज्य है । आज मुझे इस बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं हमारे दल के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ । साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से इस बजट को प्रस्तुत किया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ और उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सैलजा जी बोल रही थीं, तो मैं सुन रहा था । नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2014 से प्रधान मंत्री के रूप में काम शुरू किया है । उस समय 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट जो आर्थिक स्थिति छोड़ कर गई थी, तो यह अनुमान किया जा रहा था कि भारत फ्रेजाइल पांच देशों में चला जाएगा । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है । आर्थिक विषमता और कोरोना काल के बावजूद भी, आज के आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक रहेगी । यह बजट एक फोक्स्ड बजट है । ?(व्यवधान) लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है । इसमें वर्ष 2023-24 से लगभग 18.2 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है । जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब ऑपर्चुनिटी बढ़ती है । इसके साथ-साथ फेडरलिज्म, स्टेट के बारे में बताया जाता है । मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें 4 लाख, 82 हजार करोड़ रुपए, इस बजट से सभी राज्यों का शेयर ज्यादा जाएगा । इस लिए सैलजा जी दो राज्यों के बारे में बात कर रही थी । यह हो सकता है कि कांग्रेस के खाते में बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है । हमारे खाते में ये दोनों राज्य हैं और बाकी अन्य सभी राज्य भी हैं ।?(व्यवधान) इसलिए इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने सर्वांगीण विकास की तरफ रुख किया है । वर्ष 2013-14 में बजट 16 लाख करोड़ रुपए के आस-पास होता था, जो कांग्रेस का लास्ट बजट था, आज वह 48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा हुआ है ।?(व्यवधान) इन पांच सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार कौशल योजना से अर्निंग के अवसर मुहैया कराए जाएंगे । अभी रोजगार के बारे में बात हो रही थी ।?(व्यवधान) मैं उस पर आता हूं ।?(व्यवधान) देश के 500 टॉप कंपनीज रोजगार सृजन कर सकती हैं । इन 500 कंपनियों में पोर्टल के माध्यम से ऐप्लिकेशन लेकर एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा ।

हम स्किल के बारे में छोटी उम्र से सुनते आ रहे हैं कि जापान, कोरिया, चीन में स्किल इतनी ज्यादा है कि लोग घर में बैठ कर काम कर सकते है । वे मोबाइल बना लेते हैं, बाकी सब काम करते हैं और हर आदमी के पास

काम है, रोजगार है । यह सुनते-सुनते मैं 52 साल क्रॉस करके 53 वें साल में पहुंच गया हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी व निर्मला सीतामरण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । आपने ऐसा बजट पेश किया है, जिससे युवाओं को गारंटी के साथ रोजगार मिलने का अवसर आया है । मोदी जी की गारंटी की बात हो रही थी । मोदी जी की गारंटी है और अभी भी है । इस बजट में भी है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल्याण दा की बहुत श्रद्धा करता हूं । दादा मेरे से बड़े हैं । मैं जब लोक सभा में चुनकर आया था तब आपने बहुत प्यार से बंगला में बिप्लव बोला था । दादा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं । ? (व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैं अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हूं, एक छोटे से राज्य से, छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति हूं । आप मेरी बात भी सुना करो । अभी यहां सैलजा जी ने बोला था कि जो अंतिम व्यक्ति के बारे में सुने, मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूं । सैलजा जी मुझे संरक्षण दे दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में बड़ी मात्रा में कैम्पस सेलेक्शन होता है । अच्छे कॉलेजों में तो 100 परसेंट कैम्पस सेलेक्शन होता है, किन्तु किसी गांव में कॉलेज हो या छोटे जिले में हो, उसमें कैम्पस सेलेक्शन नहीं होता है । एक-दो परसेंटेज में होता है । युवा पढ़ने के बाद आशा करता है कि मुझे कुछ रोजगार मिलेगा । आप मानकर चलिये कि किसी कैम्पस से 30 परसेंट कैम्पस सेलेक्शन हो गया और बाकी 70 परसेंट लोग रह गए, इनके मन में इनफियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है । वे फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, ड्रग्स के शिकार होते हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने गरीब बच्चों के लिए बजट में प्रावधान रखा है कि यदि आपका कैम्पस सेलेक्शन नहीं भी हो, हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप-500 कंपनियां हैं, उनमें आपको इंटर्नशिप करने का 100 परसेंट मौका मोदी जी की गारंटी दे रहा है । ? (व्यवधान) उसमें पहले महीने 6000 रुपये और उसके बाद उनको एक साल तक पर-मंथ 5000 रुपये दिए जाएंगे । उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी । यदि उनमें क्वालिटी हो, तो उसी कंपनी में उनका चयन भी हो जाएगा । आज देश में जॉब की कमी है, ऐसा नहीं है । पारदर्शिता की कमी है, स्किल्स की कमी है । जिसके अंदर स्किल है, एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि वह आज इस कंपनी में है और कल उस कंपनी में चला जाता है । वह यहां छोड़ कर वहां चला जाता है, किन्तु गरीब बच्चा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसका कैम्पस सेलेक्शन नहीं होता है, आज नरेन्द्र भाई मोदी जी वहां खड़े हैं कि मैं गार्जियन हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं एससी के साथ हूं, मैं एसटी के साथ हूं, मैं दलित के साथ हूं । यह बजट वह दर्शाता है । लम्बे समय तक कांग्रेस का राज था, किंतु कांग्रेस ने कभी भी उस दृष्टि से युवाओं को देखा ही नहीं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में शिक्षा, रोज़गार और विकास के लिए 1.48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । यहाँ से आवाज़ उठ रही थी, कह रहे थे कि कोई व्यवस्था ही नहीं है । लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में प्रावधान किया गया है ।

महोदय, इस बजट में किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं । माननीय सैलजा जी किसानों की बात कह रही थी । मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बजट में किसानों के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए हैं और इसके अलावा, इसमें फर्टिलाइज़र के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं । वह राशि भी किसान के लिए दी जा रही है ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दस सालों में, वर्ष 2014 से 2023 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपए एमएसपी में दिये गये हैं । माननीय सैलजा जी हरियाणा के बारे में बात कर रही थीं, आपके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी दी जाती है ।

आपने एयरपोर्ट के बारे में कहा । हिसार में एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, आप वहाँ से हवाई जहाज पर चढ़ सकते हैं ।? (व्यवधान) आप मुझसे ज्यादा हरियाणा को जानती हैं क्योंकि आपने वहाँ जन्म लिया है । जब मैं दिल्ली में नया-नया आया था तब आप मंत्री थीं । आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपका आदर-सम्मान करता हूँ । आज आपने जिस तरह से निर्मला जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात की शुरुआत की, यह एक अलग ही गेस्चर है । मैं इसकी सराहना करता हूँ ।

महोदय, आज नरेन्द्रभाई मोदी जी का किसानों के प्रति काम करने का जो तरीका है, उसी के कारण आज भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में नम्बर वन पर है । यह कैसे हुआ? अगर किसानों के लिए काम नहीं हुआ तो यह कैसे हुआ? कांग्रेस के जमाने में यह नम्बर वन तो था नहीं । यह था क्या? ? (व्यवधान) मुझे डेटा दिखा दीजिए । मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि डेटा मांग लीजिए । वर्ष 2014 से पहले दुग्ध उत्पादन में देश की स्थिति क्या थी । आज यह दुग्ध उत्पादन में नम्बर वन है । मोटे अनाजों के उत्पादन में नम्बर वन है, चावल और गेहूँ के उत्पादन में नम्बर टू पर है । अगर मोदी जी ने किसानों के लिए काम नहीं किया, तो खेती में यह जो फलन है, वह कहाँ से आता है? वह पाकिस्तान से तो नहीं आता है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** बिप्लव जी, आप एक बात बताएं । बंगाल और बंगाल में महिला सदस्यों का क्या है? ये आपको बंगाल पर सबसे ज्यादा टोक रही हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** बंगाल वाले आपको सबसे ज्यादा क्यों टोक रहे हैं? आप इनको बंगाल में जवाब दे दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब **:** यह बात मुझे ज्यादा उत्साहित कर रही हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, शांत रहें ।

इनको बंगाल की भाषा में जवाब दे दीजिए ।

श्री बिप्लब कुमार देब **:** जवाब दे देंगे ।? (व्यवधान) दादा, मैं बंगाल में जाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हैं? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मां और बच्चे के साथ प्रधान मंत्री, ?प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना? को लेकर खड़े हो जाते हैं । ? (व्यवधान) बच्चे के जन्म के बाद मां और बच्चे के लिए ?उज्ज्वला योजना? के माध्यम से गैस चूल्हा फ्री में देते हैं । ? (व्यवधान) ?सूर्य घर योजना? के माध्यम से गरीब लोगों को बिजली फ्री मिलती है । ? (व्यवधान) ?प्रधान मंत्री आवास योजना? के माध्यम से घर फ्री मिलता है । ? (व्यवधान) ?प्रधान मंत्री शौचालय योजना? के माध्यम से शौचालय फ्री, तबियत खराब हो, तो ?आयुष्मान भारत योजना? के माध्यम से पांच लाख रुपए का हैल्थ इंश्योरेंस है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा हैल्थ इंश्योरेंस है, उसे श्री नरेन्द्र मोदी जी लेकर आए हैं । ? (व्यवधान)

घर से निकलना है, तो अटल जी ने ?प्रधानमंत्री सड़क योजना? की शुरूआत की थी, जिससे अब लोग अपने घर से निकलकर पक्के रास्तों पर चल सकते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, प्लीज, बैठे-बैठे टिप्पणी न करें ।

? (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब **:** अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ घर में पानी की व्यवस्था की गई है । ?जल जीवन मिशन? के माध्यम से हर घर में मुफ्त पानी पहुंचाने की व्यवस्था प्रधान मंत्री जी ने की । ? (व्यवधान) खाना बनाने के लिए घर में गैस चूल्हा होना चाहिए, मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है । यह अगले पांच सालों तक चलेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जन्म के समय भी मोदी जी हैं, खाना पकाते समय भी मोदी जी हैं, घर में रहने की व्यवस्था भी मोदी जी करते हैं, रास्ते पर चलने के लिए भी मोदी जी हैं, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस-वेज़ बनाने के लिए भी मोदी जी हैं । इसका परिणाम है कि आज देश की 25 करोड़ फैमलीज़ गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मध्यम वर्ग में पहुंच गई हैं । ? (व्यवधान) अब आप लोग नहीं चाहते हैं कि वे लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मध्यम वर्ग में पहुंचें, तो मैं क्या करूं? ? (व्यवधान)

सैलजा जी बोल रही थीं कि डीसी के लिए, एससी-1, 2 के लिए क्या किया गया है? जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, यह चीज उन लोगों को ही ज्यादा मिलती है । जब मैं त्रिपुरा में मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा था, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने एक और स्कीम भी लॉन्च की थी । जीवन भर के लिए तो सब स्कीम्ज हैं, घर भी है, मकान भी है, रास्ता भी है, बिजली भी है, पानी भी है, खाना भी है, चावल भी है, अनाज भी है, लेकिन त्रिपुरा में यदि किसी गरीब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार के लिए दो हजार रुपए मोदी जी के नेतृत्व में वहां की सरकार देती है । ? (व्यवधान) मृत्यु के बाद लोगों के परिजनों के लिए स्मृति का रास्ता मैंने बनाया, शमशान में अपने माता-पिता जी की स्मृति में पेड़-पौधे लगा दीजिए, वे पेड़-पौधे लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे । ? (व्यवधान) उससे राहुल गांधी जी को भी आक्सीजन मिलती है और हम लोगों को भी ऑक्सीजन मिलती है । ? (व्यवधान) मेरे मित्रों, यह कार्य भी मोदी जी ने ही किया है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सैलजा जी महिला हैं । हमारी माननीय वित्त मंत्री भी महिला हैं । ? (व्यवधान) श्रीमती इंदिरा गांधी महिला प्रधान मंत्री थीं । ? (व्यवधान) उसके बाद सोनिया जी यूपीए सरकार के दस सालों में, यूपीए की चेयरपर्सन थीं । ? (व्यवधान) मीसा जी यहां बैठी हुई थीं, अभी शायद नहीं हैं । ? (व्यवधान) अच्छा हैं? उधर बैठी हैं मेरी बहन । ? (व्यवधान) सोनिया जी 33 परसेंट रिजर्वेशन का बिल लाना चाहती थीं, आपकी पार्टी के लोगों ने उसे फाड़कर स्पीकर के सामने फेंक दिया था । ? (व्यवधान) दो-दो महिला, इंदिरा गांधी जी और सोनिया जी, इतनी प्रभावशाली होते हुए भी, यूपीए की चेयरपर्सन होने और चाहने के बावजूद भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं लाईं । ? (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं गर्व करता हूं, दोनों हाउस में महिला आरक्षण बिल लाने में सफल रहे और करके दिखाया । ? (व्यवधान) मेरे मित्रों, 2029 में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन से महिलाओं, बहनों को इसी हाउस में लाया जाएगा । ? (व्यवधान)

एसएचजी ग्रुप, आज 10 करोड़ बहनें एचएचजी ग्रुप्स में काम करती हैं ।? (व्यवधान) रोजगार करती हैं, वे स्वरोजगारी बनी हैं ।? (व्यवधान) ड्रोन दीदी, हम शहर के लोग ड्रोन चलाएंगे, इसके बारे में आइडिया नहीं था, आजकल गाँव में बैठी एसएचजी ग्रुप की महिला ड्रोन चलाती है । ? (व्यवधान) किसानों की फसलों की देखभाल कराती हैं ।? (व्यवधान) वह फर्टिलाइजर देने की व्यवस्था करता है ।? (व्यवधान) क्या कभी किसी गाँव में किसी महिला ने कभी सोचा था कि मैं ड्रोन चलाऊँगी? ? (व्यवधान) बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपया दिया गया है

।? (व्यवधान) मेरी बहनों आप ड्रोन नहीं चलाएंगी, आपको प्लेन दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए ।? (व्यवधान) मैं नॉर्थ-ईस्ट से आता हूँ, कांग्रेस के शासन में वहाँ मात्र 9 एयरपोर्ट थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नार्थ-ईस्ट में 16 एयरपोर्ट हैं । अभी हमारे रेलवे मंत्री जी यहाँ बैठे हुए थे, नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों में रेल कनेक्टिविटी लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं ।? (व्यवधान) कांग्रेस का लंबे समय तक शासन नॉर्थ-ईस्ट में रहा है । उस समय वहाँ करप्शन के ऊपर करप्शन, स्कैम के ऊपर स्कैम, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया । मैं यह सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ ।? (व्यवधान) इस बजट में 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान महिलाओं और उनसे संबंधित स्कीम्स के लिए रखा गया है ।? (व्यवधान) इसका मतलब है कि इस बजट में किसानों के लिए भी प्रावधान है, महिलाओं के लिए भी प्रावधान है, युवाओं के लिए भी प्रावधान है और हमारी आम जनता के लिए भी प्रावधान है ।

महोदय, यहाँ संविधान की बात उठी है । संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करनी पड़ती है । कांग्रेस ने 70 बार देश में धारा 356 लगाकर इस संविधान की हत्या की हुई है ।? (व्यवधान) दादा, आप बोलते हो ।? (व्यवधान) ममता दीदी ने भी कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा था, सीपीएम का साथ छोड़ा था ।? (व्यवधान) वह दीदी के साथ थी और इसीलिए दीदी ने छोड़ दिया और छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई । कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने, कम्युनिस्ट्स की सत्ता के समय दीदी का माथा फटा था और उस समय दीदी को 28-29 टांके लगे थे । कांग्रेस और कम्युनिस्ट्स, जो आज साथी हैं, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया था और दीदी को स्ट्रेचर पर एक रिक्शा वाला उठाकर लाया था ।? (व्यवधान) दादा, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ ।? (व्यवधान) आज आप उनके साथ बैठे हो ।? (व्यवधान) जिन्होंने दीदी का माथा फटाया, आप उनके साथ बैठे हो ।? (व्यवधान) दीदी देख रही हैं और इसीलिए दीदी ने बंगाल में कंप्रोमाइज नहीं किया ।? (व्यवधान) बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ समझौता नहीं किया और दादा आप इनके साथ बैठे हो ।? (व्यवधान) दादा, आप यहाँ बैठे हुए सुन्दर नहीं लगते हो, आप इधर बैठिए ।? (व्यवधान) कल्याण दादा, आपका नाम कल्याण है, कल्याण करो, आप इधर आओ और मोदी के साथ रहकर ही कल्याण कर सकते हो, वहाँ बैठकर कल्याण नहीं कर सकते हो, वहाँ एक परिवार, सिर्फ गाँधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपुरा से आता हूं और एक बार मिडल में त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस की सरकार आई थी । अपनी ही सरकार में राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने अपनी मित्रता रखने के लिए वहां सीपीएम को बैठाया । मेरी छोटी-सी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया और सीपीएम को वहां बैठा दिया ।? (व्यवधान) मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधान मंत्री रहे हैं । वे असम से राज्य सभा एमपी रहे । गोगोई जी सदन में बैठे हैं । असम से राज्य सभा एमपी रहने के बावजूद भी वे नार्थ-ईस्ट में एक बार भी नहीं गए और मैंने अपने क्षेत्र में तो उनकी फोटो भी नहीं देखी । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी अब तक नार्थ-ईस्ट में 90 बार जा चुके हैं और मंत्रिपरिषद में बैठे हुए लोगों ने 700 बार नार्थ-ईस्ट में प्रवास किया है । आज नार्थ-ईस्ट के राज्य 85 परसेंट ज्यादा कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट करते हैं ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, ये लोग संविधान की बात करते हैं । वर्ष 1975 में इमरजेंसी लगाने वाला कौन है? इमरजेंसी किसलिए लगाई थी? देश में इमरजेंसी तब लगती है, जब देश में आपातकाल होता है या देश में डिजास्टर होता है या कोई युद्ध होता है । वर्ष 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी, किस कारण से लगी, यह सभी जानते हैं । एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए भारत जैसे गणतांत्रिक देश में इमरजेंसी लगा दी गई और ये संविधान लेकर घूमते हैं ।? (व्यवधान) इस देश में एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी लगाई गई । देश में कोई युद्ध नहीं था, कहीं भीषण बाढ़ नहीं आई थी, कोई आपातकाल की स्थिति नहीं थी । ये लोग आज

संविधान की बात कर रहे हैं । बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने इलेक्शन में हराने का काम किया है । उन्हें हाउस में नहीं जाने दिया और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पंच तीर्थ बनाकर इन्हें जवाब दिया, जो हम सब के साथ है ।

अध्यक्ष जी, हमारे देश में जॉब की कमी नहीं है । हमारे देश में स्किल की कमी थी, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी नरेन्द्र भाई मोदी जी ने बनाई और राजीव प्रताप रूड़ी जी, मेरे मित्र यहां बैठे हुए थे, वे पहले मंत्री बने थे ।? (व्यवधान) जोशी जी, आप यह बात कह कर क्यों दुख देते हैं कि जनता ने हटाया । ये लोग तीन इलेक्शन मोदी जी के सामने हारे हैं । तीन चुनावों में इनकी संख्या मिलाकर भी 240 नहीं हुई । वहां बैठकर हमारे 400 की संख्या की बहुत चिंता करते हैं । ये हमारी पार्टी के लिए यह सोच रखते हैं कि 400 पार क्यों नहीं हुआ । इसके लिए मैं कहूंगा कि वर्ष 2047 तक एनडीए की ही सरकार रहेगी और 400 की संख्या पार करके जनता इन्हें जवाब देगी ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं त्रिपुरा का सीएम रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष **:** मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बैठे-बैठे यदि कोई व्यक्ति कुछ बोले तो उसका जवाब मत दो ।

श्री बिप्लब कुमार देब **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं जिस पार्टी से आता हूं, उस भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा जितना भी पॉलिटिकल करियर है, उसमें आठ साल मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एम.एल.ए. बनाया, मुख्य मंत्री बनाया ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप किसे स्पष्टीकरण दे रहे हैं?

आप इन्हें स्पष्टीकरण मत दीजिए । आप बजट पर बोलिए ।

श्री बिप्लब कुमार देब **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ-ईस्ट में लम्बे समय तक इन्सर्जेन्सी रही । चाहे वह बोडोलैंड समस्या का समाधान हो, नागालैंड में समस्या का समाधान हो, चाहे नॉर्थ-ईस्ट में आफ्स्पा को 60 प्रतिशत खत्म करने का प्रावधान हो, वह मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि मेरे राज्य त्रिपुरा में जो जनजाति है, वह वर्ष 1998 में मिज़ोरम से डिस्प्लेस्ड होकर त्रिपुरा में रिफ्यूजी जैसा 23 साल रही है । वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, केन्द्र में उनकी मिली-जुली सरकार रही । ये एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं और वहां 36,000 जनजातीय परिवारों को 23 सालों तक रिफ्यूजी जैसा रहना पड़ा । उन्हें पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, वोट देने का अधिकार तक नहीं था । उनके पास कुछ भी नहीं था । वे जनजातीय लोग हैं, एस.टी. हैं, गरीब हैं । इन्हें हक दिलाने का काम, स्थायी रूप से त्रिपुरा में रहने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इनके लिए 600-700 करोड़ रुपये का पैकेज देकर किया है ।

अध्यक्ष जी, यह कोई छोटी बात नहीं है कि अपने ही देश में कोई 23 सालों तक रिफ्यूजी बनकर रहे । उस समय केन्द्र की सरकार क्या कर रही थी? त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी । एक समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट्स की मिली-जुली सरकार थी, उनका सपोर्ट था । किन्तु, उन एस.टी. समाज, जनजातीय समाज के लिए काम नहीं किया गया ।

महोदय, त्रिपुरा में लम्बे समय तक इन्सर्जेन्सी रही । एन.एल.एफ.टी. को सरेन्डर करने का काम गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने करवाया । इसलिए चाहे नॉर्थ-ईस्ट की बात हो या पूरे देश की बात हो, माननीय प्रधान मंत्री जी ने हर क्षेत्र में पिछले दस सालों में काम किया है । इसका यह परिणाम है । मैंने शुरू में ही कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2 प्रतिशत बढ़ा है । यह ऐसे ही नहीं बढ़ा है । उन्होंने काम किया है, इसलिए यह बढ़ा है । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगले तीन सालों में हमारे देश की इकोनॉमी, जो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वह सबसे बड़ी इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर चली जाएगी ।

महोदय, इन्हें सरकार बचाने की इतनी चिंता है । शैलजा जी ने इस बजट को ?कुर्सी बचाओ बजट? कहा । इसका मतलब कि बिहार और आंध्र प्रदेश की जरूरत कांग्रेस को नहीं है । यह बजट सबके लिए है । जैसा कि मैंने बताया, इसमें लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपये शेयर सभी राज्य सरकारों को अलग-अलग स्कीम्स के माध्यम से जाएंगे । यह सिर्फ दो राज्यों में ही नहीं जाने वाला है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से निर्मला सीतारमण जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह एक सशक्त बजट है, युवाओं का बजट है, महिलाओं का बजट है, गरीबों का बजट है ।

महोदय, मनरेगा के बारे में बात हो रही थी । इस बजट में मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये बढ़ाये गये हैं । इसे जरा पढ़ कर देख लीजिए । इसे पूरा पढ़ लीजिए । चाहे देश का अन्तिम व्यक्ति हो, चाहे इस सदन में बैठे हुए हम सभी लोग हों, इस बजट में नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सबके लिए काम किया है ।

अध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में जो काम शुरू हुआ है और वर्ष 2047 तक एनडीए की सरकार रहते हुए देश को दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बनाएंगे । देश को एक नई ऊंचाई देने का काम जो रबिन्द्र नाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था । ? (व्यवधान) अभी दादा को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने टैगोर जी का नाम लिया है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य मीसा जी, आप भाषण दे देना, लेकिन आज आप बैठे-बैठे हुए टिप्पणी बहुत कर रही हैं और भाषण में अपना नाम नहीं देती हैं ।

? (व्यवधान)

श्रीमती मीसा भारती **(**पाटलिपुत्र**) :** सॉरी सर । ? (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य बिप्लब जी, आप उधर का जवाब नहीं देंगे, आप आसन की तरफ का जवाब देंगे ।

? (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब **:** महोदय, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक के नाते जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कुरीतियों को खत्म किया । ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह की शुरूआत कर के समाज सुधारक के नाते जाना जाता है । राजा राम मोहन को भी समाज

सुधारक के नाते जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सती दाह प्रथा को बंद करवाया था । इसी तरह से हमारे प्रधान मंत्री जी ने सिर्फ आर्थिक सुधार ही नहीं किए हैं, बल्कि समाज सुधारक के नाते भी काम किया है । उन्होंने भी तीन तलाक खत्म कर के सामाज को सुधार दिया है । इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिर्फ आर्थिक सुधार ही नहीं किए हैं, उन्होंने समाज सुधारक के नाते भी काम कर के इस देश के समाज को सुरक्षित रास्ता दिखाया है ।

महोदय, सैलजा दीदी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात की है । मैं बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से आज हम भारत के लोगों का स्वभाव बदला है । मैं भी जब छोटा था और जब बस से जाता था, तो बिस्किट खा कर उसका पैकेट बाहर ही फेंकता था, यही शिक्षा थी कि बाहर ही फेंको, बस में मत रखो । जबकि मैं आज देखता हूँ कि कोई बच्चा गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है, तो कुछ भी रास्ते पर नहीं फेंकता है । इस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वच्छ भारत की मानसिकता के कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिज़िटाइज़ेशन भी है, स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और नरेंद्र भाई मोदी जी इस काम को करते रहेंगे । इससे बड़ी मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है । स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना ही नहीं है, स्वच्छ भारत का मतलब करप्शन को खत्म करना भी है । नरेंद्र भाई मोदी जी ने करप्शन को खत्म कर के एक नया आयाम कायम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बजट का समर्थन करते हुए इतने बेहतरीन बजट के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । आप सबको भी धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री वीरेन्द्र सिंह जी ।

<u>14.48 hrs</u> (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

श्री वीरेन्द्र सिंह **(**चन्दौली**) :** माननीय सभापति जी, आज मैं सदन में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका विरोध करने के लिए इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी ने, जो संघीय ढांचा इस देश में बना था, सारे प्रदेशों में उनकी आबादी, उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबको बजट का आवंटन होता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसमें इस तरीके की विसंगतियां की हैं, जैसे लग रहा था कि यह सरकार बचाओ बजट है । इसमें पूरे देश में रहने वाले क्षेत्रीय प्रदेशों के तमाम लोगों के अधिकारों का भी हनन हुआ है ।

महोदय, हम यूपी से आते हैं । हमने एक बार भी माननीय वित्त मंत्री जी के मुँह से यूपी शब्द को नहीं सुना । लगता है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से रोका गया है, शायद उसी का खामियाज़ा हमारे उत्तर प्रदेश को भुगतने को मिल रहा है ।

वित्त मंत्री जी ने किसानों के बारे अपनी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है । जहां तक मेरा मानना है कि किसानों की आमदनी तब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक किसानों की स्थिति बदहाली से दूर नहीं हो पाएगी । उसके दो तरीके हैं । पहला तरीका यह है, जो खेती में होने वाली लागत है, उसको कम किया जाए और दूसरा तरीका यह है कि उसके उत्पादन को उचित मूल्य बाजार में मिले । खेती की लागत कैसे कम होगी, जब तक यह सरकार कृषि यंत्रों पर से जीएसटी नहीं हटाएगी, उपयोग में आने वाले खाद एवं दवाइयों पर 18 परसेंट जीएसटी ली जाती है, कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी लगाने का काम यह सरकार की है । इससे उनकी लागत में कमी आने की कोई उम्मीद उसके पास नहीं रह गई है ।

जहां तक किसानों को फसल बीमा का झुनझुना थमाया गया है, हम लोगों ने देखा है कि केवल उन संस्थाओं को लाभ पहुंचाने की नीयत से इस देश के टैक्स का करोड़ों-करोड़ रुपया उन कंपनियों को दिया जाता है, लेकिन जब किसान उसकी एवज में अपने फसल की बीमा का भुगतान के लिए उसके दरवाजे पर जाते हैं तो बीमा का सरलीकरण न होने के कारण तमाम उन कानूनों एवं पेचीदगियों में उसे फंसा दिया जाता है । मुझे यह विश्वास है कि भारत सरकार उनको बीमा करने के लिए शायद जितनी राशि देती है, उसका पाँच प्रतिशत भी वह उन किसानों को वापस नहीं करते हैं ।

महोदय, मैं किसान का बेटा हूं । मैं जानता हूं कि जवानों की भर्ती पूरे देश में नहीं हो रही है । गरीब, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले नौजवानों की यह इच्छा होती है कि वह सेना में भर्ती होकर, अन्य संस्थाओं में भर्ती होकर अपने सपने को पूरा करें । वे अपने देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते हैं । हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेता अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे । उस अग्निवीर योजन के बारे में, उसको खत्म करेंगे या उनके जीवन को हम सुरक्षित रखेंगे, इस बारे में एक भी शब्द माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के प्रावधान में नहीं बोला ।

महोदय, आप जानते हैं कि देश की सीमाओं पर देश की चौकीदारी करने के लिए हमारे देश के नौजवान जाते हैं, चाहे वे अग्निवीर हों, चाहे रेगुलर भर्ती का नौजवान हों, जो अपनी जान को हथेली पर लेकर बॉर्डर पर जाते हैं, उनको पूरा विश्वास होता है कि जो सरकार देश में है, वह हमारे पीछे खड़ी है । अगर मेरी जान को कुछ हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह सरकार हमारे परिवार, घर और बाल-बच्चों की रक्षा करेगी । लेकिन, दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे हुए तमाम लोगों को उनकी पीड़ा का अहसास नहीं है । वे अग्निवीर को टेम्परेरी भर्ती के रूप में लेते हैं । यहाँ तक की उनको शहीद का दर्जा भी देने के लिए आनाकानी करते हैं । इस सदन से मेरी माँग है कि यदि उन नौजवानों के प्रति पीड़ा है, किसानों और गरीब के बेटों के प्रति पीड़ा है तो उस भर्ती अभियान को जारी रखा जाए । यदि उनकी कुर्बानी देश के बार्डर की रक्षा के लिए होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए ।

रेलवे में दो कैटेगरीज़ हो गई हैं । एक ऐसी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में पैसे वाले और धनवान लोग यात्रा करते हैं । उसे बहुत अच्छे तरीके के संवारने का प्रयास यह सरकार करती है । गांव, गरीब, किसान के बच्चे और किसान जिस यात्री, सवारी गाड़ी से यात्रा करते हैं, उनकी बहुत बदहाल स्थिति है । न उनकी लैट्रिन-बाथरूम ठीक हैं, न वहां बैठने की ठीक जगह है, न रेलवे में सफाई होती है और न कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ ठीक ढंग से व्यवहार किया जाता है । मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूं । मैं पिछले दिनों अपने साथियों से मिलने के लिए मुंबई गया था । वहां के लोगों की एक मांग थी ।

मैं सदन के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि रेल मंत्री के पास बजट में व्यवस्था हो तो मुंबई से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था करें, ताकि वहां काम करने वाले हमारे तमाम साथी अपने घर ठीक तरीके से आ सकें । महोदय, हम लोगों के इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए समाजवादी विचार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में गरीब रथ गरीबों के लिए चली थी । उसमें जो व्यवस्था और सुविधा थी, वह एक अनुकरणीय व्यवस्था थी । हम चाहते हैं कि गरीब रथ जैसी गाड़ियां यदि हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा चलाई जाएं तो निश्चित रूप से हमारे किसान, गरीब और मजदूरों को लाभ होगा ।

महोदय, न्यायालयों में करीब पांच करोड़ मुकदमे लम्बित हैं । वहां गरीब सबसे ज्यादा परेशानी में जूझता है । बजट में इस तरीके का कोई प्रावधान सुनने को नहीं मिला कि मुकदमे को खत्म करने के लिए जिला न्यायालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, व्यवस्था और सुविधा होनी चाहिए । न्यायालय को दिशा-निर्देश होना चाहिए कि

उनके मुकदमों का नितारण ठीक ढंग से हो जाए, ताकि उनकी कमाई का बहुत बड़ा भाग जो मुकदमे की पैरवी करने में लग जाता है, वह बच सके ।

हम दिल्ली आते-जाते हैं तो देखते हैं कि यहां ट्रैफिक की बहुत समस्या है । जब तक सार्वजनिक ट्रैफिक प्रणाली में गाड़ियों का तंत्र सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तब तक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती । एक-एक आदमी गाड़ी से चलता है और पूरी सड़क पर गाड़ियों का जाम रहता है । सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक तरीके से की जाए । यदि सरकार के पास बजट में प्रावधान हो तो हमारे सड़क परिवहन मंत्री इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ।

15.00 hrs

मैं दैवीय आपदा से जुड़ी कुछ बातों को रखना चाहता हूं । आप सब क्षेत्रों से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं । आकाशीय बिजली गिरने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है । मैं सदन के माध्यम से यह बात उठाना चाहता हूं कि या तो हमारी साइंस प्रणाली को इतना डेवलप किया जाए ताकि पहले से अनुमान हो सके कि आकाशीय बिजली क्यों गिर रही है । आकाशीय बिजली गिरने से यदि किसी किसान की खेत में काम करते हुए या जानवर चराते हुए मृत्यु होती है तो जो उसको मुआवजा दिया जाता है, उसको दो गुना करने की बात इस बजट के माध्यम से की जानी चाहिए ।

स्वास्थ्य सेवाएं और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर गांव में सबसे जर्जर हो गया है । सुदूर गांवों में कोई ट्रॉमा सेंटर्स की व्यवस्था नहीं है । मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मैं गरीबों के लिए ही बात कर रहा हूं, इसके लिए मुझे थोड़ा संरक्षण चाहिए । मैं चाहता हूं कि सुदूर गांव में मुख्य मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर दूर कोई कस्बा या गांव है, ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां ट्रामा सेंटर उपलब्ध हो, सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध हो । हमारे चंदौली जनपद में बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां से अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज है, एक्सीडेंट का मरीज है, वहां से अगर वह मुख्यालय के ट्रामा सेंटर तक आता है तो उसकी जिन्दगी भगवान भरोसे बचती है या तो नहीं बचती है ।

हमारे यहां भाभा कैंसर संस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट एक रेफरल सेंटर बन कर रह गया है । वहां गरीबों के इलाज के लिए छह-छह महीने तक वेटिंग का सामना करना पड़ता है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डीजल-पेट्रोल को एक समान जीएसटी के दायरे में लाया जाए । हमने देखा है कि बार्डर के जो जिले हैं, उन जिलों से इसकी तस्करी होती है और तस्करी के कारण बहुत बड़े राजस्व की हानि होती है ।

खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन में जो कृषि उत्पाद हैं, उसके लिए स्टोर न होने के कारण जब फसल उनके खेतों में रहती है तो उसके दाम कम मिलते हैं, वही फसल बिचौलिये के जरिए जब अढ़तियों के स्टोर में चली जाती है तो यही प्याज की कीमत जहां 2 रुपये किलो भी मिलना मुश्किल होता है, वहीं आज 70-80 रुपये किलो प्याज मिल रहा है । यदि सरकार महंगाई कम करना चाहती है तो खाद्य पदार्थों के स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके ।

आज हमारे नौजवान बेरोजगार हैं । हम बड़े उद्योगों को संरक्षित करते हैं और उनको संरक्षण देते हैं । कृषि और खाद्य से जुड़ी हुई माइक्रो लैवल के जो कुटीर उद्योग हैं, उनको संरक्षित किया जाए और इसके लिए प्रतिबंधित

किया जाए कि वह खाद्य पदार्थ बड़े उद्योगपति न बनाने लगे । इससे स्पर्धा के वातावरण में छोटे लोगों के साथ अन्याय हो जाता है और वह अपना सामान नहीं बेच पाते हैं । मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुन: इस बजट का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं ।

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Hon. Chairman Sir and esteemed Members of this august House, today, I rise here to speak on the Union Budget that was presented by the hon. Finance Minister yesterday. If I am to describe this Budget in one line, I would say it is a Budget without any clarity or vision which has been rolled out to satisfy the coalition partners of the BJP rather than providing any substantial relief to the 140 crore people of this country. This Budget was planned by two individuals to keep another two in good faith neglecting the aspirations of 140 crore people. So, the gist is that it has been planned by two and executed for two. It is anti-people Budget crafted to bribe two political parties and buy time.

Sir, today, we stand at the precipice of a new era in Indian democracy. When PM Modi became the Prime Minister for the first time in 2014, everyone referred to the Government as Modi Government.

When Shri Modi was elected for the second term in 2019, everyone referred to the term as Modi 2.0. But on 4th June, 2024, the people of India decisively rejected the Modi-led BJP Government which reigned supreme almost for a decade.

What we now have in place is a creaky, shaky coalition. Yes, Sir, coalition. Coalition means cooperation. No one is referring this Government as Modi 3.0, not even the Union Finance Minister who presented the Budget yesterday, nor even the MPs of BJP, neither the Home Minister, nor the External Affairs Minister, nor the Defence Minister, nor the Panchayati Raj Minister, nor the Health Minister. Even the BJP leaders are not referring to this as Modi 3.0.

It is so uncertain and fragile that it can implode anytime. As I was saying, coalition means cooperation; coalition means collaboration; coalition means cohesion. But after yesterday, one thing is very clear that Coalition means appeasement and compensation. That is very clear from yesterday?s Budget. It is ironic that BJP which decried appeasement politics for the last ten years, is now ensnared in its tentacles of appeasement politics and trying to save its own chair. वक्त बदल गया है ।

This change is more than a paradigm shift in leadership. It is a clear rejection of authoritativeness; it is a rejection of arrogance, divisive politics and empty

promises. The message from the electorate of this country is loud and clear. वक्त बदल गया है ।

Today is exactly the 50th day since this rejection. But PM Modi refuses to accept this reality. He is running a coalition Government and he wants everyone to believe that ?सब चंगा सी; all is well.? So, the Defence Minister is the same person; the Commerce Minister is the same person; the Home Minister is the same person; the External Affairs Minister is the same person; the Finance Minister is also the same person.

Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the Budget was being presented. Only the cheerleaders have gone done in number. बैंच बजाने वालों का नम्बर थोडा कम हो गया है । The number of cheerleaders has gone down. It is because the people of this country denied them access to this temple of democracy. It is a big change.

Amidst all the failures in the last decade, the PM and his Government have achieved something, which is truly remarkable ? a world class collection of abbreviations. With more than 110 acronyms or abbreviations up their sleeves, every new initiative feels like almost a linguistic surprise. Sir, who needs plain names when you have a whole vocabulary of letters to decipher? There are 110 names. Just imagine!

Why am I talking about abbreviations or acronyms? It is because I want to reply to this Government in a language which they understand. There is ART which means Accountability, Responsibility, Transparency. There is HRIDAY which means Heritage City Development and Augmentation Yojana. There is UDAN which means Ude Desh ka Aam Nagarik. There is GOBAR which means Galvanising Organic Bio-Agro Resources. They have thrown every absurd acronym possible at the people of this country. There are 110 names! As I said, I want to reply to this Government in a language which this Government and the Union Ministers especially the Union Finance Minister understand.

So, take for instance the Budget ? B.U.D.G.E.T. It is a word with six letters. I will explain all six letters in detail. Let me start with ?B? ? ?B? for betrayal. BJP promised *acche din*. ? (*Interruptions*) BJP promised *acche din* before coming to power in 2014. ? (*Interruptions*) What have they done? They have betrayed the citizens. They have betrayed the housewives. They have betrayed the daily-wage earners and the farmers. ? (*Interruptions*) आप सुनने की हिम्मत रखिए ।?(व्यवधान)

As far as price rise is concerned, a home-cooked veg-thali costs eight percent more year on year in April 2024. The price of onions goes up by 43 per cent. The price of tomatoes goes up by 41 per cent. The price of potatoes goes up by 39 per cent. ? (*Interruptions*) सर, एक-एक करके सदस्यों को बोलने की इज़ाजत है । Sir, I have a lot of patience. So, these things will not distract me. You can just ask them to have patience and listen to what I say and then the Minister can reply. ? (*Interruptions*) He is not going to become the Minister. This is not going to score brownie points. ? (*Interruptions*)

Sir, BJP promised *acche din* before coming to power in 2014. Sir, what have they done? They have betrayed the citizens. They have betrayed the housewives. They have betrayed the daily-wage earners. They have betrayed the farmers.

As far as price rise is concerned, a home-cooked veg-thali costs eight percent more year on year in April 2024. The price of onion goes up by 43 per cent. The price of tomatoes goes up by 41 per cent. The price of potatoes goes up by 39 per cent. ? (*Interruptions*) The price of LPG cylinder crossed Rs. 1,100 in 2023. The household savings plummeted to a 50-year low in 2023 with household debt reaching a record high of 39.1 per cent of GDP in 2024.

Sir, in the case of earnings, 63 crore people earned less than Rs. 308 per day and 18 crore people earned less than Rs. 180 per day. If the NDA Government in the last ten years had spent even a quarter of time, which it dedicated to political witch-hunting and spreading communal hatred, on addressing the real issues of interest for the people, India would not be ranked 111th out of 125 countries in the Global Hunger Index. ? (*Interruptions*) These people sitting here in the Treasury Benches need to know that they have betrayed the marginalised communities. They spoke about ?*Sabka Saath, Sabka Vikas?* which turned into ?*jo humare saath, hum unke saath?* as admitted by BJP MLA and the Leader of the Opposition in the Bengal Assembly and proved right by the failed Finance Minister of this failed Government yesterday.? (*Interruptions*)

As far as crime against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is concerned, it has increased by 13 per cent and 14 per cent respectively from 2021 to 2023. They speak about a double-engine Government in Uttar Pradesh. They are trying to defame Bengal. But let me give you a data which was given by the Ministry of Social Justice and Empowerment last year and which was given by the Minister himself.

It proves that Uttar Pradesh has the highest number of cases of atrocities against Dalits, followed by Rajasthan. Sir, who is in power in Uttar Pradesh and Rajasthan? Can these two, who are shouting at the top of their voices, answer? ? (*Interruptions*) Who is the Chief Minister of Uttar Pradesh? ? (*Interruptions*) Who is the Chief Minister of Rajasthan? ? (*Interruptions*)

After the ?Mangalsutra? and ?Mujra? vilification episodes, the Government of Uttar Pradesh and Uttarakhand, in their infinite wisdom, have mandated that eateries along the Kanwar Yatra route display the names of owners and staff members. ? (*Interruptions*) It is a move clearly intended to instigate hate speeches and hate crimes targeting the minority community. We commend and thank the hon. Supreme Court for swiftly intervening with a stay order against all these discriminatory directives.

Sir, talking about the vacancies in tribal schools, about 10,000 vacancies in Eklavvya Model Residential Schools remain unfilled as of today.

Sir, now I come to religious representation. Religion belongs to an individual, whereas a festival is for everyone. The hon. Chief Minister of West Bengal has said: ?Dharma Jar Jar, Utsav Sobar.? ? (*Interruptions*)

Sir, BJP does not have a single Muslim MP. ? (*Interruptions*) Sir, please listen to this. ? (*Interruptions*) The whole country needs to know that BJP does not have a single Muslim MP in Lok Sabha, Rajya Sabha or any

State Assembly. ? (*Interruptions*) Diversity is not about the colours in our Flag; it is about the people in our Parliament. ? (*Interruptions*)

Sir, the absence of diversity in Parliament has tangible consequences in the past. It led to policies that overlook the needs of marginalised communities, legislation that failed to address systematic injustices, and a governance structure that perpetuated inequality rather than fostering unity. The marginalised across the country have spoken with a strong voice this time and unequivocally rejected a Government that has betrayed their aspirations and rights.

Sir, now I come to ?U?. बजट के बी पर बोला ?बिट्रेअल?, अब मैं यू पर आता हूं । ? (व्यवधान)

Sir, ?U? stands for Unemployment. ? (*Interruptions*) The unemployment rate in our country rose to an eight-month high of 9.2 per cent in June 2024. ? (*Interruptions*) Talking about youth unemployment? (*Interruptions*) मोदी जी की तीसरी बार, युवा अभी भी बेरोजगार । ? (व्यवधान) When we speak about youth unemployment, look what

unemployment has done to this country. ? (*Interruptions*) This is the perfect example. They have gone mad. ? (*Interruptions*) This is what unemployment has done. ? (*Interruptions*) मोदी जी की तीसरी बार, युवा अभी भी बेरोजगार । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, एक मिनट सुनिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, जैसे आप यहां चुनकर आए हैं, वैसे ये लोग भी यहां चुनकर आए हैं । Please respect each other. आप थोड़ा अपनी भाषा का ध्यान रखें ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** प्लीज, आप लोग बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Abhijeet ji, please continue.

? (*Interruptions*)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** मोदी जी की तीसरी बार, युवा अभी भी बेरोजगार । ? (व्यवधान)

Sir, among graduates, unemployment was 13 per cent in 2022-23. Among postgraduates and above, it was 12.1 per cent in 2022-23. The Skill India Mission aimed to train 400 million people by 2022, but only 14 million received training by 2024. The target still remains a distant dream. The hon. Finance Minister announced Rs. 2 lakh crore package for five schemes on jobs and skilling of 4,10,00,000 youth. BJP had previously promised two crore jobs a year. They are nowhere close to meeting the target, and now they are setting unrealistic targets. ? (*Interruptions*) These young people do not want to listen to Budget Speeches. The young people of this country, the young India, does not want to listen to your rhetoric, does not want to listen to your empty promises, does not want to listen to your 90-minute long Budget Speeches.

Now, I come to women unemployment. Unemployment rate for women living in urban India is 22.7 per cent. They speak of ?*Beti Bachao, Beti Padao?,* but they forget to mention about *beti ko naukri dilao.* On the other hand, you see what is happening in West Bengal. *Kanyashree Scholarship Scheme* touched the lives of 85 lakh girls, and won the UN Public Service Award. This award was not handed over by any Tom, Dick or Harry. ….*(Interruptions)* It was the UN Public Service Award. Over 2,20,00,000 women have been financially empowered through schemes like

Lakshmir Bhandar. Financial assistance of Rs.12,000 annually for general category, and Rs.14,400 for women of SC/ST categories has been provided. Many other States are also rolling out similar schemes. I appeal to the hon. Finance Minister, and I humbly urge the Government to set aside arrogance, and embrace willingness to learn from successful practices integrating them into their approach. Only three States in the country have enterprises where women own more than three out of 10 establishments, and these three States are Telangana, West Bengal and Karnataka. It is not coincidental that all three States are governed by the non-BJP political parties. ….*(Interruptions)* And, I have no qualms or hesitation in saying that BJP and women empowerment simply do not align and are rather paradoxical.

Sir, now I come to ?D? which stands for ?deprive? like the hon. Member has deprived his …* Sir, ?D? stands for ?deprive?. You spend Rs.20,000 crore on revamping Central Vista. ….*(Interruptions)* You did this to improve the homes of the rich, influential and powerful. ….*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Abhishek ji, please sit down.

….*(Interruptions)*

SHRI ABHISHEK BANERJEE: What have you done for the homeless in the cities, in the towns, in the villages? ….*(Interruptions)*

माननीय सभापति**:** अभिषेक जी, प्लीज मेरी बात सुनिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, जो इस सदन का मेंबर नहीं है, आप उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं । इसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए ।

….*(Interruptions)?* ***

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, he is speaking about Mamta Banerjee. ….*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please do not mention the name of a person who is not a Member of this House.

….*(Interruptions)*

15.23 hrs

At this stage, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Sushri Mahua Moitra came and stood on the floor near the Table.

HON. CHAIRPERSON: Saumitra Khan ji, please go back to your seat.

....(Interruptions)

माननीय सभापति **:** आप लोग भी बैठ जाइए । मैं भी आसन से खड़ा हो गया हूं ।

? (व्यवधान)

<u>15.23½ hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

<u>15.24 hrs</u>

At this stage, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar and Sushri Mahua Moitra went back to their seats.

-

माननीय अध्यक्ष **:** कल्याण जी, प्लीज बैठ जाइए । आपकी पार्टी के एक सदस्य बोल रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभापति महोदय ने बोला है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है ।?(व्यवधान) सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए । ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप भी बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य न हो, उसके बारे में टिप्पणी न करें । सभी लोग इसका पालन करने का प्रयास करें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने सबको बोल दिया है ।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **(श्रीरामपुर) :** आप सिर्फ हम लोगों को बोलते हैं । जब बीजेपी के लोग इंटर्विन करते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं । क्यों?...(व्यवधान) You did not stop them. ....*(Interruptions)* Why this discrimination? ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष **:** क्या आप अपने सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते हैं? आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अभिषेक जी, एक मिनट के लिए रुकिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** क्या आप मुझे डायरेक्शन देंगी?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** ऐसे मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, मेज मत थपथपाइए । जब आपको बोल दिया है कि बैठना है तो बैठना है ।

? (व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर, मैं एक चीज़ स्पष्ट करता हूं । ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा । मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर इस सदन की सदस्य नहीं हैं । उन्होंने टिप्पणी क्यों की? आप अपने पद का मान रखिए । उनको बोलिए कि उठकर माफी मांगे । Then, I will continue my speech. ? (*Interruptions*) No, Sir. You have to intervene. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है ।

? (व्यवधान) *

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, you are the Speaker of this House. ? (*Interruptions*) No, Sir.

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट, प्लीज बैठिए ।

? (व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर, मैं विनम्र रूप से आग्रह करता हूं कि आप उनको बोलिए । आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन की गरिमा के लिए आप उनको बोलिए कि वह उठकर माफी मांगें । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आपको कंटीन्यू करना है तो कीजिए । उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है । अगर आपको कंटीन्यू नहीं करना है तो डायरेक्शन मत दीजिए कि वे माफी मांगें । आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं । मैंने उनका नाम निकाल दिया है । सदन में ऐसा कई बार हुआ है, पहले भी निकाला गया है ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, ?D? stands for deprived. You spent Rs. 2,000 crore on revamping Central Vista. You did this to improve the homes of the rich, influential and powerful. What have you done for the homeless in the cities, towns and villages? Why have you deprived the homeless across India and Bengal? You are not only visionless and shameless ? (*Interruptions*) You are not ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट, प्लीज ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, he is not even listening to you.

माननीय अध्यक्ष **:** आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नहीं, सब निकाल देंगे ।

? (व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर, ये तो आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं । Now, I come to the issue of depriving the rural poor. मोदी जी का तीसरी बार, गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार । Sir, over the past decade, the BJP-led Central Government has made its Bangla-*virodhi* stand abundantly clear by deliberately depriving people and abusing power to suppress Bengal?s voice. They have made an array of hollow promises, disrespected Bengal?s culture and hatched continuous conspiracies to tarnish the State?s image. Failing to fight us politically, you declared an all-out war on our rural poor, depriving them of *roti, kapda* and *makaan.*

Sir, hon. Finance Minister gave a statement today in the Rajya Sabha, saying that Bengal has failed to implement the scheme that Centre has aided in the last ten years. Sir, I challenge the hon. Finance Minister if she can release the White Paper of how many dimes, pennies or rupees the Central Government has given to

Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal Legislative Assembly elections in 2021. Sir, in the last three years, let me put this on record, मैं कुछ बोलूंगा, वह सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे, वह सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन कागज तो झूठ नहीं कहता है । मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपने वर्ष 2021 में बंगाल में हारने के बाद मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया? आवास योजना में वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने वाइट पेपर रिलीज करके साबित कर दिया कि दस पैसा दिया है । ? (व्यवधान)

सर, देखिए मैं वाइट पेपर मांग रहा हूं, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं । अरे भईया, वाइट पेपर दे दीजिए, कहानी खत्म । हम वाइट पेपर मांग रहे हैं, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं । इनके पास कागज नहीं हैं, लेकिन सीएए के नाम पर पूरे देश से कागज मांग रहे हैं । यह बीजेपी हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में मत टोकिए ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, MGNREGS funds to the tune of Rs. 6,913 crore have been forcefully withheld denying wages to more than 59 lakh workers over the past three years. Around 11,36,000 eligible families have been deprived of a roof over their heads as Rs. 8,140 crore under the PM Awas Yojana have been deliberately halted. The Government withheld the release of Rs. 800 crore under the National Health Mission due to non-compliance and certain colour branding guidelines for health and wellness centres despite other conditions being duly met. Despite 334 Central and NLM teams visiting West Bengal in the last three years and ATRs being submitted on time by the departments concerned of the State Government against every observation that was made by the Centre, still no funds have been released. Official interactions with the hon. Prime Minister and the other BJP Ministers of the Department concerned were met with dismissive attitude and constant rejection. Our leaders fighting for the people of West Bengal were even detained in Delhi by Delhi Police. Even women MPs were manhandled and dragged by their hair. And this BJP talks about *naari shakti*.

The Finance Minister yesterday in her speech proposed flood control initiatives for States like Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Sikkim, and Uttarakhand. Unsurprisingly, West Bengal was once again left out in spite of northern part of West Bengal being one of the worst flood affected areas and despite the fact that six out of eight MPs from PCs that fall under the northern part of West Bengal are from BJP. This is the kind of discrimination meted out to our State. I hope people of Jalpaiguri and Alipurduar are watching this and listening to what I am saying.

As long as we stand as people?s representative, the rights of West Bengal?s people cannot be taken away. The State Government of West Bengal has already cleared the pending wages of 59 lakh MGNREGS workers from its own treasury. It has also been decided that the first instalment of funds for the construction of houses shall be released by 31st December, 2024, which is by the end of this year. In 2022 and 2023 under the Pathashree Scheme, 26,486 kilometres of rural roads were constructed and repaired with a financial outlay of Rs. 6,448 crore.

As regards depriving women, ?वंचित हो रही देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी ।? You have 240 MPs in Parliament. If you had implemented the one-third quota as per the Women?s Reservation Bill, the BJP would have had 80-woman MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13 per cent of their total strength. Compare this to the Trinamool Congress Party, which boasts not one per cent, five per cent, 10 per cent, 13 per cent, 15 per cent, 20 per cent, 25 per cent but it has 38 per cent women MPs in Lok Sabha. Last year, a Special Session was convened to pass the Women?s Reservation Bill. Yet, the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there is a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That is the difference.

Sir, this Government is depriving the students. ?तीसरी बार मोदी सरकार, खो गया है शिक्षा का अधिकार । The inability to conduct NEET is one of the biggest failures of this Government, jeopardising the future of almost 33 lakh bright students. We, all of us, in the Opposition demanded a discussion on this in Parliament but there is hardly a word from the hon. Prime Minister on this issue. Our CM wrote to the PM for scrapping NEET in favour of reverting to a system where the State Government conducts its own medical tests. More than 12,000 vacancies in Kendriya Vidyalayas nationwide are yet to be filled in. There are more than 7,50,000 vacancies for teaching posts nationwide from Class I to Class VIII. There are more than 1,20,000 vacancies for teaching posts in UP alone from Class I to Class VIII. Students account for eight per cent of the total number of suicide victims.

Lives of more than, 13,000 students are lost every year because of suicides. ?(*Interruptions*) Depriving the working class ? (*Interruptions*) ?मजदूर की जेब हो रही है खाली, बताओ कब यह हालत है सुधरने वाली ।?

The ILO data reveals that the growth rate of real wages between 2006 and 2013 was six per cent. So, the data suggests that the growth rate of real wages from 2006 to 2013 was at six per cent and between 2014 to 2021 it is down to 1.4 per

cent. The Indian Railways made a bold proclamation about upgrading 40,000 conventional coaches to Vande Bharat standards turning a blind eye to the genuine struggle faced by everyday travellers and neglecting the fact that almost 96 per cent of passengers perform their journey in general and non-AC coaches. They continue to endure grave risks and vulnerabilities compounded by this Government's sheer ineptitude.

Now, I come to ?G?, G for Guarantee. ? (*Interruptions*)

SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): It is G for Ghotala. ? (*Interruptions*)

श्री अभिषेक बनर्जी : सर, देखिए ये खुद बोल रहे हैं कि सरकार का घोटाला है ।? (व्यवधान) Thank you. ? (*Interruptions*) I will take it actively. ? (*Interruptions*) It is very good. ? (*Interruptions*) G for Guarantee, G for Ghotala. NEET Ghotala and a guarantee with zero warranty. ? (*Interruptions*)

PM announced demonetization and guaranteed that black money would be wiped out. He failed in it ? (*Interruptions*) आप कितना सेल्फ गोल देंगे?? (व्यवधान) देते रहिए, आप को ही डांट पड़ेगी ।? (व्यवधान) Why I say guarantee with zero warranty? It is because PM announced demonetization and he said that black money will be wiped down. This Government failed in it as 99 per cent of the black money came back into circulation and is in the system now.

He guaranteed that terrorism would be curbed; again he failed in it. There have been 26 terror attacks in Jammu and Kashmir in the last six months. He guaranteed to create 25 crore jobs in 2014 and he failed to do it. In 2023, the Government admitted that in the last 10 years only one crore jobs were created. He guaranteed that everyone will have a house. The Prime Minister himself said that every Indian will have a roof over their head and everyone will have a house by 2022. The Finance Minister proposed the construction of an additional three crore houses under the PM Awas Yojana. Yet, no mention has been made of 11,36,000 houses in West Bengal that are still awaiting the Central funds. Now, the same money is being allocated to purchase aircraft worth Rs. 8,000 crore and construct palatial buildings as a part of Central Vista project worth Rs. 20,000 crore, and the poor people of this country still endure homelessness and still remain without a roof over their heads. It is another failed promise.

They guaranteed employment to the rural poor under MGNREGA, but failed to do so. As I said, not a penny has been allocated for West Bengal in the last three financial years following BJP's embarrassing defeat in the 2021 Assembly elections.

They guaranteed to turn bullet trains into a reality by 2022, but failed again. Now, the deadline has been conveniently shifted and postponed to 2026. One kilometre of bullet train costs Rs. 200 crore whereas one kilometre of Dedicated Freight Corridors (DFCs) on the other hand costs Rs. 25 crore.

Railway accidents today have become the order of the day, but the Union Budget presented yesterday makes no mention of rail safety or installation of anti-collision devices or Kavach in the passenger trains. They had guaranteed to double farmers income by 2022, but it failed. The actual growth staggers at three per cent and at this rate, the farmers can expect their incomes to be doubled by 2035 or 2040.

Over one lakh persons involved in farming sector tragically took their lives between 2014 and 2022. Around 30 suicides happen every single day. They guaranteed that no home would be without electricity or water by 2022. They failed again. They guaranteed to end terrorism, they failed again. More than 50 soldiers died in Jammu and Kashmir terrorist attack in the last 32 months. More than 50 soldiers died in J&K terrorist attacks in 32 months. From 2018-2022, Jammu & Kashmir had seen 761 terrorist incidents leading to 174 civilian casualties. You make all the big promises, but you fail to keep them. You give all the guarantees but those guarantees come with zero warranty. Under this budget, one thing is clear. The only thing that is growing faster than price rise and inflation is the BJP's list of broken promises and guarantees. So, we have ?B? for Betrayal, ?U? for Unemployment, ?D? for Deprive, and ?G? for Guarantee. सर, मैंने कहा है कि यह एक्रोनिम्स की सरकार है, तो मैं एक्रोनिम्स में ही जवाब दूंगा । बजट का ?बी? था, बिट्रेयल, ?यू? था अनइम्प्लॉयमेंट, ?डी? था डेपराइव, ?जी? था गारंटी । अब मैं ?ई? पर आता हूं । Sir, ?E? for Eccentric. Modi j's ... has turned governance into a ..., costing the nation dearly. His obsession with grandstanding has only distracted the countrymen from the real issues, leaving India to pay the price for his dictatorial displays. He announced unplanned lockdown. The Government's abrupt announcement of the national lockdown in March 2020 left citizens with only four hours to prepare, triggering widespread chaos and hardship. The unplanned and poorly implemented lockdown resulted in the tragic deaths of over 8,700 people, primarily migrant workers, on our railway tracks and roads.

Now, I will talk about the Farm Bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed three contentious farm Bills without any consultation with the farmers or farmers? organisation or any Opposition parties.

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, इस रिकॉर्ड को क्लियर कर लें । इस सदन में किसान विधेयक पर साढ़े पांच घंटे चर्चा हुई थी ।

?(व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई है ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** किसान बिल पर ??

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** जब स्पीकर बोलता है, तो बोलता है और वह सही बोलता है । आप अपनी जानकारी करेक्ट करें ।

?(व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर, बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई है ।?(व्यवधान) इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो मैं बताऊं ।?(व्यवधान) आपने सदन को यह याद दिलाया ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल सकता ।

?(व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** किसान विधेयक पर साढ़े? ।

?(व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर, एक मिनट । इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं । 700 किसान मारे गए हैं । उनको मौत के घाट उतारा गया है । सर एक आदमी ने एक मिनट भी उनको श्रद्धांजलि दी??(व्यवधान) ये आज ताली बजा रहे हैं । इसीलिए इनका ऐसा हाल है ।?(व्यवधान) सर, 700 लोग मारे गए हैं ।?(व्यवधान) क्या? ?(व्यवधान) 700 farmers died! 700 farmers died! What did you do? ? (*Interruptions*) You people have blood on your hands! You people have blood on your hands! ?(*Interruptions*) In 2020, these contentious Farm Bills were passed without any consultation with the Opposition parties or farmers? organisations. These Bills sparked massive protests. मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं । ये जो बोल रहे हैं, मैं बीजेपी से यहां पर जो सवाल पूछ रहा हूं, मिनिस्टर को जवाब देना है, अगर इनमें से कोई भी जवाब देना चाहता है, तो मीडिया चैनल चूज कर ले और मुझे टाइम बता दे । मैं आ जाऊंगा, एक-एक हाथ लड़ लूंगा ।?(व्यवधान) सर, मैं कह रहा हूं ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो । आप अपनी बात कहिए ।

?(व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** अगर इनके सीने में दम है और अगर हिम्मत है, तो ये सेट कर लें ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, आप चुनौती मत दीजिए । आप अपनी बात कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: I am challenging them to come and debate with me. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप इनको सदन में चुनौती मत दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, यह चुनौती बाहर दीजिए, सदन में चुनौती नहीं दीजिए ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बाहर चुनौती देना**,** यहां सदन में नहीं ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the Capital. ? (*Interruptions*) This reveals the true face of this fascist Government. ? (*Interruptions*)

Now, I will come to demonetisation. In November 2016, the Union Government demonetised Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes ? (*Interruptions*), You do not know that demonetization was done in 2016 ? (*Interruptions*) Sir, this Government demonetised Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes. ? (*Interruptions*) सर**,** ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं पढ़ कर बोल रहा हूं । पीएम टेलीप्रॉम्पटर से बोलते हैं । ? (व्यवधान) सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्पटर से बोलते हैं । ? (व्यवधान) सर, डेटा तो मैं पढ़ कर ही बोलूंगा । ? (व्यवधान) आप अपने नेता को जाकर ज्ञान दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सदन के नेता के बारे में चर्चा मत कीजिए । आप अपनी बात कहिये ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, demonetization was brought to combat black money. ? (*Interruptions*) It was brought to combat corruption. ? (*Interruptions*) It was brought to combat terrorism. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने हटा दिया है । मैंने उनको टोक दिया है ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. ? (*Interruptions*) Despite promises to eliminate black money, over 99 per cent of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of the initiative. ? (*Interruptions*) Shockingly, counterfeit notes increased by 10.7 per cent in 2022 with fake Rs. 500 notes rising by 101.93 per cent and Rs. 2,000 notes by 54 per cent.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य**,** वर्ष 2016 के बाद तो वर्ष 2019 के चुनाव हो गए ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. ? (*Interruptions*) That is why we say ?E? for `Eccentric?.

Now, I come to the last letter. ? (*Interruptions*) Sir, `T? for Tragedy. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य**,** आप वर्तमान बजट पर बोलिये । वर्ष 2016 के बाद तो वर्ष 2019 के चुनाव हो गए ।

? (व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर**,** कोई 60 साल पहले जवाहर लाल नेहरू की बात करेगा**,** दूसरे नेताओं की बात करेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** सब बोलते हैं ।

? (व्यवधान)

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर**,** मैं पाँच साल पहले की डीमोनेटाइजेशन की बात बोलूंगा तो आप कहेंगे कि वर्तमान इश्यु पर बोलिये । सर**,** यह पक्षपात नहीं चलेगा ।**?** (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बजट पर बोलिये ।

श्री अभिषेक बनर्जी **:** सर**,** मैं बजट पर ही बोल रहा हूं । जब बिप्लब देब बोल रहे थे तब 100 साल पुरानी बात कर रहे थे । वह 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात कर रहे थे तब आप चुप थे । अब मैं डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आपको चुभ रहा है । **?** (व्यवधान) सर, वाह! ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य**,** आप अपनी बात कहिये ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, `T? for Tragedy. ? (*Interruptions*) and this is the tragedy. ? (*Interruptions*) The example you all set in the House, that is why I said, `T?

for Tragedy. ? (*Interruptions*). When the Kolkata flyover collapsed a few years ago, Modi Ji jested that it was not an act of God. He said, ?It is an act of fraud.? ? (*Interruptions*) Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or an act of fraud? ? (*Interruptions*) Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur, and Gujarat airports collapsed. ? (*Interruptions*) Was it an act of God or act of fraud? ? (*Interruptions*) Sir, what happened when the Ayodhya Ram Temple roof started leaking after first rain? Was it an act of God or an act of fraud? ? (*Interruptions*) Sir, when Mumbai?s Atal Setu started developing cracks within six months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? ? (*Interruptions*) When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi Tunnel was caved in, was it an act of God or an act of fraud? ? (*Interruptions*) When 20 people killed as girder launcher collapsed on Samruddhi Expressway in Thane, what was it? Was it an act of God or an act of fraud? ? (*Interruptions*) When 300 lives were lost in Balasore train accident last year, what was it? Was it an act of God or an act of fraud? When nine people were killed and 40 people were injured as a goods train rammed with Kanchanjunga Express last month, what was it? Was it an act of God or an act of fraud? The Railway Minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. There have been 244 train accidents between 2017 and 2022. There have been 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50 per cent of compulsory track safety inspections were not even completed. ? (*Interruptions*) Only Rs.672 crore was spent out of the needed Rs.58,459 crore on track renewal. The Rashtriya Rail Sanraksha Kosh which would have received Rs.20,000 crore every year, received only Rs.4,225 crore. There is a staggering shortfall of Rs.15,775 crore.

Manipur is burning over the last almost one-and-a-half years. There have been more than 200 killings, 70,000 displacements and wrecking of 1000 homes. ? (*Interruptions*) There is no mention of the word Manipur in the Union Budget. ? (*Interruptions*)

Another tragedy of this Government has been the weaponisation of the Central agencies to carry out politically motivated witch-hunts against the Opposition leaders like many of us including me. They did not stop at me or my wife or my elderly parents or my PA or my advocate, but even my 11-year-old daughter and four-year-old son were not spared. ? (*Interruptions*) The BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see by letting the ED and the CBI go after me. ? (*Interruptions*) What did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है ।? (व्यवधान) The people of West Bengal and the

people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes setting an example for Shri Narendra Modi, Shri Amit Shah and the millions of BJP members and the rest of the country to see that this is the people?s power. ? (*Interruptions*) If I have to bow, I will bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. People need to understand this.

India?s national debt today stands at staggering Rs.169 lakh crore. The Finance Minister needs to know this. ? (*Interruptions*) Before you ridicule West Bengal for a debt of Rs.6 lakh crore, the budget predominantly, as I said, is anti-Bengal and anti-people even though the State elected 12 BJP MPs as compared to three in Andhra Pradesh. You still have the guts and gall to overlook West Bengal. You will get a befitting reply again. Perhaps, the Central Government would have benefited drawing inspiration from West Bengal Budget for the year 2024-25. Our Budget stood out for its inclusive approach introducing new schemes while enhancing the incentives of the existing ones. It comprehensively addressed the needs of every section of the society ensuring support for women, youth, students, fishermen and artisans alike. By prioritising equitable growth and social welfare, it has set a commendable example of governance focussed on holistic development of the people.

I have explained to the august House, including the Finance Minister who is sadly not present in the House, ?BUDGET?. I repeat again: ?B? for Betrayal, ?U? for Unemployment, ?D? for Deprived, ?G? for *Ghotala* and guarantee, ?E? for Eccentric and ?T? for Tragedy. The Finance Minister made her seventh Budget speech. There are more empty words, more empty promises, and hollow words. This Budget has got more fiction than finance. ? (*Interruptions*)

I have exposed the track record of this Government on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the General Budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit or try to take a look at an audit. Sir, if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show? The election results are a direct audit of the performance of the hon. Prime Minister and this Government. The PM was the face, the body and the head of the BJP campaign which cried, ?अबकी बार, 400 पार?. And what is the result of that audit? The result of the audit is that the BJP lost heavily in West Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh. They were shaken up in Maharashtra. Their slogan of ?जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे? backfired. ? (*Interruptions*) Their slogan of ?जो राम को लाए

हैं, हम उनको लाएंगे? backfired. ? (*Interruptions*) I would rather say, प्रभु राम आए, तो न्याय आया । कुछ वक्त ज़रूर लगा, लेकिन इंसाफ आया ।

The BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat but it also lost Badrinath in the last bye-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है । The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, and shaky coalition, and it leads a coalition Government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the Union Government is investing for Modi ji?s political survival at the expense of the nation?s well-being. The truth is that the hon. Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है ।

Thank you, Sir.

सुश्री बाँसुरी स्वराज (नई दिल्ली) **:** सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है । ? (व्यवधान) माननीय सांसद जी ने एक नहीं, बल्कि तीन बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है । ? (व्यवधान) वर्ष 2021 की आप ही की रूलिंग है, ?बिट्रेड? और ?बिट्रेयल? शब्द अनपार्लियामेंट्री कैटिगरी में आते हैं, वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते । ? (व्यवधान) इसके अलावा उन्होंने ?मिनियन? शब्द का इस्तेमाल किया, जो आपत्तिजनक है । ? (व्यवधान) इन्होंने हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की और ?एक्सेन्ट्रिक? शब्द का इस्तेमाल किया । ? (व्यवधान)

सर, मेरा आपसे निवेदन है कि इन तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** जो विषय आपने उठाया है, मैं उसको चैक करूंगा । मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं । मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि इससे बचना चाहिए, यह उचित नहीं है ।

श्री जी. किशन रेड्डी जी ? आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

कोयला मंत्री**;** तथा खान मंत्री (श्री जी**.** किशन रेड्डी) **:** बहुत मिनिस्ट्रीज़ में यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट्स से नहीं आते हैं । बहुत से अलग-अलग स्टेट्स से, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उसका ?ज़ीरो?, एक भी नहीं है । ? (व्यवधान) किसानों पर अत्याचार हुआ, ?ज़ीरो?, कुछ भी नहीं है । ? (व्यवधान) आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांत में न किसानों द्वारा आत्महत्या होती है, न महिलाओं द्वारा आत्महत्या होती है, न महिलाओं पर अत्याचार होता है । ? (व्यवधान) एक ही स्टेट है, अभी हमने जो भाषण सुना है, उन्हें वैस्ट बंगाल के बारे में बात करनी थी, उन्होंने वे सारे शब्द इधर के लिए यूज़ किए हैं । ? (व्यवधान)

15.59 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

आदरणीय सदस्यों, यह पूरा भाषण, जो अभिषेक बनर्जी जी ने दिया है, यह पूरा भाषण वैस्ट बंगाल की सरकार के लिए है । ? (व्यवधान) यह भाषण भारत सरकार के लिए नहीं है, बल्कि पूरा भाषण वैस्ट बंगाल की सरकार के लिए है । ? (व्यवधान)

16.00 hrs

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Vanakkam Sir. Vaazhga Tamil**.**

The Prime Minister said: ?It is unfortunate that I was not born as a Tamilian. I only wish to be born as a Tamilian in the next birth. I love the language of Tamil and the people of Tamil Nadu.? This is what our Prime Minister said before the first phase election.

After the election got over, in the last phase when he goes to Odisha, what does he say? How can he give the control of Odisha to Tamilians? This showed his anger. People of Tamil Nadu will never forget and that is depicted here in this Budget. As you try to cheat by saying who are Tamil people and saying that you will support Tamil and wherever you went, you tried to speak our Thirukkurral and tried to get our hearts but your true heart is this. The Prime Minister is spewing venom against the people of Tamil Nadu.

Sir, I will not take much time speaking about the Budget because even the BJP Member who spoke today never spoke on the Budget. I think the time has come for the Prime Minister to take some good advice and follow our Dravidian model Chief Minister Shri M.K. Stalin. When my Chief Minister Shri M. K. Stalin became the Chief Minister of Tamil Nadu, he said, I will work not only for the people who voted for me but also for the people who did not vote for me. It is my duty. But today, Sir, our Prime Minister is not working for the people who voted for his Party but only for the parties which are supporting him.

In fact, if you see Sir, lakhs and crores of rupees were spent by this Union Government to promote Modi ki Guarantee before the elections. Wherever you went, televisions, radios, newspapers channels, it was all public money that was used to promote the Prime Minister.

Sir, after the election, Modi ki guarantee has gone. Now, we have Modi ka insurance. What is this insurance? The insurance premium is being paid by the people of India to ensure that he still continues as our Prime Minister.

Sir, for three years, the Union Government?s share of funds for Chennai?s Metro Rail has been pending. Our Chief Minister has repeatedly written and urged for the

funds. For the Chennai Metro Rail phase II, he had written to them to give 50 per cent of funds. Till date, they have not given a single rupee. But our Chief Minister has said that Tamil Nadu Government will fund it and already put Rs. 12,000 crore in this Budget.

Sir, we would like to know about this. You went to Coimbatore. You had a roadshow. The Prime Minister tried to appease the people of Coimbatore. Our Tamil Nadu has sent you a project for the Coimbatore Metro Rail and Madurai Metro Rail. We have not received any response. Nothing has come from you.

Sir, our Tamil Nadu Government has made a request for the Tambaram-Chengalpattu elevated expressway. Till now, there is no mention of the funds. For ten years, the middle class has faced the brunt of inflation, rise in food prices and rise in fuel and LPG prices.

Right now, Russia ? Ukraine war is going on and it is because of that the western countries are not buying fuel directly from Russia but this Russian fuel is being bought by India. If the price of petroleum per barrel is 120 dollars, India was getting it for 60 dollars. Did any of the Indian benefit because of the price reduction? No. The oil went to our Prime Minister?s refineries, got refined into diesel and petrol and exported to Europe and they sold it at the market price. You brought windfall taxes. For the first time in India windfall taxes was brought.

Sir, I would like to ask the Finance Minister why do you not give us a white paper on the windfall taxes and how much of money Ambanis and Adanis made because of the Ukraine war.

Sir, one has to have a heart to provide substantial relief in income tax. Household savings rate is at a record low of 5.2 per cent of Gross National Disposable Income in 2023. What does the common man get? It is only a saving of Rs.1058 per month. That is the saving they are talking about.

You have announced targeted programmes relating to irrigation and flood mitigation. Bihar got the funds for Kosi-Mechi inter-State link project. Assam, Sikkim and Uttarakhand are getting assistance for flood management. Himachal Pradesh is also getting the assistance for reconstruction and rehabilitation.

What about Tamil Nadu? We had the worst flood in Chennai. In Tuticorin, there is flood which we have never seen for 150 years. The Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman went there. She said that she was among her friends. There,

she appealed to the people, yes, we will do something. Till now, not a single rupee has come. In fact, she visited a temple there and asked the residents not to put money into the temple hundi and give the money directly to the priests.

Is this the way the Finance Minister behaves? Will it be okay if I tell the people of Tamil Nadu not to pay taxes to the Union Government? How is it that the money goes to the other States but does not come to Tamil Nadu? That is not the way. I am an elected person. But she is a selected person.

Our Chief Minister of Tamil Nadu has met the Prime Minister multiple times and made a demand for Rs.37,000 crore as disaster relief. Do you know how much money the Union Government has given to Tamil Nadu? You will be surprised or even faint. The Union Government has given only 276 crore so far. It seems to be very imbalanced for this minority BJP Government in announcing Rs.11,500 crore to Bihar due to political compulsion. When there was flood in Gujarat, the Prime Minister went there the very next day and announced a slew of support up to Rs.1,000 crore immediately. But for Tamil Nadu, even months later, there is no care.

Why is this Union Government singling out our State and denying our people the schemes that they need? It is not enough to visit Tamil Nadu during elections and call us your brothers and sisters. People of Tamil Nadu will never ever forgive you for this betrayal.

I am happy that the BJP has finally taken the clue and followed the footsteps of hon. Chief Minister Shri M.K. Stalin?s Dravidian model by copying his pioneering scheme. But the scale which you have announced is unbecoming. Take for example, the skill development scheme. What does the Budget say about it? The Finance Minister says that it will train 20 lakh people in a year. But my Dravidian-model Chief Minister, Thiru. M.K. Stalin has already introduced a scheme of training 15 lakh youth in a year. The State Government is training 15 lakh people but the Union Government, with all the resources, is training only 20 lakh people in a year.

They have also taken our trademark Dravidian scheme like State-run hostels for women ? the ?Thozhi? hostels. It was implemented by our Chief Minister. We welcome it. This should, in fact, be named as a Dravidian-model hostels for women throughout the country. The credit for this should go to our Chief Minister who first implemented it in Tamil Nadu.

Another scheme, ?Naan Mudhalvan Scheme? has now been repackaged as an upskilling programme. Even the idea of INDIA?s alliance of ensuring apprenticeship and employment-linked incentives has been taken up. It is good for them. They are copying us. But I need to remind, when the Congress manifesto announced this, what Shrimati Nirmala Sitharaman said? She said, ?It is unimplementable?. What has happened now? I think probably she thought that it was not brought by Nehru ji.

The BJP has surprisingly managed to get a few votes in Tamil Nadu. I feel bad for them. In 2019, they were competing with NOTA.

This time, the people of Tamil Nadu have given a little more. This time we got 40 seats out of 40 seats. They got no seat. Not a single seat they could win. They think that the people of Tamil Nadu will forgive them for such treatment. They are being so vicious against the people of Tamil Nadu. The South is being ignored. They have announced a slew of schemes for their allies like Bihar and Andhra Pradesh but States like Tamil Nadu, Kerala, Telangana, and Karnataka have been completely ignored. We have no issues. We want them to support Andhra Pradesh. We are not against it. But, they should not penalise other States. This reflects very poorly on them.

I thought Mrs. Nirmala Sitharaman is a very learned person. She has come out with a New East angle. Yesterday, I was scratching my head and wondering what is this New East thing. In the New East of India, Bihar and Andhra Pradesh come but West Bengal does not come. The State of Tamil Nadu is sharing border with Andhra Pradesh but we do not come into this. She is using such things. It is usually said that if I get injured, its blood for me but if you get injured, it is only a tomato puree. I remember, probably Mrs. Nirmala Sitharaman is suffering from selective amnesia or dementia. I do not know that. In 2014, the Government had Chandrababu Naidu garu as their alliance partner. We all know how badly he was treated. He had to give two choices for the ministry. He did not even have the choice to pick the portfolio. He had come for the swearing in ceremony. The Government said that one of his MPs was going to become a minister and the same Civil Aviation was given to him. At that time, the Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu garu wanted an appointment with the Prime Minister Modi. He had to wait for four months for that. He had to wait for four months to get an appointment with Modi. It is for what, it is for a special status for Andhra Pradesh. What all you have been giving him now? What did our Prime Minister say in 2019? He said

during a rally in Rajamahendravaram: ?The Polavaram Project is an ATM for Chandrababu Naidu and his son.? When he sues you, you put him up and down but when you want to becomes the Prime Minister because of his help, the same ATM changes and become a very important machine for the country.

As far as Bihar is concerned, within one week, 15 bridges in Bihar collapsed. Normally, our Sangh Parivar would have come and said: ?There is corruption. The bridges have fallen. There should be a CBI and ED inquiry.? But, what is the Government doing? The Government is giving Rs. 26,000 crore to rebuild those bridges. The Government is rewarding the corrupt persons in Bihar because they want to stay in power and they say that they are pure. How can we accept that?

There was a lot of hope from the Budget. Everyone thought that it would be a pro-poor, pro-farmer, and pro-youth Budget. We also thought that this Government?s humbling defeat would make it to come back clean and good for everyone. The expenditure on social sector is crucial for a developing nation like India. It is the only tool by which we can eradicate poverty, develop better health infrastructure, and provide safety net for the most vulnerable sections of the society. As per the Government?s estimate, the Government always compares the amount spent this year versus the last year to show how overall the welfare expenditure has grown at a CAGR of 12.8 per cent; education by 9.4 per cent and health by 15.8 per cent and claims it as a record expenditure but the devil is in the details. Looking at the figures in terms of percentage of total expenditure reveals a different story. The expenditure on education was just around 1.9 per cent in 2017-18.

Medical and public health expenditure has decreased from 0.8 per cent to 0.16 per cent. Welfare schemes for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Minorities have declined from 0.16 per cent to 0.13 per cent. There is no mention about census. This is the fifth Budget being presented without census. This is the first Government since Independence that has failed to conduct census, even three years after the pandemic.

Sir, you compare yourself with the other countries and talk about becoming the fifth-largest economy of the world. One hundred and forty-three countries in the world have conducted the census successfully after the pandemic and managed to get the data. So, what does it mean? The Government does not know how many people to plan for, what the state of human resources are, what the demography and economic structure are at the local, regional and national levels. So, how can we expect effective policy making from this Government? One wonders if you are

avoiding conducting a census because of the pressure from within your dependable allies for a caste-based census. The Budget lets down the poor and fails to address the growing economic inequality.

Sir, when Dr. Manmohan Singh, the Former Prime Minister took over, the GDP in 2004 was Rs. 54.8 lakh crore. The GDP usually doubles every ten years. When Dr. Manmohan Singh left the office and the great Prime Minister, Shri Modi took over in 2014, the GDP was Rs. 105.27 lakh crore which literally doubled. Now, let us do the maths. That means, after ten years, it should have been doubled. It should have been more than Rs. 200 lakh crore. But in 2023-24, it is only Rs. 173.82 lakh crore. This shows that you are not performing as you claim to perform.

Sir, Budgets are aimed at stimulating growth. The Economic Survey says that India's real GDP grew by 8.2 per cent in FY24, marking a growth of over 7 per cent for the third consecutive year. Its forecast now is a modest 6.5 to 7 per cent. But what is growth? Is it just the increase in the size of the economy or is it an equitable distribution of wealth from the growth? Who is benefitting from this growth? Is it the 3.44 crore people living in extreme poverty in the country? Afterall, they are the ones most affected by macroeconomic indicators like inflation in food prices. While headline and core inflation have eased to 5.1 per cent and 3.1 per cent respectively, the Consumer Food Price Index remains high at 9.4 per cent in June 2024. Economic inequality has widened significantly over the past decade under the BJP's crony capitalist Government. The wealth of India's billionaires, who are Modi?s friends, has increased by 35 per cent in 2020 alone, while millions were pushed into poverty due to the pandemic. Reports indicate that the top 10 per cent of the population holds 77 per cent of the national wealth, highlighting a severe disparity in income distribution.

Sir, there is another astounding statistic within this as well. By 2022-23, the top one percent of the country's population had 22.6 per cent share of all income and owned 40 per cent of all the wealth in the country. This is worse than the colonial era of the British Raj.

Sir, talking about youth and unemployment data, this is the elephant in the room. Despite promises to create two crore jobs annually, the reality has been starkly different. The unemployment rate rose to a 45-year high of 6.1 per cent in 2018 to 17.8 per cent now. This was much before the pandemic. So, you cannot blame the global situation. Today the situation is worse. On one hand, the Ministry of Labour and Employment is saying that as per the latest available Annual Periodic Labour

Force Survey Reports, the estimated unemployment rate on usual status for persons of age 15 years and above was 4.2 per cent in 2021, 4.1 per cent in 2022 and 3.2 per cent in 2023. But the data from the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), an independent think tank, says that the unemployment rate was 8 per cent in 2020-21, 5.9 per cent in 2021-22 and 7.3 per cent in 2022-23. This is far more believable looking at the ground reality. According to the CMIE Data, the unemployment rate in India stood at 9.2 per cent in June 2024, a sharp increase from 7 per cent in May 2024. CMIE's Consumer Pyramids Household Survey shows that female unemployment reached 18.5 per cent, exceeding the national average, in June 2024. This is up from 15.1 per cent in the same period last year. At the same time, male unemployment stood at 7.8 per cent, slightly higher than 7.7 per cent in June 2023. While the Labour Participation Rate (LPR) rose to 41.4 per cent in June 2024 from 40.8 per cent in May and up from 39.9 per cent in June 2023, the rural unemployment rate rose to 9.3 per cent in June from 6.3 per cent in May. The urban unemployment rate climbed from 8.6 per cent to 8.9 per cent. This contrasts sharply with the 2014 figures, where the unemployment rate was 5.44 per cent when the UPA left power.

Sir, the Finance Minister highlighted the BJP Government's nine crucial priorities for transforming India into a developed country by 2047. The nine priorities for generating ample opportunities for Indians included - productivity and resilience in agriculture, employment and skilling, inclusive human resource development, social justice, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development, and next-generation reforms.

Let me take them one by one. First is, productivity and resilience in agriculture. An Inter-Ministerial Committee was set up in April 2016 to lay out a roadmap to double the farmers? income by 2022 as promised by the Prime Minister. They used the 2012-13 National Sample Survey Office data to estimate that. The national average annual income of Indian farmers was Rs.96,703 in 2015-16. Based on this, the Committee set the targeted double income at Rs.192,694 at 2015-16 constant prices to Rs.271,378 at current prices in 2022-23. The Committee calculated that to achieve those levels, the farm income would have to grow annually by 10.4 per cent over the next seven years. While data for 2022-23 is not available. According to the last situational survey data released in 2021, the average annual income of farming households increased from Rs.96,703 in 2015-16 to Rs.1,22,616 in 2018-19. This suggests that the annual growth in farmers' income has been mere 2.8 per cent.

Even this growth has been driven by non-farm income since the income from crop cultivation declined by 1.5 per cent annually since 2015-16.

Sir, when this Government came to power, they did a promise ? I was also surprised ? that a mega project of interlinking of rivers will be taken up. How many rivers have they interlinked? Can they give us a White Paper on that? They changed the name of the Ministry as Jal Shakti Ministry because they want to interlink rivers. What a scam, Sir! That means, they are still all alone.

Sir, now let us come to employment and skilling. I have already presented my case on the unemployment issues and the lack of scale in the Skill Development Scheme. I remind you again, the Budget says it will train 20 lakh youths across the country while in my State, the Chief Minister of Tamil Nadu is providing training to 15 lakh youths every year through the Dravidian Model. So, there is a wide gap between a State and a country.

So far as inclusive human resource development is concerned, the Government's strategy for inclusive human resource development and social justice focuses on comprehensive growth across various sectors. Programs for education, health, and economic empowerment, enhancing schemes like PM Vishwakarma and PM SVANidhi to support artisans, self-help groups and entrepreneurs, the Purvodaya Initiative in the East, projects like the Patna-Purnea Expressway, Rs 15,000 crore for Andhra Pradesh's capital needs and support for the Polavaram Irrigation Project are all commendable. But why is my State, Tamil Nadu not included? Why are all the other States not included? I would ask, and the people of India would like to know where is the report card for how similar schemes have fared in the past. Many questions on these topics have only given vague data on funding and outcomes.

Sir, India?s public healthcare system remains under-funded and over-burdened. The country?s healthcare expenditure is still averaging around 1.28 per cent of GDP, much lower than the global average of six per cent. Rural areas face severe shortages of doctors and medical facilities. So, how exactly will you have inclusive human resource development?

Sir, let us come to social justice. Caste-based discrimination and social inequalities persist. Dalits and other marginalised communities continue to face significant socio-economic challenges. Inclusive policies and robust implementation are needed to ensure social justice. But all we see is welfare schemes being ignored

and spending being cut for these sections that require a social security or safety net. We, from Tamil Nadu, and our Chief Minister have repeatedly explained how NEET is anti-social justice, yet you still remain adamant on not abolishing it. Our hon. Speaker comes from Kota and that is his constituency. Every year more than 22 students commit suicide because of the fear of facing NEET. The same thing is coming from other States. There is the question of future of our children. Your arrogance should not come in the way. This is not what we want. This is anti-social. This is against social development. I hope, you open your eyes and, after all the scams, try not to cover it up and pushover it.

Sir, then they are talking about urban development. You refuse to fund our Chennai Metro Project or any other metro project, and load the States with the construction bill for housing projects. The Air Quality Index (AQI) in major cities continues to be hazardous, and deforestation rates have increased.

Smart Cities Mission has been extended till March 2025 after the June deadline was missed. Smart cities allocation is slashed to Rs. 2,400 crore for FY25 from Rs. 8,000 crore in FY24.

You say more resources will be allocated to the Urban Rejuvenation Mission, which is more about improving the living conditions of the urban poor in the cities, but even during the course of this election, we saw in Chennai that when the Prime Minister Modi went for a roadshow from his favourite area of West Mambalam, he had to cross my constituency where poor people were staying in the Slum Board houses on which clothes were put. They did the same thing in Nama Kshetram where they did not want to see the poor of Gujarat. In the similar way, the houses of poor people of Chennai were covered. This is the condition of the poor.

Then, what happened to piped drinking water to every house? Nothing has been happening.

PM is talking about energy security. FM has announced a diversified energy plan focussed on small, modular nuclear reactors, rooftop solar plants and the development of indigenous technology for Advanced Ultra Super Critical (AUSC) thermal power plants with much higher energy efficiency. Can we have the data of how much of this funding will be allocated to each State and how will the criteria for selecting these projects for each State be decided?

As on June, about 54.5 per cent of India?s power came from thermal sources like coal, gas and diesel, while 45.5 per cent came from non-fossil fuel sources, which

includes 1.8 per cent nuclear power capacity, according to the Power Ministry. How does the FM plan to alter this drastically in a short period? What happens if a State decides to not opt for small, modular nuclear reactors and wants to pursue an alternate source? Is there a mechanism for how this announcement will be implemented?

There is an announcement related to the ambitious green hydrogen mission which got Rs. 600 crore in the Interim Budget. No announcement has been made related to electric vehicles and FAME III, which will be critical to not just cleaner environments but also the industry. What about funding for harnessing offshore wind energy potential?

Regarding infrastructure, FM has budgeted Rs. 11.11 lakh crore of capital expenditure for 2024-25, and roads and railway projects are to get nearly 50 per cent of this outlay. The massive slash in the social sector spending over the years coupled with the unimaginative move to push capex once again in the latest Union Budget has become the trademark of the BJP Budgets and does little for the common people of this country.

The budgeted capital expenditure is about 17 per cent more compared to the actual expenditure of Rs. 9.48 lakh crore last year. The FM has once again bet on increased capital expenditure spending, but with little to show how it has helped deliver results. The two most powerful indicators of a revival in the capital expenditure cycle are acceleration in the completion of investment projects and in the increase in net fixed assets of non-finance companies. We are yet to see any result for the capex investments of the last few years. So, how can we be sure?

We must also not forget that large capital expenditure is at the cost of welfare. There have been significant cuts in major schemes and no investment in key sectors like healthcare and education. Similarly, schemes for minorities, the disabled, and pensions for the elderly, have all been summarily reduced. In addition, the rise in prices over the past five years means that every rupee buys about less than it did in 2019. This deadly combination of insufficient funding and rising inflation directly hurts our nation?s poorest and the most disadvantaged. It will only aggravate the existing crises such as inflation, historically high unemployment, and low savings in the country. So, this push for infrastructure comes at a large cost. When will we see the results of the massive capex spending by the BJP?

Now, I will come to innovation and development. All of us will be in support of fostering indigenous innovation and research, but will the Union Government follow through with sufficient and consistent funding? The Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development is to be operationalised. How does the Government propose to do this? Is there a roadmap in place? Financing pool of Rs. 1 lakh crore for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale is commendable but where are the funds for such an announcement going to come from?

16.32 hrs (Shri A**.** Raja *in the Chair*)

Let us talk about the next-generation reforms. How does the Government plan to ensure uniform implementation of land and labour reforms across the States, given the varying levels of infrastructure and governance capabilities? How does the Union Government plan to structure the fiscal support for the States? What criteria will be used to determine the allocation of funds? How will the Government address the digital divide, particularly in rural areas, to ensure that the benefits of digitised land records and GIS mapping are accessible to all the citizens? How will the Government involve various stakeholders, including farmers, labour unions, and industry representatives, in the reform process to ensure their concerns and suggestions are adequately addressed? We already saw how your farm laws backfired due to lack of consultation.

Chairman Sir, in conclusion, the Union Budget has once again failed to meet the aspirations of the middle-class people. Nearly Rs. 4 lakh crore have been promised as subsidy for Andhra Pradesh and Bihar to support you being the Prime Minister. I would like to ask this. From where is the money going to come? At whose cost are you going to do this? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

? (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: We are supporting you. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair. Do not yield to them.

? (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Thank you, Sir. You are very fair. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, at this point, while I conclude, I would like to mention our demands. Our Chief Minister, Shri MK Stalin, is for the people. Tamil Nadu has risen as a primary State, as a number one State in governance, and is ensuring that development takes place. But why are you penalising us? Is it because we did not elect you? We did not elect you because you are two faced. You always do useless abuses. You want to split us in the name of religion, caste. You make sure to discriminate us by birth. Till now, many times the Prime Minister has said he loves Tamil language. What has he done for our Tamil language or for the people of Tamil Nadu? We say in Tamil: ?Vaayila vadai sudaravar thaan Modi.? It means: ?He fries *vada* through his mouth, not in the oil.? He does not even give the *vada* to us. He takes it and eats it himself.

I humbly request you this. The people of Tamil Nadu are watching you. Do not try to punish them. If you punish Tamil Nadu, then India will not grow. If India has to grow, Tamil Nadu has to grow. The people of Tamil Nadu have one more great fear from our Prime Minister. In 2014 when the Prime Minister first entered the Parliament, he came to the old Parliament and fell flat and took the blessings of the Parliament. This was in 2014. Now, that is no more the Parliament building. Now, in 2024, the Prime Minister took blessings from the Constitution. He took the Constitution book and took all his blessings. The people of Tamil Nadu and the country are worried. Please do not destroy the Constitution. Thank you, Sir. Vazhga Tamil!

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Sir. This is my first speech in the Parliament. I have heard many learned Members speak today. I am not as prepared for countering many of the things that were said, but I think as we speak in the future, I will learn from it. I think the takeaway is that politics at different times change, and when we point fingers at someone, there are four fingers pointing back at us. I think that I will speak about those as we proceed into the future.

I would like to start off by thanking the hon. Prime Minister and the Finance Minister for their visionary Budget, which exemplifies the Government's unwavering commitment to Viksit Bharat and the goal of making India a $30 trillion economy by 2047 and also making it the third largest economy by 2027.

There were things that were said by Members of the Opposition. I would like to highlight some of them. One was that the Government today is not a stable Government. I would like to remind everyone that when the UPA-II came into power in 2009, the UPA did not get the magic numbers. They were under 273 and they had to take external support of other Parties to form the Government. Compared to the times then and the partners over here that were part of that alliance, they are much stronger now than they were then.

I would like to also highlight that what we are doing now is that the alliance is based on pre-election agreement among the political parties and we have all come together based on the needs of our respective States. I will come back to why Andhra Pradesh needs help and what are the challenges that we have faced over the last five years.

I would like to highlight certain aspects of the Budget, which will help us become Viksit Bharat by 2047. I would like to start off with the focus on infrastructure and capital expenditure. The amount of Rs. 11.11 crore that has been committed to capital expenditure is about 12 per cent greater than what was committed last year. I would also like to appreciate that an amount of Rs. 1.5 lakh crore has been given interest-free for multiple States across the country to leverage and to build their own infrastructure.

I would also like to acknowledge the budget given for Rural Bharat. There is an allocation of Rs. 2.66 lakh crore. In particular, I would like to appreciate the Government for recognising the challenges of the MSME sector by basically providing end-to-end support from the new credit assessment for giving about Rs. 100 crore of loan without collateral; from giving support to stressed MSMEs during their times of difficulty; and to giving them access to funds. I think that the MSMEs are the backbone of the country because across rural and urban areas, there are millions of MSMEs across the country that need that help.

But, through this development we are not leaving people behind because there are allegations of price rise and inflation. I would like to remind here that the average inflation in the NDA Government over the last 10 years has been about five per cent as per the World Economic Outlook, but during the UPA regime between 2004 and 2014, the inflation was 7.5 per cent. So, there is a 2.5 per cent average lower number of inflation in the last 10 years compared to the UPA regime from 2004 to 2014. So, whatever complaints the Opposition has about price rise, I think they are pointing a lot more fingers at themselves.

I think the commitment of the Government to give budget support to one crore families for building housing -- both in urban and rural areas -- is much appreciated and we look forward to getting that benefit in Andhra Pradesh also. We appreciate the continued welfare support through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to 80 crore people and the Government is continuing that for five more years.

I would like to specially mention about the water management, sewage and solid waste treatment plan in about 100 cities, and I hope that the city of Visakhapatnam that I represent is covered in it. I have been told in the Parliament, during the entire campaign and also after having contested in 2019 that there is an acute shortage and this is an acute challenge which we face in our city with sewage and solid waste treatment issues.

I would also like to highlight the solar plan which is about installing solar panels in one crore households for 300 units of free electricity. Through this, the Government is providing developmental support to not only the wealthy, but also to the poor and to the people all around the country. I hope that, as the country keeps moving forward, we support many others. We have provided a basic standard of living through these various initiatives. We focus on infrastructure and we focus on economic growth. But the question is about equity. How are we giving opportunity to different people around the country?

There are different things that the hon. Finance Minister has spoken about in the Budget speech. One thing, which is very interesting, was about being able to provide internship opportunities to one crore youth across the country to start with in the 500 top companies. But I hope that it gets spread to other companies. In the budget outlay, the Government has announced to give one-time assistance of Rs. 6,000 and a monthly benefit of about Rs. 5,000. I would like to appreciate the intention to set up a thousand ITIs in the hub-and-spoke model across the country and train 20 lakh youth in skilling. I think it is a much-needed initiative.

Being a person who is in higher education, I would like to, in particular, appreciate the intention to give loan support of about Rs. 10 lakh to every student who wants to pursue higher education in domestic institutions and also giving three per cent subvention on interest. I did my graduation in the US. I lead a university in India today with about 30,000 students. I have seen over the last two decades that increasingly the number of assets that one holds is going down. Most of the people have to take debt to educate their children. And today, I do not want India to go into a place where the United States is right now, which is rising debt trap in the

students community. And, I think, if you see the major expenditure that any household incurs is on education and on healthcare. So, this important scheme coming in the higher education is much appreciated.

I would also like to briefly mention some initiatives in the Atmanirbhar Bharat intentionality, which is about making ourselves self-sufficient on the semiconductors and the entire technology sector. Given the challenges we have seen in the pandemic and, in general, in the global uncertainty, I think all of the production link incentives we have given in the technology, IT, and automobile sector are all very necessary to provide opportunities for the Indian citizens for pursuing manufacturing in India. As we do all this, I think there are two potentially disruptive forces that we have to watch out for. I am happy to see that certain initiatives in those areas have been announced.

The first disruptive force that could really change the way we live is working on climate change and environment sustainability. While we may be ignorant of the incremental damage to the environment, we are all seeing the way cyclones, hurricanes, storms and earthquakes are happening around the world. So, investments into that area are like bringing clean energy, doubling the budget from Rs. 10,000 crore to close to Rs. 20,000 crore on new, renewable energy, increasing the nuclear power investments by almost 400 per cent from about Rs. 500 to Rs. 2,000 crore, and increasing the solar grid capacity. Looking at the overall renewable energy capacity, in 2014, we had 76 gigawatts. Now we have come close to 200 gigawatts. So, the Government is delivering on its stated intention, and I think it will keep doing so over the next five years.

I would like to also specifically mention, though it is a small investment into the space, the VC fund that has been set up for Rs. 1,000 crore. I think, it is very important because as we exhaust our natural resources and as we look beyond the earth, investing into space startups and potentially living on other planets down the line will not be an impossibility. It will be a possibility. I am glad that India is joining that idea.

I would also like to highlight the second potentially disruptive and very dangerous thing, that is, artificial intelligence which has to be managed well. The Government of India approved the India AI Mission in March 2024 with a budget outlay of about Rs. 10,000 crore over the next five years. I would like to request that we put specific focus and do research on the impact on the labour markets through the advancement of AI, what regulations we need to put in place to ensure that AI does

not overtake the way our labour market functions, and also invest into research on how we can skill our workforce to deal with AI in the future.

As far as the State of Andhra Pradesh is concerned, I would like to specifically appreciate the hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji and our hon. Prime Minister, Modi ji, for the support of Rs. 15,000 crore that has been announced for Amaravati in the current financial year and the commitment to allocate more in the coming years because Amaravati is a project that is very historic and unique. We have received about Rs. 33,000 acres from over 30,000 farmers without taking a single rupee upfront with the trust that we will develop and give back a world-class Capital. But due to the damage caused in the last five years by the previous Government, we have lost that ability to do it. So, we need the support of the Centre and we appreciate the Centre?s response to that.

As far as industrial development infrastructure goes, there was a mention of the Koparthi node, the Orvakal node in the Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and the Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor. We would like to work closely with the Central Government in ensuring that these are a reality in the very near future. We would like to appreciate the grants for the backward regions, Rayalaseema, Prakasham and North Coastal Andhra, which I represent, getting the grants continuously over the next five years, and we look forward to overall getting all the aspects of the AP Reorganization Act being implemented in letter and spirit. We appreciate the Finance Minister for that support.

I would also like to specifically mention something that was mentioned at the beginning of the Budget speech and somewhere in the middle, which is about the seafood exports. Andhra Pradesh now exports close to 40 per cent of the seafood in India out of the $8 billion industry. And there is significant challenges in terms of what the farmers face in terms of access to the shrimp brood stocks. So two things were mentioned. One, starting a breeding centre for shrimp brood stocks in the country will really mitigate the production volatility and provide the livelihood stability for thousands of aqua farmers in our State, and also providing NABARD financing for not just the shrimp farmers, but also for the processors and for the exporters. So we thank the Government for that support.

I would also like to highlight here to all Members of the House why Andhra needs this support. The State was divided in 2014. I would like to remind everybody in the House, the division, according to us, was done unscientifically. For the first time in 2014, Andhra Pradesh had a deficit budget after eight years of continuous positive

budgets. And even the revenue distribution that was done was not done fairly. It was unequal. There are multiple challenges. After our Government came to power in 2014 and our leader, Mr. Chandra Babu Naidu, was the Chief Minister. We systematically worked on developing the economy. We competed with Telangana in the development of our per capita income. On multiple metrics, we were doing well. Our agriculture grew, our economy grew at a faster rate than the country?s economy.

But in 2019, when we lost the elections, the damage that has been done to the State in the last five years, to some people?s eyes, they feel that we have gone back by 15 to 20 years. For a State that historically has received only about 40 paisa or 45 paisa for every rupee it gives to the Centre, we are in a very unique position today where we need to depend on the Centre to be able to run our State. And that is the particular reason why I even went to elections together with the BJP, with the Jana Sena, with Modi Ji and with Pawan Kalyan Ji for the good of the State. What are the challenges we faced? Amravati was not just not developed. It was systematically tried to be killed and destroyed. We have seen the farmers in Andhra Pradesh protesting for over 1200 days, close to 1,500 days, protesting against the earlier dictatorial regime in Andhra Pradesh.

Coming to the progress of Polavaram, well, it achieved about 72 percent by the end of 2019. It is because of the Government in the last five years, I am very sad to say that it has only progressed about three percent. And under the claims of saving money or reverse tendering, they have damaged so many aspects of the Polavaram project. Now we have an international committee coming and checking it out and seeing what damage has been done and how we can prepare it for the future. I am also very sad that Andhra Pradesh, that was thriving, had the highest unemployment rate among graduate youth in India at about 24 percent in the year 2022-23. We seek to really reverse that. And overall, we still have not released our White Paper on finances of the State. I think we will do that shortly, maybe today or tomorrow. But the State's debt is estimated to have reached about Rs. 13 lakh crore in many forms, debt on the State, debt through corporations - many of which we do not know - debt through liabilities that have to be paid, debt through incentives that have to be paid. When we club all of them together, it is about Rs. 13.5 lakh crore. When we left office in 2019, the State debt was about Rs. 3.5 lakh crore. In a period of five years, we have seen the debt going up by Rs. 10 lakh crore. And that has really crippled us and our ability to invest into our own future. And the by-products of that are many other failures.

One such thing I would like to highlight is the failure in the way that we have managed our power sector leading to a loss of over Rs. 1.2 lakh crore in the power sector alone. I can keep going on and on, but I think the people of Andhra Pradesh have recognized these failures in governance. And when we came together, the BJP, Jana Sena and TDP, we went to the people that we need to beat this dictatorial regime. They have given us a historical mandate of 164 seats out of 175 seats. We have won 21 seats in the NDA.

I would like to remind the Members from the Opposition that we have gone together. It is not that BJP has three MPs in Andhra Pradesh, but the NDA has 21 MPs in Andhra Pradesh. That is a very strong part of the Government today. We would like to continue to seek Central support over the next few years because we would like Andhra Pradesh to come back onto its feet. As was said before, strong States make for strong countries and cooperative federalism is very good for all the States to compete in a very positive manner. So, we would like to continue to do that. But we seek that help in the short-term so that Andhra Pradesh can get back onto its feet. Under the visionary leadership of our leader Chandrababu Naidu ji, we had difficulties in 1995 when he became Chief Minister. We had difficulties in 2014 when we came to power. But we have never seen difficulties like this what we have now in 2024. In fact, just yesterday, our Chief Minister while speaking in the Legislative Assembly said, ?I cannot even announce the Budget of the State because that is how bad the things are. I need two months? time to study how bad the things are before I can even announce a Budget for the State.? So, we are very sad as Members of Parliament representing our State to see a prospering State in this condition. But regardless this, innovation is going about unabated. Similar to the skilling commitment of the Central Government, Andhra Pradesh has taken on a very innovative decision to do a skill census to measure the requirement of skills and availability of skills in all the districts of Andhra Pradesh and use that information as a basis for skill development, as a basis for employment, as a basis for investment into the State of Andhra Pradesh, and we will continue to do so.

There are many other things that I would like to speak. But I will just end with a few things. Coming back to a few things concerning my Parliamentary constituency Visakhapatnam, the Government has recently announced the intention to overhaul 200 State-run firms and shift the focus away from privatisation and towards enhancing intrinsic value.

I request the hon. Finance Minister to include the Vizag Steel Plant among the State enterprises. We will provide all our support from the State Government to bring it back onto its feet and really deliver on providing steel to the country. We would like to continue to coordinate with the Government on the speedy establishment of the South Coast Railway Zone. I look forward to whatever budgetary allocation is required for that.

I would like to end my speech by saying that this gracious allocation for a State like Andhra Pradesh is very well received by the people of Andhra Pradesh especially in the despair that we have been in the last five years. We would like to acknowledge our Prime Minister Narendra Modi ji and our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji for recognising this need and respecting the judgement of the people of Andhra Pradesh.

I look forward to participating more in this august House in further debates. I thank the hon. Chairperson for the time given to me to speak today.

Thank you.

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट 2024-25 पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं काफी समय से सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था । कांग्रेस पार्टी की कुमारी सैलजा जी ने कहा कि यह बजट बिहार का बजट है और उन्होंने एक राज्य का नाम लिया है । उसी तरह से टीएमसी के एक सदस्य ने भी कहा कि यह बिहार का बजट है एवं इसमें और कुछ नहीं है । अभी मैं डीएमके के सम्मानित सदस्य माननीय दयानिधि मारन जी को भी सुन रहा था । उन्होंने कहा कि यह बजट कुछ राज्यों के लिए है, बिहार के लिए है । बिहार में 15 पुल गिर गए हैं । यह जो पैसा दिया गया है, यह उसकी भरपाई के लिए हैं और इस बजट से भ्रष्ट लोगों के हाथों में राशि दी गई है ।

मैं बहुत दिनों से मारन साहब को देख रहा हूं । वह अंग्रेजी में बोलते हैं, जोर-जोर से बोलते हैं और चिल्ला चिल्लाकर भी बोलते हैं । उनको बोलने से पहले थोड़ा संयम जरूर बरतना चाहिए । हम किसको भ्रष्ट कह रहे हैं? हम किसी दूसरे को भ्रष्ट कह रहे हैं, तो उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए । बिहार को पैसा दिया गया, बिहार सरकार को पैसा दिया जाएगा, तो आप भ्रष्ट कह रहे हैं । बिहार को पैसा दिया गया है, यानी आपकी नजर में हमारे शासक भ्रष्ट हैं । महोदय, वैसे मेरा स्वभाव इस तरह का बोलने का नहीं है और यदि मैं भी बिना तथ्य के कहूं कि तमिलनाडु के शासक भ्रष्ट हैं तो अच्छा नहीं लगेगा । इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए । ? (व्यवधान) रिकॉर्ड में यह बात है । आपने यह कहा था । हम उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं । आप अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेकिन हिन्दी में ट्रांसलेशन हो रहा था कि भ्रष्ट लोगों के हाथ में पैसा दे दिया गया है । मारन साहब, आप बिहार को नहीं जानते हैं । यदि आपके यहां बरसात से पानी अधिक होता है तो कभी-कभी बाढ़ आ जाती है । यदि बाढ़ आती है तो मैनेजमेंट की भी गलती होती है, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता नहीं

होता । बिहार की स्थिति यह है कि हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं, नेपाल देश से होते हुए सबसे पहले बिहार में उनका आगमन होता है । वह पानी प्रत्येक साल तबाही मचाता है । यह एक-दो बार नहीं होता है, प्रत्येक साल जान-माल की क्षति होती है और अच्छी बनी हुई सड़कें भी टूट जाती हैं । उससे पुल और पुलिया भी ध्वस्त हो जाती है, जमीन भी कट जाती है और फसल की भी बर्बादी होती है ।

महोदय, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी वजह से आधा बिहार बाढ़ से परेशान है और आधा बिहार सुखाड़ से परेशान है, फिर भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपने संसाधनों से बिहार को ऊंचाई पर उठाने का प्रयास करते हैं । हम वर्ष 1990 में विधायक हुए थे । हम अनुभव की बात बताते हैं कि बिहार विधान सभा की कमिटी पंजाब और हरियाणा आई थी, उसमें हम भी थे । हमने देखा था कि सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं । हमें आश्चर्य होता था कि हम लोगों के यहां ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन आज के दिन आप बिहार जाकर देखिए, लेकिन आप लोगों को तो मौका नहीं मिलता होगा । बिहार के लोगों के प्रति देश के लोगों का नजरिया बहुत गलत है, लेकिन ऐसे लोगो को एक बार बिहार में घूमकर देखना चाहिए । आज बिहार की यह स्थिति है कि सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं, सभी गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है । आपको उसको देखना चाहिए । यह मानसिकता बनी हुई कि बिहारी है, बिहार में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, सब पुल बह गए हैं, सभी पुलों का पैसा खा गए हैं ।

यदि भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ दिया है तो हम मानते हैं कि वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है । बिहार को बहुत कुछ मिलना चाहिए, इसलिए सरकार के स्तर पर, हम बिहार के प्रतिनिधियों के द्वारा बार-बार यह मांग की जाती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले । कुछ तकनीकी कारणों के चलते वह नहीं मिल पा रहा है । यदि बिहार को मिल गया तो इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, हम पहली बार 1996 में सांसद बनकर आए थे । इस बार मैं पांचवीं बार सांसद हूं । हमने कई सरकारों को देखा है और कई प्रधानमंत्रियों को बनते हुए देखा है । हम उनके साथ लोकसभा में रहे हैं । महोदय, हम आपको भी बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता और घनिष्ठता न हो, वह अलग बात है । पहली बार हम वर्ष 1996 में सांसद बनकर आए थे । हमने कई विभागों के मंत्रियों और अन्य लोगों को भी देखा है । तृणमूल कांग्रेस के एक नौजवान सांसद बनर्जी साहब बोल रहे थे कि बिहार में सारा पैसा चला गया है, दूसरी जगह नहीं गया है । हम यह नहीं कहते हैं और आरोप लगाना मेरा स्वभाव नहीं है । हम तो उस जमाने में भी थे, जब वहां से रेल मंत्री होती थीं । वह सम्मानित नेता थीं । हम अभी भी उनको सम्मानित मानते हैं । हम लोग चिल्लाते रहते थे और बंगाल में पैसा जाता था, लेकिन बिहार में पैसा न के बराबर जाता था । जो पिछड़ा हुआ है, जिसको आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पैसा जाता है । इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार को जरूर इस बार राशि मिली है । हम प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुझाव और प्रस्ताव को कुछ हद तक मानकर बिहार को राशि देने का काम किया है । हमारे यहां सड़क सेक्टर में भी पैसा गया है ।

17.00 hrs

सड़क सेक्टर में 26 हजार करोड़ रुपये देखने में बहुत लगता है लेकिन इससे क्या हो सकता है? इससे दो एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे । एक एक्सप्रेस हाईवे जो पटना से पूर्णिया तक बनेगा, वह हमारी लोक सभा से भी गुजरेगा । दूसरा, बक्सर से भागलपुर तक एक एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, उसके बाद छोटी-छोटी कुछ सड़कें हैं । बक्सर में

गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनेगा । ऐसा नहीं है कि जो पुल ध्वस्त हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए यह राशि दी गयी है । पुल के निर्माण के बारे में बिहार के बारे में अखबार वालों का नज़रिया भी ठीक नहीं रहता है और टीवी वाले दिखाते हैं कि पुल ध्वस्त हो गया । मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक पुल था । मैंने सुबह-सुबह मिडिया में देखा उसमें बताया जा रहा था कि बिहार के सहरसा में एक और पुल बह गया । मुझे लगा कि कहां का पुल बह गया है? मैंने इस बारे में डीएम से पूछा कि कहां का पुल बह गया है, तो उन्होंने कहा कि महिसी प्रखंड के एक गांव में ग्रामीण विकास विभाग की सड़क थी, वहां 10 लाख रुपये का पुलिया बना हुआ था । वह कोसी नदी के किनारे है और जब बाढ़ आती है तो प्रैशर होता है, चूंकि, पुलिया छोटा होता है, उसका एप्रोच बह गया । लेकिन, टीवी में यह दिखाया जा रहा था कि बिहार का एक और पुल ध्वस्त हो गया जो कि हमारी लोक सभा के महिसी प्रखंड के बारे में था । इसमें पत्रकार अपने आप से बनाकर बोलते हैं ।

बिहार में आज बिजली सभी जगह उपलब्ध है । बिहार में अभी इतने संयंत्र नहीं हैं कि आवश्यकता अनुसार बिजली का उत्पादन किया जाए, और उसी बिजली का उपयोग किया जाए । बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर में बिजली दे रहे हैं । बाहर से भी बिजली खरीदकर उपलब्ध करायी जाती है, जिसके लिए बजट में 21400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पिरपैंती में 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगेगा । उसी के साथ-साथ इसमें एक-दो हवाई अड्डों के जीर्णोद्धार के भी काम होंगे । इसमें राजगीर और भागलपुर में ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा । इसके अलावा सहरसा में भी एक राज्य सरकार का छोटा एयरपोर्ट् है, उसका जीर्णोद्धार होगा । यह सारी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए प्रस्तावों के लिए ही दी गयी है । इस सबकी आवश्यकता थी और यह सब होना चाहिए तो इसमें सभी लोगों को खुशी होनी चाहिए । इस सब से ये सारे काम होंगे ।

मैंने पहले भी कहा है कि बिहार बाढ़ से तबाह रहता है । खासकर के कोसी नदी से तो प्रत्येक साल लोग बर्बाद होते हैं । कोसी-मेची अंतरराष्ट्रीय लिंक प्रोजेक्ट, बैराज, नदी के प्रदूषण, नवीनीकरण और सिंचाई की अन्य परियोजनाओं के लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने 11500 करोड़ रुपये दिए हैं । हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव को माना है । प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि 25000 ग्रामीण बसावट में हम सड़क बनाएंगे । यह केवल बिहार में ही नहीं होगा बल्कि पूरे देश में पीएमजीएसवाई की सड़क बनेगी । इससे सभी लोगों को खुशी होनी चाहिए ।

पर्यटन की दृष्टि से बिहार पिछड़ा हुआ था । पर्यटन के विकास के लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा हुई है । काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल की तरह गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोद्धि मंदिर के लिए भी राशि की व्यवस्था करायी जाएगी । राजगीर में हिन्दू, बौद्धों और जैन धर्म के अत्यंत धार्मिक महत्व के जैन मंदिर परिसर में 20 वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का प्राचीन मंदिर है । सप्तऋषि या सात जल धाराएं मिलकर एक गर्म जल ब्रह्मकुंड राजगीर के विकास के लिए भी घोषणा की गयी है । नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है । उसके पुनुरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी, इसकी घोषणा भी की गयी है ।

सभापति महोदय, गया में जो औद्योगिक केन्द्र है, उसका विकास किया जाएगा, जो कि पूरे पूर्वांचल को कवर करेगा । भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी भारत सरकार ने राशि दी है । पहले से जो राज्य विकसित हैं, जिनको पहले से बहुत कुछ मिल चुका है, उसकी तो लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो पिछड़ा राज्य है, जिस पर माननीय प्रधान मंत्री जी की आज दया-कृपा हुई है, उसकी लोग बार-बार चर्चा कर रहे हैं । यह उचित नहीं है । इसलिए मैं सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सुझाव को माना ।

अब मैं क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनकी चर्चा संक्षेप में करना चाहता हूँ । उसके बाद मेरे और साथी बजट पर बोलेंगे । हमारे यहां सहरसा में 10 किलोवाट के एफ.एम. रेडियो की स्वीकृति हुई थी । उस समय अनुराग ठाकुर जी मंत्री थे । माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसका दिनांक 19.01.2024 को चेन्नय से शिलान्यास भी किया था, लेकिन वह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है । अन्य जगहों पर हवाई अड्डों का विकास हो रहा है । हम चाहते हैं कि सहरसा में भी एक हवाई अड्डा बने । सहरसा में भी भारत सरकार एक ?एम्स? के निर्माण की स्वीकृति दे ।? (व्यवधान)

सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

श्री दिनेश चंद्र यादव सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि मेरे बोलने का समय 15 मिनट था ।

HON. CHAIRPERSON: I think one more speaker is there from your Party.

श्री दिनेश चंद्र यादव **:** सभापति महोदय, समय बंटा हुआ है । एक गति शक्ति योजना के अंतर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र सहरसा में 185 करोड़ रुपये की लागत से सहरसा जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य का प्रस्ताव रेल मंत्रालय में आया है । मैं रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि उसके निर्माण की स्वीकृति दी जाए । सहरसा में लाइट ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्षों से वह काम थोड़ा सा करके छोड़ दिया गया । वह काम पूरा होना चाहिए । सहरसा से मानसी-मधेपुरा रेलखंड के दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का आदेश रेलवे बोर्ड से दिनांक 15.12.2023 को हो गया, लेकिन उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा है । सहरसा जंक्शन एवं मानसी जंक्शन के बाईपास के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का भी आदेश है, लेकिन वह काम भी अधूरा पड़ा हुआ है ।

सहरसा में ही मेरे लोक सभा क्षेत्र में पिछले बजट वर्ष 2023-24 में सहरसा-बैजनाथपुर स्टेशन के बीच समपार संख्या 104 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन उसका भी काम आगे बढ़ नहीं रहा है । मेरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है । वह कोसी का इलाका है । देश के अन्य जगहों से राजधानी और वंदे भारत गाड़ी चलती है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में पूर्व मध्य रेलवे का सहरसा जंक्शन काफी आय देने वाला स्टेशन है । सरकार की योजना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सहरसा जंक्शन से नई दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए । पंचगछिया एक ऐसा स्टेशन है, जहां फुट ओवरब्रिज नहीं है, उसका भी निर्माण होना चाहिए । हमारे संसदीय क्षेत्र में कोसी नदी पर घोघसम और कठडूमर घाट हैं, जहां प्रत्येक बाढ़ में कम से कम 25 लोग डूबकर मर जाते हैं । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कठडूमर घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए ।

सभापति महोदय, अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सांसद के वेतन, दैनिक भत्ता और पेंशन के लिए जब तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय जेटली जी थे, तब एक एक्ट बना था कि पांच साल के बाद महंगाई के इंडेक्स को देखकर सांसदों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन लंबा समय बीत गया है और सांसद का वेतन, भत्ते या पेंशन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी सांसद धनकुबेर नहीं हैं । यहां साधारण परिवार के लोग भी हैं, जिनको भारी परेशानी होती है । इसलिए वेतन बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here to speak on the Union Budget, the Union Territories of Jammu and Kashmir Budget, and the Demands for Grants for the Union Territories of Jammu and Kashmir 2024-25.

I congratulate the hon. Finance Minister on presenting her Sixth Budget. Every year we have a lot of expectations from her because India is no more insulated, it is a big global player over the last few decades. So, everything that impacts globally impacts our country as well. So, while we are talking about India which she also I think mentioned in her Budget Speech that what is happening globally, what is happening in Europe and South America is eventually going to affect our country as well. But I would like to make a small point before I get into the Union Budget. This is one more year after making Jammu and Kashmir a Union Territory against their wish. We are passing the Jammu and Kashmir Territory Budget and their Demands of Grants. Mr. Amit Shahji, the hon. Home Minister, had committed to this House that within a year they will hold elections and the Budget of the State will be discussed in their Assembly. So, I take this opportunity and request the Treasury Benches to keep their words and I hope next year elections are held in Jammu and Kashmir and they pass their own Budget in their own State. So, I think this is a very important point and it must be done because if parliamentary elections can be held in Jammu Kashmir, why are assembly elections not held? Anyway, you have committed to the Court that by September they are supposed to hold the elections this year. I do not know why we are passing the whole budget of 2024-25. Even if you are passing the budget, I request with full compassion and empathy for the people of Jammu and Kashmir, they deserve to make their own decisions for themselves.

The four engines of growth for a robust economy are investment, consumption, exports, and fiscal deficit. I do not want to be a prisoner of the past and history. Such a type of debate is going on from the Treasury Benches. Actually, I was disappointed with the Treasury Benches today. We used to listen to such wonderful speeches even if they were opponents and I miss most of them today. If we study the entire Budget for the last decade of this entire Government, they probably had very less to say in their Budget because the Treasury Benches only spoke about things which have happened 50 years ago. People have apologized and moved on. It has nothing to do with our economy and the future of this country or the growth of this country.

So, I want to speak only about the Budget today and I want to limit my entire speech to that. If you look at investments itself, now, how much investments have come into this country? What was the idea of reducing the corporate tax? They reduced the corporate tax under the pretext or maybe they thought it was a wonderful decision at their level that if they reduced the Corporate Tax, more investments will come. But, that is not reflecting in the numbers that the Government has given. The Gross Fixed Capital Formation of the percentage of GDP, if you look at it, in 2013-14, it was Rs. 30.70 lakh crore while if you look at 2023-24, it was Rs. 30.80 lakh crore. So, there is reduction in bringing GST. They have made a lot of effort. I am saying that governance is continuity. I am not taking away the credit that the Government has done nothing in last 10 years. Well, GST was the Congress's Bill which they implemented. We may have differences in the way they have implemented it but it was a good effort.

As far as digitalization is concerned, what they have done in banking, I am not taking away the credit from them. But at the same time, was it too little, too late to reduce corporate tax? That is the one reason why investments are not coming. I think, the Government needs to even introspect why the environment for investment is not as good as it should be.

As far as consumption is concerned, it is clearly not doing well, especially, the agrarian crisis and the rural economy. The data speaks for itself louder than you and I arguing about it. I am not running the Government down, but they need to accept that there is an agrarian crisis in this country.

A new word which I also have learned over the last few years is shrinkflation. Sir, if you go into FMGCs, you will notice that all these big FMGCs have started a new line which is actually called shrinkflation. It is shrinking, showing the inflation and shrinking. So, if the biscuit is for five rupees, there were five biscuits in it. Now there are four. The size of the biscuit and the packaging has become less. You look at any big company, be it Godrej and all, all the big boys, they have started this new concept of shrinkflation. This Government is denying the fact that there is a price rise. Where is this shrinkflation coming from? It is a completely new concept in Economics. But it is a marketing activity for all these big companies which directly impact jobs and the economy. It is a reflection when FMCGs do not do well. The data speaks for itself.

Now, I come to exports. When there was a global issue with China, everybody looked at it as China plus one. So, there was a great opportunity for India to

become the ?plus one?. Has India truly become Atma Nirbhar Bharat? Was it really Make in India? It was all wonderful sloganeering but has it really converted into jobs? So, if it is China plus one, what number are we globally? China plus one has become Mexico, China plus one has become Vietnam, China plus one has become Indonesia. We are at number four globally. So, we have not done as well as we should have done. And this was the sloganeering of this Government when they had a clear mandate. They had 300 MPs, and they could have done anything they wanted. So, what went wrong in ?Make in India?? I think we all need to introspect. There is just no point changing policies. Change is inevitable in any economy. We understand that.

Fourth is fiscal spending. Now, in fiscal spending, what is important is this. After the global issues and slowing down after the pandemic, India has recovered in the K shape. We will give credit. But who has really done well? The hon. Finance Minister constantly spoke about fiscal deficit. The FRBM Act was wonderful. Even though it came into force under the leadership of Atal Bihari Vajpayeeji, the UPA continued it because governance is continuity. It was a very good Act and we continued it. It was three per cent for the States, and we should not cross five per cent for the country.

Yesterday, the hon. Finance Minister said that the fiscal deficit is estimated at 4.9 per cent. Is it really going to stop at 4.9 per cent? My concern is, once the supplementary demands come, it will probably go up. I am not saying that my number is perfect. Neither I am a finance expert nor am I an economist. But from whatever little that I read, it will probably go up to 5.6 per cent. This is what the rough estimate is. Now, if the fiscal deficit goes up, what did we bring this law for? Should there be no good practices? Are the States also following the same? Just now, a gentleman from Andhra, Mr. Bharat spoke about it. He said that in Andhra, they do not have money and their Chief Minister who is such a learned man is going to take two months to find out where their fiscal deficit is. My State is not far away from that either, but I will come to that.

Sir, I want a clarification from this Government for my understanding and for the country to know. You are saying that you are at 4.9 per cent. Well, the data does not say so. If they really have reached 4.9 per cent, it is not because of the great policies of this Government. ? (*Interruptions*) They are saying 4.5 per cent but at whose cost? How are you reaching that ?4.5? number? This is not because of the policies of the then Modi Government and the present NDA Government, as they

call themselves. But the Modi Government has survived this whole thing not because of the great work they have done. It is the hard work that this nation and the people of this country have done, and the credit goes to the RBI. Actually, the entire house should thank the RBI and its Governor, Shri Shaktikanta Das, who gave them a dividend of Rs. 2 lakh crore. That is why they are at 4.9 per cent. Otherwise, they would not have been at 4.9 per cent. So, this is something very important. I think, we should really thank the RBI which has done a wonderful job and actually saved this Government. It is not their credit. Instead, it is the RBI's credit in terms of the good policies that they have managed to come here even at ?240?. Otherwise, they would have not reached this much.

Another question which my colleague Shri Dayanidhi Maran very rightly put up is about the census. I do not see anything about the census in this entire Budget. I want to ask them two-three very pointed questions. I am not criticizing them; I am just asking them.

Sir, they talked about women, how much more they want to do for women, and how they have got the Women?s Reservation Bill which is still not implemented. But unless you do the census, how are you going to implement the Bill is my first question.

Second is about delimitation. Our constituencies are huge with 23 to 24 lakh voters. When I started as an MP, there were 14 to15 lakhs voters. Now, the number has reached to 23 lakh and the money we are getting is Rs. 5 crore. In Maharashtra, one MLA gets Rs. 5 crore per year. So, if I have six MLAs, the amount is actually equivalent to Rs. 30 crore. ? (*Interruptions*) We are getting Rs. 5 crore per MLA. So, unless you do this delimitation, how are we going to manage this? Is the Government thinking of doing this and raising funding for this?

The other point is with regard to MPLADS. Either you increase the fund under that or stop that. I would request the Government to scrap it either or make them fair because what will a Member of Parliament do with that? An MLA gets Rs.5 crore and I am also getting Rs.5 crore. ….*(Interruptions)* What are we achieving? ….*(Interruptions)* Some hon. Members are saying that MLAs get Rs.15 crore. ….*(Interruptions)* So, why do not you increase it? That is one very important question. What about the fiscal deficit? I want a clear answer from this Government. What about the caste census? We definitely want to ask the Government.

Sir, they talk about GST. Whenever you ask anything from this Government with regard to GST, they say that the GST Council will decide. I want to ask two very small questions from the hon. Finance Minister. The Income-Tax Department has unearthed a huge fake money changing scam. There are companies which have input tax credit. Now, input tax credit scam under the Goods and Services Tax is some thousands of crores of rupees scam. What has this Government done to make sure that such scams do not happen in future? What are the checks and balances? Anything you ask from this Government, they will say, ?Go to GST Council?. Now, I have a problem in my State. You may not have that problem in your State because I do not know what your Finance Minister does. But unfortunately, in Maharashtra, our Finance Minister, never attends the GST Council meeting. This is what data says. So, my State is always unheard. What is the Plan-B for it, if a Finance Minister does not attend GST Council meetings? Maharashtra is never heard. So, I want some justice for that, and want a solution for that. Besides the Finance Minister, nobody can speak in that meeting. *....(Interruptions)*

He is your ally, you will have to tell in that case. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

....(Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: So, that is one very important thing.

Sir, the other very important scheme of the Government is PLI scheme. I want to ask one very pointed question because this is really important. My hon. colleague, Shri Dayanidhi Maran talked about unemployment. I think the whole thrust of this Government was on skilling and employment. They started a very good scheme of Production Linked Incentive. I am not taking away from the intention of this Government. Shri Raghuram Rajan has said that there was some semiconductor company in Gujarat to which they have given an incentive of Rs.2.3 crore. This is the kind of money which we have paid them as an incentive. *....(Interruptions)* That is the level of money that has been given with no outcome. Not only that, one of the Cabinet Ministers has agreed with that figure. I do not know who he is, and I do not want to name anybody. But he said that the Government has given Rs.2.31 crore per employee for that particular unit in Gujarat. Is this the PLI scheme? Is this what you thought of giving in the Government? Is this how you are going to create jobs?

Now, the new one is Employment Linked Incentive scheme. So, your PLI has already failed, and this ELI is also going to fail. You have already failed even in fiscal

deficit. Thanks to the RBI. So, where is really this economy going? Just by making all these announcements, and giving all these schemes, there is nothing that you are quantifying in this economy. The numbers are not helping for what they are saying in these various schemes.

They are very proud of feeding 80 crore people. I am also very happy if they are feeding 80 crore people. But how come when they keep saying about this multi-dimensional poverty index, every time they are saying that they are getting people out of poverty? How come you are still feeding 80 crore people after 10 years? I mean, it is the same number. They are so proud to say for 10 years that they are feeding them. I am very happy if they are feeding them. Then, how come are they talking about multi-dimensional poverty index? What is this for?

They are doing nothing for EPS-95. So much they talked about pension. EPS-95 was a commitment this Government made. I mean, may his soul rest in peace because Arun ji, unfortunately, is no more with us, but Arun ji had mentioned it that EPS-95 is something we commit to. This Government has not done it.

Then, I come to the agrarian crisis. The hon. Finance Minister, unfortunately, is not here. Shri Biplab Deb is here. He was talking about milk production, wheat production. This is the data from 10 years.

There is no great innovation. What have they done to milk prices and casein? What have they done by banning the exports of onions? They have lost two seats in Maharashtra only because of banning exports of onions? Their allies are begging them to allow onion export, but they have done nothing. Even after losing two or three seats and after doing miserably in the elections, they have still not done it. It is fine because it helps us in the State. Once we form the Government, we will make sure that agrarian issues are addressed and farmers are respected not just by hands-me-down approach and *revdis*, which is their favourite word, but by respectfully giving MSPs to the farmers for their produce which they produce with their hard work.

As a percentage of GDP, the increase for agriculture in this year?s Budget is not even one per cent over the last ten years. In agriculture, it was 3.52 per cent and now, it has only become 4.2 per cent. In health, from 1.15 per cent of the GDP, it has gone to 1.85 per cent. In education, 1.8 per cent has only become 3 per cent. For infrastructure, which is their favourite, they like only big-ticket projects even in Maharashtra. They only work for infrastructure and you know, obviously, why.

Then, social justice is only 1.5 per cent, which is not a great thing. I just need to ask this Government one thing. In her reply, the hon. Finance Minister should tell us what the plan of this Government is.

I am as concerned as Andhra Pradesh is. They have just come to power and they are suffering as they are saying. The same thing is there in Maharashtra. Every time, there is no fiscal management in that State. Then, why did we pass that Bill? If there is no good discipline of finances, in this country unfortunately, I say this with great pain, there will be a complete economic crisis. We do not want to go our neighbour?s way. We want to be firm and committed to be a robust country with good growth with very good fiscal management and a strict one.

So, I urge this Government to kindly reply to all these questions and reassure us. I have no problem with what they have given to Andhra Pradesh and Bihar, but they should not give us a step-motherly treatment because of what the voters have decided. This is mandated by our Constitution that elections have to be fair and just, and we are living in a democracy.

Thank you.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman Sir for giving me an opportunity to add my words to the Indian National Congress?s view on the Union Budget presented by the hon. Finance Minister.

Mr. Chairman, Sir, this under-whelming Budget has been a woefully missed opportunity for, after all, this was the Government?s chance to prove to the citizens of India, after the colossal setback the BJP suffered in the recently concluded general election, that the Prime Minister and the Finance Minister have actually listened to the concerns of the people. Once again, they have let the people of India down.

The Budget is, in many ways, an emblem of this Government?s economic mismanagement and financial recklessness made all the more worse by its divisive policies. This Budget makes it abundantly clear that the BJP has run out of ideas. Rather than being a vision statement of the economic future of the country, this Budget is an illustration, as has been pointed out by many, of their politics. Their priorities chiefly revolve around appeasing their two regional allies, forgetting there are 26 other States and eight Union Territories whose people have nothing to be happy about. But even out of those two, the people of Andhra Pradesh have less reason to be happy at the supposed allocations made to their State in the Budget.

The Budget only commits to arranging Rs. 15,000 crore towards the development of Amravati. This is not an allocation. It merely entails the facilitation of loans by the Centre from multilateral development organisations to your State. Instead of amounting to a formal financial support from the Centre, this commitment would only add to Andhra Pradesh?s existing debt burden. The other promises made, of course, are the very ones broken in the NDA?s first term. One only hopes that another No Confidence Motion will not again have to follow!

The four other States which have received the Government support for natural calamities are all NDA-ruled States ? Bihar, Assam, Sikkim and Uttarakhand. On the other hand, INDIA alliance-States find themselves cast out and ignored. Indeed, Karnataka, Tamil Nadu as well as my home State of Kerala have, time and again, sought funds for natural calamities from cyclones to rapid coastal erosions, but they have got none. Bihar received Rs. 26,000 crore for its highways, but Karnataka had sought and got nothing for the critical road infrastructure projects in Bengaluru.

For the Government of India, it seems some States are more equal than others. Now, this inclination to bias is not limited to State allocations either. If one looks at the specific concessions on basic customs duty given to three cancer drugs, it turns out they are all made by the same pharmaceutical company. Why were various other costly life saving drugs being imported into the country overlooked for this exemption?

On that subject, Mr. Chairman, I find it worrying that the Government has completely disregarded the augmentation of existing healthcare infrastructure. In my own State of Kerala, many were hoping to hear a mention of the long proposed AIIMS in Kerala. Alas, even with the presence of two Ministers of State from Kerala, the Government has continued to disappoint us.

Bias, Mr. Chairman, takes many forms. This Budget fails to consider that in our country today private investment is sputtering; consumption growth is slow; real rural wages are plummeting; overall wages are in decline; and the demand for investment credit has collapsed. As a result, returns on labour are low and so are returns on debt capital. Only equity and private profits are booming. The situation is perverse. Luxury watches, premium cars, and business class travel are reporting huge increases in sales and net profits but the purchases of ordinary people have plunged. बनियान, गंजी खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं हैं । But SUV sales are rising

and small car and two-wheeler sales are tanking. It is starkly clear why inequality in India today is said to be worst than during the British *raj*.

Even when all the flaws that beset the developing country, ill health, poor education, abysmal housing, poor sanitation, malnutrition, infant mortality, all linger in India, a multibillionaire can preside over an obscenely extravagant wedding reportedly spending Rs. 5,000 crore while in the sprawling slums in the same city most Indians struggle to survive on less than Rs. 200 a day. This Government does not frame its policies with those Rs. 200-a-day people in mind. Instead, it gives tax breaks to favoured capitalists and corporates in the name of boosting private investment. In fact, this Government?s corporate tax cuts have meant a revenue loss over the last five years of an astronomical Rs. 8.7 lakh crore foregone by the Government. Who has this benefit? Can you tell us where the jobs are, hon. Finance Minister? Where is the capital investment?

While no one expects it any better from this Government, it is extraordinary that in India individuals pay more direct tax than corporates. Budgeted figures of higher direct taxes from individuals and lower from corporates will surprise voters and should shame the Government. Perhaps, they are ashamed since they have stopped even releasing detailed GST revenue collection data allegedly because their GST collections are so high that they have not revealed the extent to which the *aam aadmi* is subsidising this Government through regular purchases that they pay GST on while the Government subsidises a favoured few. But once again, concealing data is a speciality of this Government. Remember the PM CARES Fund.

During the UPA years, Mr. Chairman, the personal income tax was 21 per cent of total tax collection; corporate tax was 35 per cent. Today, the share of corporate taxes out of total tax collection is at the lowest level ever at just 26 per cent while the share of personal income tax in total tax collections has increased to 28 per cent. While this is going on, private investment has nosedived from a peak of 35 per cent of GDP under Dr. Manmohan Singh to below 29 per cent during this Government?s 10 years of BJP rule. So, the corporate tax cut has put over Rs. 8.7 lakh crore on the pockets of billionaires while the middle-class and the *aam aadmi* continue to bear the weight of heavy taxation.

In contrast, if the money were to be put into the hands of ordinary people, they would spend it in their local communities and on their own essentials, and so stimulate the economy. It would be a matter of spending on *roti, kapda, aur makaan*, rather than on the pockets of those who happen to support the BJP. So, I

want to point out to the hon. Finance Minister ? in her absence, of course ? that one-third of our populations lives under Rs. 100 a day. And if we are to have a Budget that addresses their needs, then we must pay attention to those crucial sectors of our economy that are conspicuous in their absence from this Budget.

My colleague, Kumari Selja has already addressed the issues of emissions, farmers? welfare and agriculture, and in the interest of time, I would not touch them. But consider, for instance the word ?health?, which is mentioned only four times in the speech. Indeed, Madam Minister did not even discuss healthcare at length at a time in India when 55 million of our most vulnerable citizens are annually cast below the poverty line because of having to spend on healthcare. This Budget offers nothing tangible to this vital sector.

Was it really so long ago that COVID-19 rampaged across the world, wreaking havoc and exposing our massively inadequate and ineffective healthcare sector? Yes, if one were to look at the Budget, it would seem that the pandemic has been forgotten. The allocations for the Ministry of Health and Family Welfare have decreased as a share of the overall expenditure from 2.16 per cent in 2019 to 1.9 per cent in the Budget. At the same time, the Ministry of Ayush had an allocation nearly doubling.

The fact is that India is just not spending enough on health. Brazil, Russia, China and South Africa, the other BRICS countries spend roughly 14 to 15 times more than us. Until recently, even Bhutan, Nepal and Maldives were outspending us. This year, the Budget Outlay for health has seen a miniscule rise, yet far from the aspiration of five per cent of the GDP. The Modi Government's health expenditure, as a proportion of GDP, remains stagnant and we are even distant from spending the minimum 2.5 per cent that was outlined by their Governments in the National Health Policy.

I must address the so-called ?missing middle?. According to NITI Aayog, these are the people who have no health insurance cover and are too well-off to be eligible for the Ayushman Bharat Yojana. When flagged in a 2021 NITI Aayog Report, the Government said that they would take notice of this and yet here we are in 2024 with no health solution at all for this middle-class. This is highly irresponsible and reflective of our Government's inability to afford something as basic as healthcare insurance cover to some of our neediest citizens.

Offering health insurance to employees at negotiated rates; reducing GST on health insurance premiums; offering such tax benefits as increased exemption limits under Section 80D of Income Tax Act could all have been ideas for the Finance Minister to make health insurance far more affordable and accessible, especially for the middle section, the ?missing middle? of our population which is growing according to the Government. But she has completely overlooked them.

The truth is that even when it comes to a sector as indispensable as public healthcare, the mantra of the BJP as with everything else has been re-brand, not revamp. So, we have had India's health and wellness centres, which need more funds and more staff to provide cost-effective treatment to ordinary Indians, but regardless of their faith, being renamed Ayushman Arogya Mandirs casting a secular institution of a secular nation into an overtly religious mode. But, perhaps, a certain Constituency in Uttar Pradesh should have taught the BJP to never again to exploit a Mandir for scoring political goals.

Re-branding is what this Government has done for the last 10 years. We have been calling it a name-changing Government and not a game-changing Government as you know. But honestly, hearing the inflated claims of the Ruling Party after this weak Budget and all the TV shows that I had to appear on yesterday, I am reminded of a garage mechanic saying to the owner of a car ?हम आपकी कार के ब्रेक्स तो ठीक नहीं कर सके, लेकिन हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है ।? That is what the Government is doing. The brakes of the Indian economy have fallen out because the Government?s horn keeps getting louder.

Let us look at the targets announced for Make in India. In its 10 years of existence and under-achievements, this Government thinks honestly that rhetoric is a substitute for action. But I may move to another sector of the economy, which the Budget barely pays any attention to, and that is education. It is immensely critical to employment generation. For all the BJPs talk of upskilling youth and equipping them with the tools that they need to procure jobs in today?s intensely competitive job market, there is no mention in the Budget speech of primary or higher education.

We have a staggering 35 lakh youngsters who dropped out of school in the last academic year for which there are records. And this is not just an indication of economic failure by the Government of kids having to join the informal workforce to support their families. But it is the future of India stepping away from the path of knowledge. It is deeply unfortunate. While leaving school may not be in these

students? hands, getting them back to school is certainly in the Government?s hands. So, it is a shame that access to quality and compulsory education has been wholly overlooked in this Budget.

Education has been allocated a miserly Rs. 1.2 lakh crore, which is a seven per cent decrease from the revised estimated allocation of 2023-24. More alarming is the fact that the allocation for the Department of School Education and Literacy as a share of the total budget outlay reduced from 3.16 per cent in 2013-14, the last year that we were in Government when the UPA was there, to just 1.53 per cent in 2024-25. And the combined allocations for both the Departments have declined from 4.7 per cent as a share of the total budget expenditure in our last year to 2.53 per cent in your last year. Now, as a share of GDP, it is even worse. It is a horrifically low 0.36 per cent. The Government's own New Education Policy of 2020 recommends that the education budget should be six per cent of GDP. Now, Mr. Chairman, if this Modi Government cannot even meet the goals that they set for themselves, then what can we expect of them?

In continuance of their onslaught in education, by the way, the Budget has slashed the funding for the UGC by 60 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, my Party has allocated 20 minutes to me. So, I have another six or seven minutes to go.

HON. CHAIRPERSON: You have 15 members from your Party.

DR. SHASHI THAROOR: No, Sir, I have been told to take 20 minutes, and I have prepared accordingly, please.

But they have slashed the UGC budget by 60 per cent, and fears do abound now that this would reduce the UGC to purely a regulatory agency, encourage universities to start more self-financing courses, creating an additional financial burden on students, and will also make more universities dependent on loans from the Higher Education Financing Agency ? a complete transformation in our education environment. On top of that, in 2019, the Government introduced four per cent education and health cess, which is not a sustainable source of revenue for the Government, but this cess has financed 70 per cent of the total educational expenditure after 2015. So, that is another source of worry.

There is little to cheer on health and education, but should we welcome the Government's belated recognition of the worst-ever employment crisis in our country in history by their borrowing the Congress Party's proposed apprenticeship scheme and renaming it? No. First, the exaggerated claims of the Government that it added 125 million jobs in its 10 years, including 47 million last year, are completely fake. They include unpaid labour, and even one hour's work a week has been counted as a job. Second, they have diluted our scheme. We had proposed an apprenticeship, which would lead to jobs. They have reduced that to an internship, which is only an assistance. They have only restricted it to 500 top companies. We had it open-ended. We offered Rs. 1 lakh per person, they are offering only Rs. 5,000 a month. And on top of that, they are taking 10 per cent from CSR funds. The CSR funds are meant for social welfare benefits and not for the companies to spend on themselves.

You have the fine print in the annexure that says that the participation of these companies is voluntary. I do not know how they are going to define the 500 top companies and how these companies would voluntarily shoulder the Government's burden of creating an economy where there are enough jobs.

The precedents are not encouraging. Can the Government tell us what came off their 10 years of skill development efforts? How many of those trained have been placed in real jobs? What about the schemes for women? Why is the participation of female labour force today at a record low of 28 per cent? सभापति जी, हारने के बाद बीजेपी हमारे सुझाव मानने लगी । यह तो अच्छी बात है, अगर इससे भारत की भलाई हो जाए । But it is amusing to me that the BJP had to lose its majority in Parliament before they became receptive to effective suggestions from the Opposition. Let me immodestly point out that it was I who in the Lok Sabha on 10th March, 2016, asked the late Finance Minister, Shri Arun Jaitley, to reduce or remove angel tax in order to strengthen the startup ecosystem. I am glad to see that eight years later, a Finance Minister has heeded my words and abolished it. चलिए, ?देर आए, दुरुस्त आए ।?

I have to say that the Finance Minister's rosy claims on FDI are belied by facts. The FDI as a ratio of GDP has, in fact, collapsed from an average two per cent of GDP to 0.5 per cent of GDP last year, the lowest in a decade. One big reason for stunted private investment is the heightened risk perception of the Indian economy. The foreign companies are actually pulling money out of our country. Some USD 44.4 billion have been pulled out in 2023-24. And actual FDI, that is investments minus what they take out, has fallen to USD 26 billion, which is a 37 per cent drop

according to RBI data, and the lowest number since 2006-07 when the UPA was in power. Similarly, the Government's disservice of removing indexation benefits under the long-term capital gains tax is unforgivable because countless members of the middle-class worked tirelessly for years to be able to afford a house or make an investment in real estate to secure a *pakka* house for their families. And it is no longer a viable investment because you no longer can index the appreciation of that value to inflation and you will pay a much larger sum as a result. ?(*Interruptions*) A couple of minutes more, Sir. In this example, we are looking at the Government taking more taxes out of the pockets of the middle-class, out of people who might even end up losing money in the course of buying and selling a property, which may be the only one that they can afford. So the real worry with all of this is that you are going to see a strong resurgence of cash transactions in purchases of property. It will bring the real estate economy back into the deadly pool of black money for so much for *na khaunga na khaane dunga*.

I must say, Sir, the Government keeps boasting of capex and infrastructure, but the fact is that - and it even says it will create jobs in the tourism sector because of this - but the truth is, how can you create jobs or strengthen tourism when your refusal to reduce GST in hotels has made India amongst the costliest destinations? ?(*Interruptions*)

I am just concluding, Sir. Or, how does it indeed boost tourism when everything on the infrastructure side that we are seeing, is collapsing? The roof in Terminal 1 in Delhi has collapsed. In Rajkot in Jabalpur, the canopies have collapsed. Five bridges have fallen in Bihar last month, and Mumbai's Trans Harbour Link, which was inaugurated by the PM in January this year, has developed cracks. So what the Finance Minister ought to do is allocate resources to fix our infrastructure rather than boasting about the tourists it will attract.

I am going to wrap up, Sir, with just one sad comment further before I conclude, which is about the accidents and the failure of the Government to implement its own *kavach* that it has been talking about. We have had grisly and ghastly railway accidents, but the *kavach* system has only utilized less than half of the money allotted to it in the last Budget and only one per cent of the total amount of railway lines that are supposed to have been equipped with *kavach* have been equipped. So, this is pretty shameful and the Budget has glossed over it.

Nor did the Finance Minister mention MGNREGA which has been mentioned by others, so I can just say in one sentence that demand keeps going up, but the Modi

Government keeps reducing its allocations to this, and the allocation they have requested now is far short of the amounts requested and required to meet the demands. On top of that, they have deleted job cards. 267 per cent of more job cards have been deleted this year, and the new Aadhaar-based payment system has left eight million active workers ineligible for payment. This is supposed to be something to help the rural poor. It is actually hurting them,

Sir, let me conclude by saying that this Budget is a do-nothing, claim-to-do-everything exercise. No matter how much the Government ratchets up the mythic vision of a Viksit Bharat and its rhetoric, this is not a Budget for a Viksit Bharat. It is a motley collection of schemes without an analytical framework or a coherent spending plan, and no pathway to achieve the boasts and rhetoric of either Amrit Kaal or Viksit Bharat. The Government is selling us a penthouse in a building whose foundations are shaky, whose canopy has collapsed, whose lift shaft is yet to be installed, and whose workers are starving.

The Budget lacks originality, ambition and strategy. We get no answers to the employment puzzle. We get no solutions to education, health, and we do not engage with any of the crises of investment I have outlined today.

The Budget that India needs and India deserves is much more than a statement of solidarity with the ruling party's political allies.

Thank you, Mr. Chairman. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairperson. I will be speaking for the first time after being elected to the 18th Lok Sabha. It is my pleasure and I express my gratitude to my party, Bharatiya Janata Party and my leader *Yashasvi Pradhan Mantri* Narendra Modi ji for being entrusted to participate in the deliberation on the Budget 2024-25.

This budget is for continuation of empowerment of the newly emerged neo middle-class. The budget sans poetry, but is filled with political pragmatism. This is a Budget that will take the country?s villages, poor and the farmers on the path of prosperity. The Budget exercise is a complex intertwining of political-economy compulsions with multiple policy trade-offs required to achieve often conflicting economic objectives, while constrained by limited revenues. Despite these difficulties, a hallmark of the budgets of the past few years has been stability and predictability in approach and outcomes. Key to this continuity is furthering progress on the path of fiscal consolidation.

The fiscal deficit has been steadily reduced from 9.2 per cent of the GDP in the FY 2021 to a budgeted 5.1 per cent for the FY 2025 in the Interim Budget. Now it is estimated that the fiscal deficit would be 4.9 per cent of GDP. The earlier FY 2024 fiscal deficit has been 5.6 per cent. This demonstrates that the Indian economy has recovered strongly from the pandemic, but sustaining growth to attain Viksit Bharat?s goal will require sustained interventions and dealing with several emerging economic and policy challenges. India has achieved higher growth in the post-pandemic period without compromising on financial stability. This year?s Budget is remarkably different from that of the previous 10 budgets.

When the Interim Budget was presented last February, 2024 I had said sitting that side, ?The Government is full of self-confidence to form the next Government and thereby looking at the long-term picture?. This Budget has specifically outlined the developmental programmes in the Eastern States of the country. The hon. Prime Minister?s vision of Purvodaya has been propounded in this year?s Budget mentioning Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. There was a time in not so distant past when this part of the country was feeding the whole of India. It was rich because of its trade and commerce, because of its rich soil, because of the production of food grains. People thronged to that part for employment as Odisha is rich in minerals, with abundant water and forest cover. Andhra Pradesh and Odisha have a long coastline with vibrant ports. Jharkhand is a mineral-rich State with adequate human resources. Bihar has a vast stretch of plains for cultivation and able human resources. West Bengal developed its agriculture and has a vigorous MSME sector engaging a large number of youths. Yet, I would say that this part of the country was systematically pauperised during the last 50 or 60 years until there was an intervention of the Union Government led by Modi ji.

Today, we find policy intervention and the greater focus is on the eastern States. The hon. Prime Minister has repeatedly said during the last 10 years that the country cannot become fully Viksit if a region is left unattended and underdeveloped. I congratulate the Government and the Finance Minister for bringing the eastern States into the focus of development. Investment on infrastructure will facilitate investment and investment will generate employment which will ultimately help in the economic growth of the country.

Hon. Chairperson, Sir, here, I would like to mention that there have been some criticisms in my State by the Opposition that Odisha did not find place in the

Finance Minister?s Budget Speech. While mentioning about ?Purvodaya?, the Finance Minister has categorically stated and I quote:

?We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh.?

Here is the actual issue that is there and the plan that is there before this Government. I quote:

?This will actually cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Viksit Bharat.?

These five States will be the engine of development of our nation. And today, I may mention here that in the other House there was a Question from an Opposition Member relating to Odisha. He was asking, ?What are you going to do about the Coastal Express Highway that was supposed to be built? What are you going to do relating to the capital region highway or the roadway that is going to begin? And there is a specific answer by the Government in the other House. I believe in tomorrow?s newspaper and in today?s media, all that will be flashed.

Now, I come to the Polavaram issue on which there were some criticisms also. Categorically, I had stated, being a Member in the 16th Lok Sabha, that the Government of Odisha and the people of Odisha are not against the Polavaram project *per se*. Our concern was relating to the inundation of backwaters after the commencement of the Polavaram project. It is a national project. Adequate funding is now going to be provided for the Polavaram project. But the concern of Odisha is that adequate measures need to be taken and the Chief Minister of Odisha and the Chief Minister of Andhra Pradesh are going to sit together and settle that matter. It is not a political issue at all. Whatever human intervention is necessary or whatever Government intervention is necessary, that will be done by the respective two Governments together sitting there and finding out the solution.

My third point for deliberation here is this. How does we focus on forging a new economic strategy? I believe the Government will take note of it -- what I am going to mention just now -- which is now crucial to counter the challenge to investment and growth by China?s muscular industrial policy. Amid rapidly rising trade deficit with China, despite efforts to curb imports and investment in the backdrop of Galwan clash in 2020, some are advocating to attract investment from Chinese

companies to boost import. We know that a number of countries such as Mexico, Vietnam, Taiwan and Korea are benefitting from ?China Plus One? strategy pursued by western firms. The question for us is this. If we adopt this policy, will it result in a total movement of trading relations away from China?

<u>18.00 hrs</u>

Should we import goods from China or import capital from China? That is the question. The Economic Survey has stated this. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is already 6 ?o? clock. Since there is a long list of Members from various parties to speak, if the House agrees, we will extend the time of the House up to 8 ?o? clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Ok Sir, we agree with you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: To boost Indian manufacturing, plug India into the global supply chain, it is inevitable that India plugs itself into the China supply chain. Whether we do so by relying solely on imports or partially through Chinese investment is a choice that India has to make. The economic survey has posed this question before the nation and before the Parliament and the Parliament has to take a decision and to a certain extent, the Finance Minister has mentioned it in her speech not in such clear terms but a mention is there.

<u>18.01 hrs</u> (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

So, what is the decision of the Government I would like to understand. There are two things prevalent today. One is this China plus one policy. The other is ABC which means anybody other than China. Why can we not adopt the second option? I believe there is a need to strike a balance between importing goods and FDI from China. Data shows that foreign investment from China has not been robust although Chinese goods has been persistent and has been rising for close to two decades. Out of the two choices to benefit from the China plus one strategy, it can integrate into China supply chain or promote FDI from China. Amongst these choices, focussing on FDI from China seems more promising for boosting India?s export. Moreover, choosing FDI to benefit from the China plus one approach appears more advantageous than relying on trade.

India has huge ambition in photo-voltaic semiconductor electric vehicles and pharma industries. India has robust capacity in steel and yet sees significant imports of cheap Chinese steel. Why are we importing Chinese steel that are

flooding our market? China is a dominant supplier in India including pharma. Since roads, ports and rail tracks are not tradeable, we make it here but the rest are falling prey to Chinese industrial policy. If current needs are met by our imports, that would rule out investment and depress overall economic growth in our country. To thwart industrial infanticide at the hands of the Chinese State, Indian industry must be spared the price pressure of Chinese imports.

The fourth point that I would like to mention is this. The country is at a critical juncture grappling with significant economic challenges despite being an accounting document. The Budget is more than just a ledger of expenditure and revenue. It is a powerful signal of the Government?s priorities and policy directions and an estimated 135 million Indians emerged from multidimensional poverty between 2015-16 and 2019-20. This trend is primarily driven by improvements in rural India with the most major gains in States such as Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha and Rajasthan.

India today is on track to achieve the Sustainable Development Goal of cutting multidimensional poverty by at least half by 2030. By each of the nine tracks highlighted in the Budget, it has many areas to appreciate. The focus on employment generation will be a big boost and provide the thrust for the growth of the economy. The support for manufacturing sector, a package for employment generation and the skilling and upskilling for 4.1 crore youth across sectors are some of the key highlights of the Budget.

This, coupled with the allocation of Rs.1.48 lakh crore for education and employment skilling, underscores the Government?s commitment to harnessing India?s demographic dividend.

The plan to upscale 1,000 industrial training institutes is a pivotal step towards enhancing the skill sets of our future workforce. I am particularly heartened by the allocation of over Rs.3 lakh crore for women-led development initiatives including provisions for accommodation through working women?s hostels which will greatly benefit women workforce, especially those who are in the manufacturing industries.

The Indian economy?s stunning revival from COVID-19 and its emergence as the world?s fastest growing major economy is partially attributed to an infrastructural revival spurred by Government?s spending in the past few years.

The CAPEX budget for the financial year 2025 has been retained at Rs.11.1 lakh crore or 3.4 per cent of GDP. A massive expansion in urban housing at an investment of Rs.10 lakh crore and rural roads programmes with Rs.26,000 crore is a big infra push.

Employment generation is a real bottom line for Indian industries. Indian companies in private sector should pick up the job creation baton from the Government and invest in new manufacturing capacities so that the country can complete its journey to Vikshit Bharat by 2047. Providing employment is not the job of the Government only. The private sector also has to join in and play their roles.

It seems that the question in most of our minds has been whether India?s new Government would work as Modi 3.0, that is, the third term of the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji or an NDA 2.0. Earlier, there was a coalition Government led by Shri Atal Bihari Bajpayee ji and this is the second coalition Government which Modi ji is leading.

I am of the opinion that barring a few sops for allies, its policy priorities suggest no change in the Government?s approach. The approach which was there in the Interim Budget has also been magnified in the present Budget that we have a long-term goal to achieve and we have to reach 2027 as Vikshit Bharat.

This Budget is unruffled. As many Opposition Members have already spoken, this Government or the Party in power is totally ruffled because of the election result. This Government is totally unruffled and is continuing in its long-term approach. We are not ruffled by 2024 election result.

With these words, I support the Budget in full term. Thank you.

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिव सेना पार्टी की तरफ से बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

मैं सबसे पहले माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, वह तीन बार चुनकर आए हैं और प्रधान मंत्री बने हैं । मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, उन्होंने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है । वह पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने सात बार लगातार बजट पेश किया है । मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे जी का भी आभार व्यक्त करता हूं । मैं मुम्बई नार्थ-वैस्ट कांस्टीटुएंसी से चुनकर आया हूं, मैं वहां की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुनकर इस सदन में भेजा ।

माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने गरीबों के सुख-दुख, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिटीज़ के डेवलमेंट का बजट पेश किया । उसी प्रकार से हमारे महायुति के माध्यम से मुम्बई में विकास हो रहा है । मैं महायुति को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने वधावन पोर्ट का, समृद्धि महामार्ग का और मुम्बई में अटल सेतु जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

तैयार किया । मेरा एक सौभाग्य है कि मुम्बई शहर होने के नाते मैं वहां का चार बार काउंसलर, तीन बार एमएलए और आठवीं बार लोक सभा में आया हूं । यह मेरा भाग्य है कि मैं अपने पक्ष की तरफ से यहां आया हूं । जब हम इन सभी समस्याओं को इलेक्शन के टाइम देखते हैं, लोगों के पास जाते हैं तो उनकी समस्या केवल बेसिक चीज की होती है । वही बेसिक चीज उन्हें चाहिए । उसी मूलभूत सुविधा के माध्यम से हम काउंसलर का इलेक्शन लड़े, एमएलए का इलेक्शन लड़े और एमपी का इलेक्शन लड़े । हम उनको बेसिक एमेनिटीज देना चाहते हैं और वही लोग मांगते हैं । उसी प्रकार से इस बजट के माध्यम से सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी । यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट है । माननीय वित्त मंत्री जी ने विकसित भारत के लिए सरकार के 9 प्रॉयोरिटी एरियाज बताए हैं, जिसमें शहर का विकास प्रगति से हो जाएगा ।

सभापति महोदय, मैं एक शहर से प्रतिनिधित्व करता हूं । वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारत को 840 बिलियन डॉलर का निवेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा । आज शहरी भाग देश के जीडीपी में 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं । मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है ।

सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय क्रमश: 32.0 लाख करोड़ रुपये और 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है । निवल कर प्राप्ति कर 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है । राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है । ये बताते हैं कि यह अलग है । लेकिन, ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड यह 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है । वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल निवल बाजार उधारी क्रमश: 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.60 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है । दोनों ही वर्ष 2023-24 की तुलना में कम होंगे ।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इस बजट में शहर का डेवलपमेंट करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास की जरूरत का समाधान किया जाएगा । इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी । किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है ।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुए हैं, उसके बाद शहरों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था । शहरों के अंदर औद्योगिकरण हुआ और उस औद्योगिकरण के माध्यम से लोग नौकरी करने के लिए और अन्य काम करने के लिए शहरों में आने लगे । काम करने के लिए शहरों में आने के बाद उन्हें रहने की प्रॉब्लम होने लगी । इसके कारण उनके यहां झोपड़पट्टियां बनने लगी और घर बनने लगे । उसी तरह से मुम्बई शहर भी महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की औद्योगिक राजधानी भी है । वहां भी उसी प्रकार से वर्ष 1960 के बाद औद्योगिकरण हुआ । वहां औद्योगिकरण के माध्यम से जहां मिल बनी, इंडस्ट्री बनी तो खेड़े गाँव से लोग मुम्बई आने लगे । मुम्बई शहर पहले छोटा था, लेकिन उसके बाद लोग पूर्व नगर और पश्चिम नगर के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी बनाने लगे । उसके माध्यम से मुम्बई शहर मुम्बई पश्चिम नगर और मुम्बई पूर्व नगर बन गया । इसी तरह उनको देखते हुए शिवसेना प्रमुख माननीय बालासाहेब ठाकरे जी ने सन् 1995 में गरीब लोगों के लिए अच्छे घर बनाने की कल्पना की थी, जिसका उद्देश्य आज सफल होने जा रहा है । मुझे मालूम है, हमारे यहां एमएचएडीए है, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड है । झोपड़-पट्टियों के डेवलपमेंट के लिए एसआरडी बने, उनके लिए एसआरए बने, मगर वहां जैसा विकास होना चाहिए था, वैसा विकास नहीं हुआ । अब जब 10,00,000 करोड़ रुपये की निधि के माध्यम से शहरों का विकास होगा, तो शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपना घर ले सकते हैं । उसी तरह से विकास होने जा रहा है, जिसके कारण झोपड़-पट्टियां कम हो जाएंगी । जो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, वे अफोर्डेबल घर के माध्यम से घर ले सकेंगे । हम भाड़े में

रहने वाले लोगों के लिए भी घर बनाने वाले हैं, तब झोपड़-पट्टियां कम हो जाएंगी । सब घर कानूनी होंगे, वहां सबको सुविधाएं मिलेंगी । इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने लोगों को बेहतर जीवन देने का प्रयास किया है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे । इन परियोजनाओं में उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी परिकल्पना की जाएगी । जब बारिश होती है, जब हमारे शहर बने थे, तब स्ट्रक्चरली कुछ तय नहीं था । जैसे लोग आते गए, भवन बनते गए, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था । उसको स्ट्रक्चरल सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है । हम लोग ?प्रधानमंत्री आवास योजना? के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, अभी बारिश का मौसम चल रहा है । हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में जल भराव का मुद्दा हर वर्ष उठता है । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह घोषणा की है कि राज्य सरकारों और मल्टी लैटरल डेवलेपमेंट बैंक्स के साथ मिलकर केन्द्र सरकार वॉटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 100 बड़े शहरों में लाएगी । शहरों में बस्ती बढ़ती जा रही है, पानी की सुविधा कम हो रही है । मगर 100 शहरों के माध्यम से हम उनका विकास कर सकते हैं । जब कोई शहर बनता है, तो वहां पानी की सुविधा बहुत जरूरी है । 100 शहर डेवलेपमेंट के माध्यम से हम विकास कर सकते हैं ।

मैं कहूंगा कि हम मुंबई शहर में 7 तालाबों के माध्यम से पानी पहुंचाते हैं । मुंबई शहर को प्रतिदिन 3,850 मिलियन लीटर पानी मिलता है । मगर मुंबई की पानी की जो आवश्यकता है, वह 4,500 मिलियन लीटर पानी की है । हम 100 सिटीज़ बनाने जा रहे हैं, उसी माध्यम से मुंबई शहर के लिए हमें और धरणों की जरूरत है । उसके अंदर गारगाई, पिंजाल परियोजना हो । इन धरणों की बहुत जरूरत है । हम जो 100 सिटीज़ बनाने जा रहे हैं, वहां हम पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं । वहां हम लोग पाइपलाइन का निर्माण करेंगे । हम गारगाई और पिंजाल परियोजना बनाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा । हम उसके माध्यम से मुंबई शहर के लिए 4,500 एमएलडी पानी ला सकते हैं ।

इसी तरह से हमें डीसैलिनेशन भी करना चाहिए, ताकि पानी की आपूर्ति के लिए समंदर के पानी को मीठा किया जा सके । जब हम कोई सिटी बनाते हैं, तो परिपूर्ण सिटी बनाने की जरूरत है । जब हम पानी लाते हैं, तो पीने के लिए जो पानी होता है, हम उसको दे देते हैं । मगर सेकेंडरी यूज के लिए जो पानी बचता है, हम एसटीपी के माध्यम से समंदर में छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं, नाले में छोड़ते हैं, जहां हो पाता है, वहां छोड़ते हैं । इसके लिए एसटीपी की भी जरूरत होती है, जिसका इसमें प्रबंध किया गया है । इसमें बताया गया है । हम 100 बड़े शहरों का विकास करने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, जैसा इन्होंने कहा है कि मुंबई-महाराष्ट्र में हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रबंध किया है । केन्द्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप अगले पांच वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे ।

महोदय, इस वर्ष वित्त मंत्री जी ने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा । कोई भी शहर बनता है तो उस शहर में इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है । उसके लिए प्रबंध होना बहुत जरूरी है, उसमें जैसे, मेट्रो हो, रोड हो, रेल हो । इन्फ्रास्ट्रक्चर की वहां की सिटी को बहुत जरूरत होती है । मुंबई के बारे में मैं कहूंगा कि वहां पर एयरपोर्ट है, जैसा मैंने जीरो ऑवर में भी कहा था और उसके लिए मुझे एक मिनट बोलने के लिए मिला था । उस एयरपोर्ट पर एक ही रन-वे है और जो दूसरा है, वह उसको क्रॉस करके जा रहा है, यानी एक ही रन-वे चालू है । जब हम मुंबई आते हैं तो हमें आधा-आधा, एक-एक घण्टा ऐसे ही ऊपर घूमना पड़ता है । मेरी मांग है कि उसके बाजू में जो झोपड़पट्टी है, यदि हम उसका डेवलपमेंट शहरी विकास के माध्यम से करेंगे तो वहां दूसरा रन-वे बन जाएगा । हम दूसरे रन-वे के माध्यम से एयरपोर्ट की स्थिति में सुधार ला सकते हैं ।

महोदय, वहां एक फनेल भी होता है । रडार के माध्यम से फनेल के अंदर की जो सुविधा है, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए । मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं । वहां कोंकण रेलवे है । जब हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेलवे के अंदर भी डेवलप होना चाहिए । रेलवे के अंदर मुंबई के लिए दस साल से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी करने का एक प्रयास है । उसका क्या हुआ है, अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है । इसके लिए भी आपके माध्यम से प्रयत्न होना चाहिए । इसी प्रकार से कोंकण रेलवे में दो ट्रैक होने चाहिए । वहां पर एक ही ट्रैक है । यदि मुंबई से कोंकण जाना है तो एक ही ट्रैक पर ट्रेन चलती है । वहां पर दो ट्रैक बनने चाहिए । मेट्रो 6 और 7 का डेवलपमेंट होना चाहिए । मैं एक ही मिनट में पर्यटन के लिए अपनी बात कहूंगा । वहां पर पर्यटन बढ़ना चाहिए और बाहर का पैसा आना चाहिए । मेरे एरिया में जोगेश्वरी गुफा और अंधेरी की गुफा है । आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से टूरिज्म के लिए इनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए । हमारे यहां महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जो किले हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए । यहां क्रूज का जिक्र किया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि अलीबाग, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जो एरियाज़ हैं, वहां पर डेवलपमेंट के लिए क्रूज बनाया जाएगा । वहां टूरिज्म का एक साधन पैदा हो जाएगा । इसी के माध्यम से हमारे यहां समुद्र के किनारे अच्छे होटल बनेंगे, थ्री स्टार और फाइव स्टार होटल बनेंगे और इसी के माध्यम से हमारा टूरिज्म बढ़ता जाएगा । महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, वह बजट भेदभावपूर्ण बजट है । किसानों, नौजवानों, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति के साथ अन्याय किया गया है । किसी भी देश के विकास का रास्ता, भारत के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है । जब खेत और खलिहान समृद्धशाली होंगे तो देश की आय बढ़ेगी । लेकिन इस बजट में किसानों के बारे में, उनकी एमएसपी की गारंटी देने के बारे में कोई बात नहीं रखी गयी है ।

मान्यवर, यह बजट किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला बजट है । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने एमएसपी अधिक बढ़ाकर देने का काम किया है । हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन है, सरकार के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों में उस कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन के समतुल्य जो समर्थन मूल्य है, वह नहीं है । महंगाई के कारण किसान की लागत बढ़ गयी है । खाद का दाम बढ़ गया, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, लेकिन उसके समतुल्य एमएसपी का दाम नहीं बढ़ा है । इससे किसान की आमदनी घटी है । दूसरी तरफ किसान जो कृषि यंत्र खरीदता है, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में दूसरे सेक्टर्स को रियायत देने का काम किया है, लेकिन कृषि यंत्रों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, जिन पर 28 परसेंट जीएसटी है ।

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है । जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे, भारत को समृद्धशाली नहीं बना सकते हैं । उस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ाने वाला यह बजट है । जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है । इस बजट में पिछड़े वर्गों की बैकलॉग भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है । अनुसूचित जाति के आरक्षण को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है । इसके साथ-साथ किसान को समर्थन मूल्य देने की गारंटी का उल्लेख नहीं है । मैंने बजट के विभिन्न हिस्सों को देखने का काम किया है । पिछले वर्ष के मुकाबले उर्वरक पर कम पैसा रखने का काम किया गया है । कृषि के बजट को भी जिस तरह से बढ़ाने का काम होना चाहिए, उस ढंग से नहीं बढ़ाया गया है । केवीके की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है । मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी मजदूरी 231 रुपये प्रतिदिन है । 231 रुपये में आजकल कोई मजदूर नहीं मिलता है । उसको बढ़ाने का भी इस बजट में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है । अनुसूचित जाति के पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति और फीस की प्रतिपूर्ति देने की व्यवस्था होती थी । इस बजट में केन्द्र सरकार ने उसको घटाने का काम किया है । उसको बढ़ाने का प्रोविजन इस बजट में नहीं किया गया है । शहरी विकास की बात की गयी है, लेकिन ग्रामीण विकास की दिशा में इस बजट में कोई प्रोविजन करने का काम नहीं किया गया है । मेरा यह मानना है कि जब तक हम किसान को, चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधान मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है- ?भारत की आर्थिक भयावह स्थिति- कारण और निदान ? हमारे वित्त मंत्री जी को उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए था । अगर हम उस किताब को पढ़ते तो निश्चित रूप से इस देश में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करते । बुनकर उद्योग पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है । यह तमाम लोगों को रोजगार देता है । लेकिन बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

माननीय सभापति **:** कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री लालजी वर्मा **:** मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें उन बुनकरों को बिजली सस्ती दर पर देने के लिए, उनके उत्पादन की खरीद करने के लिए तथा उनको सस्ते रेट्स पर धागा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए । साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया है । उत्तर प्रदेश कभी बाढ़ से तो कभी सूखे से प्रभावित हुआ है । वहां पर तमाम जगहों पर बाढ़ आई है । नेपाल पानी को नदियों में छोड़ता है, उसका बहुत बड़े हिस्से पर असर पड़ता है । दूसरी तरफ सूखा भी है । हमारे जिले में आज कम वर्षा के कारण किसान की धान की फसल खत्म हो रही है । उसके विकास के लिए तथा उसको कैसे ठीक किया जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

मान्यवर, अयोध्या के बारे में बार-बार चर्चा होती है । बनारस से माननीय प्रधान मंत्री जी चुनकर आते हैं । अयोध्या से बनारस जाने में सात घंटों से ज्यादा का समय लगता है । उसके लिए एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान करने का काम नहीं किया गया है ।

मान्यवर, सांसदों की जो क्षेत्र विकास निधि है, वह बहुत कम है । वह पांच करोड़ रुपये है । एक किलोमीटर में एक करोड़ रुपये लगते हैं । पांच करोड़ रुपये में पांच किलोमीटर सड़क बनेगी । हमारे यहां पर पांच विधान सभा क्षेत्र हैं और वे 20 लाख की आबादी को कवर करते हैं । उस राशि को भी इस बजट में बढ़ाने का माननीय वित्त मंत्री महोदया ने उल्लेख नहीं किया है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि क्षेत्र विकास निधि कम से कम 20 करोड़ रुपये होनी चाहिए ।

मान्यवर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बात करने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया करती हूँ ।

हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है । इन चार शब्दों में भारत की ताकत और महानता छिपी है । न कोई जाति, न धर्म, न भाषा, न पहनावा, सिर्फ हम भारत के लोग । इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में ही हमारी गरिमा बसी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इस ताकत को धर्म की राजनीति से कमजोर बनाया गया है ।

आज वर्ष 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है । मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहती हूँ । हम सब जानते हैं और पूरा विश्व यह मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी । उस समय जी.डी.पी. और इस प्रकार की चीजें नहीं थीं, लेकिन भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी और हम यह भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी, बावजूद इसके मुट्ठीभर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा और न सिर्फ लूटा, बल्कि हमें सैकड़ों साल गुलाम भी बनाए रखा । ऐसा क्यों हुआ? पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया । ऐसा वे कर पाए, क्योंकि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी और वह थी ? सामाजिक एकता की ।

धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठीभर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी । 90 प्रतिशत समाज प्रताड़ित था और मैं यह कहूंगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था । आज हमारा देश दुनिया की पांचवीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुझे यह उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही दुनिया की पहले नम्बर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसकी प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद की सरकार ने रखी थी । इसी के साथ हम आज सामाजिक तौर पर जात-पांत-धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं । फाइनेंशियल इनइक्वेलिटीज़ बढ़ती जा रही है । पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है या मैं यह कहूंगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा जानबूझकर करवाया जा रहा है ।

मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, बल्कि समाज की एकता में है । हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए । बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है, लेकिन इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है । क्या यह हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ी पड़ी रहने के बावजूद जिंदा है और जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वह खतरे में कैसे आ सकती है? लेकिन फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियों की वजह से हिंदू खतरे में है । हमारी हिन्दू संस्कृति एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही है । वह सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर में सेंध लगाते हुए बह रही है । उसके बहाव को न कोई तलवार काट सकती है और न ही कोई पहाड़ रोक सकता है । पर, दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव को रोक कर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है । मैं समझती हूं कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है ।

सभापति महोदय, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला और आज वह आरक्षण भी इनकी नजरों में खटक रहा है । इसीलिए सभी सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरैक्टली आरक्षण खत्म करने का षडयंत्र बीजेपी कर रही है ।

सभापति महोदय, इनके मुताबिक बीते वर्ष 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ । कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही वर्ष 2014 में हुआ । खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झुठला सकते हैं कि आज भारत चांद पर पहुंचा, उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी । वर्ष 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपगैंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है । पर, इनकी लाखों नॉन-बायलॉजिकल कोशिशों के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू-गांधी का देश ही मानेगी । जब ये दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, तो इनको गांधी जी की प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है । ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें, जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती हैं कि दाम बढ़ते हैं, तो बढ़ने दो, हम प्याज नहीं खाते । स्कूल्स-कॉलेजेज के फीस बढ़ते हैं, तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं, भक्त बढ़ाते हैं । फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन के समक्ष पेश करूं ।

सभापति महोदय, मैं पंतप्रधान किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कहना चाहती हूं । किसानों को पंतप्रधान किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सालाना छ: हजार रुपए दिए जाते हैं । उनको दो-दो हजार रुपए तीन इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजर खरीदने पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है । एक किसान एक साल में कम से कम एक लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप उन्हें छ: हजार रुपए देते हैं लेकिन उनसे 18 हजार रुपए लेते हैं । यह किस तरह की नाइंसाफी उनके साथ हुई? आप उन किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं । आप उन्हें छ: हजार रुपए देते हैं, लेकिन उनसे जीएसटी के माध्यम से 18 हजार रुपए लेते हैं । जब यूपीए की सरकार थी, तब फर्टिलाइजर पर से टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया था । मेरी मांग है कि उनको जो सालाना छ: हजार रुपए मिलते हैं, उसे बढ़ा कर 12 हजार रुपए किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 50 हजार लोग पंतप्रधान किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हैं, क्योंकि इसको अप्रुवल नहीं मिल रहे हैं । जब वे मंत्रालय में जाकर पूछते हैं, कि हमारी योजना के अप्रुवल का क्या हुआ, वे कहते हैं कि दिल्ली जाकर पूछो, हमें नहीं पता है । पंतप्रधान किसान सम्मान निधि योजना का इंटेंशन क्या है? क्या इस योजना के माध्यम से किसानों को फंसाया जा रहा है?

सभापति महोदय, मैं फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहती हूं । पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, सांगली, सतारा और कोल्हापुर में उड़द और अरहर की दाल उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए मिलती है ।

आपके माध्यम से मैं फाइनैंस मिनिस्ट्री से गुजारिश करती हूं कि अरहर और उड़द फसल के लिए भी फसल बीमा योजना के फार्म्स भर दिए गए हैं, लेकिन उनको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ।

सभापति महोदय, मैं पंतप्रधान आवास योजना के बारे में कहना चाहती हूं । आदरणीय फाइनैंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि वे इस बजट में घरों की संख्या बढ़ा कर तीन करोड़ घर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को पंतप्रधान आवास योजना का टारगेट नहीं मिला है, क्योंकि इस योजना के तहत गौठान जमीन पर घर बनाए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि गांव में गौठान जमीन नहीं है । जब लोग कलेक्टर के पास जाते हैं, तो कहा जाता है कि गौठान जमीन नहीं है, आप गायरान जमीन ढूंढ कर लाइए, तो हम आपको पीएम आवास योजना की सुविधा देंगे । अब वे गायरान जमीन कहां से लाएंगे?

मैं आपके माध्यम से फाइनैंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूं कि सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दें कि गांवों में जितनी भी गायरान जमीनें हैं, उनको गौठान जमीन में बदल कर पंतप्रधान आवास योजना लोगों के लिए लागू की जाए । सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाए । मेरी आपसे यह गुजारिश है कि इस योजना के लिए 1 लाख 40 हजार रुपये मिलते हैं । यह बहुत कम पूंजी है । पंतप्रधान आवास योजना के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये दिए जाए ।

महोदय, वर्ष 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एंबिशियस्ली मुद्रा लोन की घोषणा की थी । कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी राशि 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की है । लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले, जिनकी सिफारिशें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि जो सामान्य आदमी है, आम आदमी है, उसको यह लोन नहीं मिला था । सिर्फ कुछ चंद लोगों को यह लोन दिया गया था । मेरी यह मांग है कि कोरोना के टाइम पर जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज नहीं दे पाए, आपने जैसे अदानी और अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे ही इन लाभार्थियों का कर्जा भी माफ किया जाए । उनका मुद्रा लोन का कर्ज तुरंत माफ किया जाए ।

आदरणीय सभापति महोदय, जो माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स दिए जाते हैं, यह हमारे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और बीड़ी कामकारों को, पावरलूम वर्कर्स को दिए जाते हैं, हमारी काफी सारी महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन इस माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है । इसलिए ये बेहिसाब इंट्रेस्ट इन लोगों से, गरीब लोगों से लेते हैं । मुझे इस बात का दु:ख हो रहा है कि कल की बजट स्पीच में, हमारी जो अन्नधान्य सुरक्षा योजना है, अन्न सुरक्षा योजना जो यूपीए सरकार लाई थी, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई जिक्र नहीं किया । पिछले दस साल से हमारे देश का जो गरीब है, एपीएल कार्डधारक को अन्नधान्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । दस साल से करोड़ों लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं । सैलजा जी ने जैसे कहा था कि कुपोषण का जो प्रमाण है, हमारे देश में बढ़ रहा है । गरीब लोगों से जान-बूझकर एक फॉर्म ? गिव-अप सब्सिडी फॉर्म ? उनको बिना बताये जान-बूझकर भरवाया जा रहा है । अगर आप यह फॉर्म भरेंगे तो आपकी फूड सब्सिडी कट हो जाएगी । उनसे जबर्दस्ती यह फॉर्म भरवा रहे हैं, ताकि उनको इस योजना का, जो कि कांग्रेस की योजना थी, लाभ न मिले । इसकी वजह से हमारे देश में ढेर सारे लोग भूखे मर रहे हैं । मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह गुजारिश करती हूं कि एपीएल कार्डधारक को तुरंत इस योजना का लाभ मिले और सारे के सारे जितने भी लोग हैं, उनको धान मिले ।

महोदय, कल की स्पीच में आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर बहुत प्यार जताया गया । मुझे उस बात से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों है? महाराष्ट्र की तरफ उतना प्यार क्यों नहीं जताया गया, जितना बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ जताया गया । क्योंकि उनको पिछली लोक सभा से कम सीटें मिलीं या शायद उनको अंदाजा लगा कि आने वाले इलैक्शन में वह चुनाव हारने वाले हैं । मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में हिन्दवी स्वराज की नींव रखी गई थी? कणखर देशा, राकट देशा, दगडांच्या देशा, महाराष्ट्र देशा ? यह हमारे महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है । लेकिन अफसोस है कि महाराष्ट्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । सिर्फ महाराष्ट्र का इस्तेमाल किया जाता है ।

महोदय, अगर मैं रेलवे के बारे में बोलूं तो रेलवे में स्लीपर कोच की संख्या कम कर रहे हैं । फर्स्ट क्लास और सैकेंड क्लास की संख्या बढ़ा रहे हैं । देश का जो गरीब आदमी है, वह स्लीपर कोच से ट्रेवल करता है । वह फर्स्ट क्लास और सैकेंड क्लास सफर नहीं करता है । मैं आपके माध्यम से गुजारिश करती हूं कि स्लीपर कोचेज की संख्या बढ़ाई जाए ।

मैं शोलापुर के लिए कुछ मांगे रखती हूं और अपना भाषण समाप्त करती हूं । हमारे शोलापुर में एयरपोर्ट है, लेकिन एयर सर्विस नहीं है । उडान स्कीम के अंतर्गत यह आया है, लेकिन जान-बूझकर वहां पर जो चिमनी थी, ऑब्स्ट्रक्शन था, वह तोड़ा गया और अभी तक वहां पर एयर सर्विस शुरू नहीं हुई है । वहां बोरामणी एयरपोर्ट है । वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फंड्स एक बार दिए गए, लेकिन उसके बाद फंड्स नहीं दिए गए । मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करती हूं कि बोरामणी एयरपोर्ट के लिए फंड्स दिए जाए । जो मंगलवेढा तालुका है, वहां पर इरिगेशन स्कीम है और वहां के 35 गांव पानी से वंचित है । मैं विनती करती हूँ कि आप उन गांवों के लिए भी इरिगेशन स्कीम जल्द-से-जल्द अप्रूव करें । अंत में, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी विपक्ष की अवहेलना कर रही है कि हमें इतनी सीटें मिलीं, जनता ने अस्वीकार किया, पर आपके 400 पार का क्या हुआ? लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हम स्वीकार करते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाए । हम हमारी बातें शायद जनता को बेहतर तरीके से नहीं समझा पाए । लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगी कि हम हार गये तो क्या हुआ, हम झोला उठाकर चल नहीं देंगे । हम लोग यहीं डटे रहेंगे । हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए एवं इस देश की जनता के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे ।

मैं कुछ शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी ।

सत्ता की लालच में न फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग,

आपकी हस्ती मिटा देंगे, हम भारत के लोग ।

जय हिन्द, जय महाराष्ट्र । धन्यवाद ।

SHRI JAGADISH SHETTAR (BELGAUM): Respected Chairman, Sir, I have been given the opportunity to address this august House. For the first time, I am elected to the Parliament from the Belgaum constituency that is in Karnataka. I am very much thankful to the hon. Speaker and our Party and our leader Shri Narendra Modi Ji for giving me a positive address and participating in the Budget Session.

Sir, I am honoured to be here today to discuss the crucial elements that drive our nation's progress. The Budget mainly focuses on four major pillars ? Garib, mahila, yuva and anndaata. This is from the cornerstone of our pursuit of our hon. Prime Minister Narendra Modi Ji?s vision of a Viksit Bharat.

Viksit Bharat is a concept, a promise to every citizen of our great nation. It embodies our commitment to economic growth that reaches every corner of the country ensuring that no one is left behind ? *Sabka Saath Sabka Vikaas*. Through strategic initiatives and inclusive policies, the Budget is building a nation where the opportunities are abundant and everyone has the means to contribute to and benefit from our collective prosperity.

I will focus mainly on the benefits of our start-ups, the women empowerment consumption, MSMEs and job creation. These are the main important pillars of the

development of our nation. Our hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister Narendra Modi Ji have given importance to these four pillars. Accordingly, the Budget has been presented. I am very much happy. I am supporting this Budget and I congratulate our Finance Minister and our leader Shri Narendra Modi Ji for this important and a good Budget.

As far as start-ups are concerned, the abolition of angel tax is a wonderful step in ensuring the continued success of our start-ups in the nation. The investments in AIML are in the right direction. The start-ups are the livelihood of innovation and economic vitality. They bring fresh ideas, create new markets, and generate employment opportunities. The Budget recognizes this and is committed to fostering a supportive environment for the start-ups.

To promote the farmer producer organisations, cooperatives and start-ups in the vegetable supply chain, ensuring better collection, storage and marketing, additionally the Budget is providing financial support to encourage development of new crop varieties and fostering agricultural start-ups. That will bring innovation into our farming communities. This is very important.

We have seen start-up in other fields. But now this aim to encourage start-ups in the agriculture is very important. It will be helpful to the farmers and it will facilitate women empowerment. It is giving so much importance to facilities and projects concerning women. It will facilitate women empowerment. That is also a very good step taken by our hon. Prime Minister.

Regarding local economy, boosting domestic consumption is another key focus area. To stimulate local economy, the Budget envisages developing 100 weekly *haats* or street food hubs in select cities. That is also very important and it will create more employment opportunities.

Another important sector is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This will create more employment opportunities at the national level. Wherever MSMEs are there, it will create more employment opportunities for youth. That is a very important sector. Loan and other facilities will be given to the MSMEs for their development. The aim of our leader Narendra Modi ji to create more job opportunities is very important.

The Budget has launched schemes to provide internship opportunities in 500 top companies for one crore youth over the next five years equipping them with the skills and experience needed to succeed in today?s competitive job market.

Additionally, the Budget is offering an allowance of Rs.5,000 per month and one-time assistance of Rs.6,000 through CSR fund providing crucial support to our young workers. The Budget?s skilling initiative is aimed at equipping 20 lakh youths with new skills over the next five years. The Budget is also upgrading 1000 industrial training institutes in hub and spoke arrangements ensuring that our work force is ready for the jobs of tomorrow. These are very good steps for development, for creation of employment opportunities, women empowerment and skilled youth labour. Whatever steps have been taken by Narendra Modi ji are very important.

The Opposition parties are criticising it but I think, they have forgotten what Modi ji has done for the country in the last 10 years. I will give one example. Take for example, the UDAN scheme. In Karnataka only Bengaluru and Mangaluru airports are developed. But Hubli and Belgaum airports were there only as showpieces. After launching of the UDAN scheme, there is much connectivity from Belgaum to so many important cities. There is connectivity even to Delhi. There is connectivity from Hubli to Delhi and from Belgaum to Hubli. There is connectivity to so many cities. There is connectivity even to Gulbarga. Even in Kalyana-Karnataka, Gulbarga Airport has been developed. Shimoga Airport has been developed. So, air connectivity started because of UDAN scheme. UDAN scheme is for a limited period.

I would request the hon. Prime Minister and the concerned Minister that if the period is further extended, then more commercial activities will happen in the cities and they will be further developed.

Hon. Chairperson, Sir, another point is this. The Members from the Opposition Parties have started criticising the Government asking as to what has happened to the infrastructure. Earlier, when the UPA Government was there, and when the Congress Government was there, why had the infrastructure not developed? When Atal Bihar Vajpayee came into power and when he became the Prime Minister, four-lane and six-lane roads were constructed. And when did the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana start? It was started when Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister.

During these 10 years of Modi ji?s regime also, so many expressways and highways and four lanes and eight-lanes roads have been constructed. Why did it not happen during the UPA Government? Why did it not happen during the Congress

Government? They are only criticising the Government. Kindly see the contributions made by Modi ji during the last 10 years.

Earlier, in Karnataka, for the last so many years, we have not been given IITs. When the Congress Government was there and when the UPA Government was there, we did not get IITs. But when Modi ji came into power, the State of Karnataka got IIT for the first time. Several medical colleges have been established. AIIMS have also been established in so many States. Why was it not done by the Congress? They have to answer it. ? (*Interruptions*) What happened? ? (*Interruptions*) Only corruption and scams happened during UPA-II.

During the last 10 years, there have not been any scam. There is no blackspot on Modi ji. A transparent Government has been given by Modi ji. What had happened during UPA-II? Only scams, scams and scams happened. Only corruption, corruption, corruption had happened. ? (*Interruptions*) Transparent Government and good administration are given by Modi ji. And now, we are the fifth largest economy in the world. Within a short period, we will become the third largest economy in the world.

What had happened in the UPA Government? What had happened during the Congress Government? Why did you not solve all such problems? Only criticising will not help. You see your performance. You compare your performance. I have limited time. If I am given more time, I will explain what had happened during the UPA Government and the Congress Government, and will also explain what the Karnataka Government is doing. I will explain everything. But nothing had happened. Model Government is there. Good administration is there. You have to see and learn from Modi ji?s leadership. Still, he is the mass leader. Indian people like Modi ji. He is the mass leader. He is the popular leader. Nobody can compare with the leadership of Modi ji. So, now, this has happened.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to say one last point. There are river disputes also. A dispute relating to Kalasa-Banduri (Mahadayi river) is there between Karnataka and Goa. There is also a dispute with regard to Upper Krishna Project among Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Kaveri river water dispute is there between the States of Karnataka and Tamil Nadu. The Minister of Jal Shakti Shri C R Patil was sitting here. With regard to this issue, I request all the national Parties as well as the regional Parties. If there is economic development, and if more irrigation projects are taken up everywhere in the country, the farmers will develop like anything, and economic activities will be increased. So, keeping in view

of all these things, these issues have to be resolved consciously. If such disputes involving rivers like Mahadayi and Kaveri, and Upper Krishna Project are resolved, then it will be helpful.

I am very much thankful to the hon. Chairperson and our Party for giving me the opportunity to address this august House.

Thank you.

19.00 hrs

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you Sir, hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman Ji presented the Union Budget for the financial year 2024-25. The Budget outlines a total expenditure of Rs. 48.21 lakh crore and receipts of Rs. 32.07 lakh crore which excludes borrowings. The Budget shows the net tax receipts estimated at Rs.25.83 lakh crore. Thus, the fiscal deficit is projected at 4.9 per cent of GDP. I hope the Government would contain this deficit well within the limits prescribed and would not certainly jump so that the economy does not get shaken.

Though this budget emphasizes on key initiatives under the Viksit Bharat theme, it largely offers sops to BJP's allies - TDP and JDU governed Andhra Pradesh and Bihar - whereas States like Maharashtra, Haryana, Jharkhand found hardly any mention in the Speech made by hon. Finance Minister. We are not averse to Andhra Pradesh or Bihar as these states do require allocation of sufficient funds but in the true spirit of cooperative federalism, other states in the country should have been allocated proportionate share in allocation. This has not happened.

Sir, road map drawn out by the govt. for the pursuit of Viksit Bharat is focusing on four major groups - *Mahilaye* (women), *Garib* (poor), *Yuva* (youth), and *Annadata* (farmers). To achieve the goal of Viksit Bharat, nine priorities have been chalked out in this Budget which includes productivity in agriculture, employment and skilling, inclusive human resource development and social justice, manufacturing and services, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development and next generation reforms. These are the nine major points which have been focussed in this Budget.

Though this Budget carries an allocation of more than Rs. 3 lakh crore for schemes benefitting women and girls in order to enhance women's role in economic development, what is the situation on the ground as far as security and well-being

of women in various states is concerned? Whatever is provisioned in the Budget, does it really go to empower the rural women? Rural women's education, health and security are the issues which remain unanswered as of date.

Secondly, as far as *garib* or poor is concerned, the Niti Aayog claimed that 24.8 crore people have been lifted out of multidimensional poverty in nine years leading up to year 2022- 23. If this is true, then why is the programme of free ration for five years to 80 crore poor in operation? May the hon. Finance Minister enlighten the house on this issue?

Sir, unemployment is the biggest problem being faced in our country. Unemployment has reached its peak at the rate of 9.2 per cent according to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). The Central Govt. departments, Central Government undertakings which have huge capacity to offer permanent employment to youth of India, should take up recruitment drives and encourage State Governments to fill in their vacancies in various departments. Private sector corporates should also be urged to take up recruitment drives.

Recently, in the state of Maharashtra, Air India's fixed contract term recruitment exercise showed a pathetic sight of thousands of unemployed youth stranded outside the campus of Air India struggling to make their way to get jobs in the heavy rains which lashed the city of Mumbai. This situation prevails in all the States in varying degrees. Permanent job has become a word of the past and contract basis has become the norm where exploitation of youth at the hands of contractors has become the order of the day.

Sir, since I come from the State of Maharashtra, the above-stated facts about *mahilayen, garib, yuva* and *annadata* do really matter in various districts of my State. Along with this, I would like to mention here that Maharashtra contributes immensely to the Central exchequer but does not get its due share in return.

Our city of Mumbai which is the financial capital of India is the highest direct tax paying city in the country. But what does Mumbai get in return? The PIB released State-wise GST collections in March 2024, which shows that Maharashtra has ranked first in the list in absolute numbers followed by Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu, Haryana and UP. I sincerely request to the hon. Finance Minister to review the devolution of funds and increase the share of Maharashtra substantially in the coming years.

Sir, the Railways has seen an increased allocation of 5.8 per cent from the previous years in this Budget. It was anticipated that this Budget would give priority to rail safety. However, the Budget does not reflect Government?s promised focus on rail safety despite several rail accidents in recent times. It does not have anything to counter the issues of congestion and comfortable travel which have been plaguing the Railways for quite some time.

In the year 2020, the Government declared that the National Automatic Train Protection System, that is, Kavach, would cover more than 35,000 kilometres of rail route. The technology is to be fitted in trains as well as on rail routes so that it would decrease the probability of accidents. But the implementation of Kavach is slow and limited progress has been made in this direction. I would urge the Government to complete the implementation programme of Kavach and ensure the safety in rail travel.

Sir, many welfare schemes have been announced in this Budget which look good on paper. But do they really materialise, become operational and benefit the people at large? The schemes like Har Ghar Nal Se Jal, Izzat Ghar, PM Awas Yojana etc. are good for the people at large especially in rural areas. But the audit of the timely implementation will give the correct picture of these schemes.

Sir, the provision for Central Government schemes like MGNREGA is being reduced now to Rs.60,000 crore from Rs.86,000 crore in 2023-24. May I know the reason for this? MGNREGA is the Scheme which really helps the rural farmers and the rural economy. Similarly, lesser provision has been made in Research & Development projects this year compared to 2023-24. Earlier, it was Rs.1200 crore. Now, it has been reduced to Rs.840 crore. Solar power grid also faces this same thing. From Rs.10,000 crore, it has been reduced to Rs.4,970 crore. May I know from hon. Finance Minister the reason for this reduction in the provision?

Sir, before I conclude, I regret that hon. Finance Minister has not given any relief to the salaried middle-class people which they were looking for. Mediclaim policy is of essence in today's world as medical treatment charges are beyond the capacity of the common man. The GST charged on Mediclaim policy is 18 per cent which makes it unaffordable to the middle-class people. This needs review by GST council. The New Pension Scheme should be replaced by Old Pension Scheme as it is the genuine demand of salaried class, which I hope the hon. Finance Minister would look into and oblige the middle-class people.

Sir, the Economic Survey which came the other day just before the Budget was presented shows that the household savings and small savings have been really low as far as our economy is concerned. It is one of the indicators which gauge the strength of the economy. If India is to become third largest economy as far as the global powers are concerned, then this is the power that we should give to the people who really make the labour force of India. May I know from the hon. Finance Minister what measures would be taken on the sidelines of the Budget which will strengthen the economy of India and make it a super power in times to come?

Thank you very much.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति महोदय, 18 वीं लोक सभा के गठन के बाद और इस नए संसद भवन के बनने के बाद मैं आज पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति जी, मैं सबसे पहले श्रद्धेय नेता जी को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत, साहस और अपने पूरे जीवन की तपस्या समाज के उत्थान, देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है । सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को अपनी समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक़ की लड़ाई करना सिखाया है । उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से न केवल लड़ रहे हैं, बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक चुप बैठने वाले नहीं हैं ।

सभापति महोदय, बजट एक व्यापक विषय है । जब हम इस विषय के बारे में सोचते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें । क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम से कम 95 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो आज पूरी तरह से बर्बाद हैं । एनडीए की यह सरकार 11 वां बजट पेश कर रही है । लेकिन इस 11 वें बजट के बावजूद, अगर मैं देखता हूँ तो समाज के गरीबों के लिए जो सबसे ज्यादा ज़रूरी चीज़े हैं, जैसे स्वास्थ्य है तो वर्ष 2023 और 2024 में उसका बजट घटा दिया है । किसानों का बजट जहां यूपीए की सरकार के समय वर्ष 2014 तक 5.5 पर्सेंट था, वहीं 2024 आते-आते यह 3.15 पर्सेंट रह गया है । शिक्षा का बजट जहां वर्ष 2013 में 4.77 पर्सेंट था, आज 2023-24 आते-आते यह ढाई पर्सेंट रह गया है । इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह जो बीजेपी-एनडीए की सरकार है, वह पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मज़दूर विरोधी, जितनी भी उपाधियां दी जाएंगी, वे कम हैं । मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ । मैं उदाहरण सहित बता रहा हूँ । ? (व्यवधान) जब आपका नंबर आएगा तब बोल देना और हमें पता है कि आपकी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए आपका नंबर भी नहीं आएगा, यह भी हमें पता है ।

सभापति महोदय, श्रद्धेय नेता जी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वह भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है । उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी-एनडीए की सरकार ने बनाया है ।

सभापति महोदय, वर्ष 2014 के चुनाव के समय प्रधान मंत्री जी ने वादे किए कि दो करोड़ रोज़गार हर साल मिलेंगे । स्वामीनाथन जी, जिनको इस सरकार ने भारत रत्न दिया, उसके लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वह धन्यवाद अधूरा है, जब तक यह सरकार उनकी सिफारिशों को नहीं मानती है । वर्ष 2007-08 से लगातार देश में मांग चल रही है कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश हैं, जैसे किसानों को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, कानूनी हक और अधिकार दिए जाएं, उस गारंटी को आज तक नहीं माना है । ? (व्यवधान) आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए । ? (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप चेयर की तरफ देख कर बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव **:** अरे यार! ... से जीत आए हो तो ज्यादा न बोलो । ? (व्यवधान) मालूम है कि कितने बड़े तीरंदाज हो । ? (व्यवधान) ... *? (व्यवधान) स्वामीनाथन जी की सिफारिश आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की और कितनी बढ़िया बात है कि खाद पर हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले 50 किलो से घटा कर 45 किलो किया गया । फिर 45 किलो को 40 किलो किया गया और मुझे लगता है कि तीसरा कार्यकाल पूरा होते-होते खाद के कट्टे में केवल 10 किलो ही बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा । इस सरकार ने मंडी एक नहीं बनाई, किसान इतनी आत्महत्याएं कर रहे हैं और अगर किसान एमएसपी की माँग करते हैं, हज़ारों किसान दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी बात को कोई नहीं समझेगा ।

सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया! नौजवानों से कह दिया गया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा । मैं आज अपने नौजवानों की ओर से सवाल पूछता हूं । भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग बताएं । 10 साल आपने राज कर लिया है । आखिर 20 करोड़ नौजवानों का रोजगार कहां है?? (व्यवधान) छोड़िए । कोई तुम्हें नोटिस नहीं लेता ।? (व्यवधान) छोड़ो, तुम्हें कोई नोटिस नहीं लेगा । 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11 वें बजट में जब याद आई तो वह भी ट्रेनिंग की बात करते हो । मैं कहना चाहता हूं कि आप आईआईएम, आईआईटी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो । आप सोच रहे हो कि इंटर्नशिप जैसे छोटे शिगुफे से नौजवान खुश होंगे । देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं हैं ।

सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है । लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है । इस बीजेपी सरकार का लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे । देश में जेएनयू से लेकर, बीएचयू से लेकर, एएमयू से लेकर, जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है । एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं भी आपका वाइस चांसलर नहीं है । जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल बेसिक कोर्स नहीं करेगा, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी । आप क्या सोच रहे हो कि इन नौजवानों को देश नहीं देख रहा है? यूजीसी का बजट लगातार कम किया जा रहा है । इस सरकार पर मेरा खुला आरोप है, शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठीभर उद्योगपतियों के हाथों में देकर, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देकर, देश के 140 करोड़ लोगों में,

जिसमें मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का षडयंत्र आपकी सरकार कर रही है । इसके लिए हम लोग इस मौके पर विरोध करते हैं । आप लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो ।

सभापति महोदय, जहां तक समाजिक असमानता की बात है, वर्ष 2014 में जिस समय एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय देश की जितनी भी आर्थिक चीजें थीं, जो वेल्थ थीं, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17 फीसदी थी । आज दस सालों की एनडीए सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत केवल 9 फीसदी हो गई है । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बता दें । अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो आप बता दो । एक भी अरबपति हो तो बता दो । एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो । एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो आप बता दो । आप अपने जवाब में डेटा दे देना । आप डेटा देना, हमारी अवाज नहीं रूकेगी ।

सभापति महोदय, जब भी बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे, आपने ओपीएस की बात की है । दस साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11 वां बजट पेश कर रहे हो । आज ओपीएस के लिए पूरा देश और सरकारी कर्मचारी परेशान हैं । कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है । पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है ।

सभापति महोदय, हम पुरानी पेंशन के लिए माँग करते हैं । आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हो । मैं माँग करता हूं कि देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए । मैं इसकी माँग करता हूं । आप राष्ट्रभक्त हैं न? सीमा पर जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो समस्याओं को झेल रहे हैं, मेरी माँग है कि आप उनको ओपीएस दीजिए । उनको आप ओपीएस नहीं दे पाओगे ।

सभापति महोदय, इसी तरीके से देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं । एक से एक बढ़िया फार्मूला है, अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े व दलितों को रोकें, तो संविदा कर्मी आ गया । संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी आ गई । आपने संविदा कर्मी की आउटसोर्सिंग कर दी । आउटसोर्सिंग के कारण देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी, आपकी सेवाओं से बाहर हो गए । उनके पास कोई कानूनी हक नहीं है । आप लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए तरह-तरह के जो षडयंत्र अपना रहे हो, इन षडयंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है । इसीलिए, उत्तर प्रदेश से तो आपको बाहर कर ही दिया है, देश से भी जल्दी बाहर करेंगे । हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे ।

सभापति महोदय, इसी तरह से हम माँग करते हैं । आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश की यह बात है, देश के अन्य प्रांत की हालात मुझे नहीं पता, वे और बदतर होंगे । अकेले उत्तर प्रदेश में एक हजार से अधिक शिक्षामित्र आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन किसी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है । किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं । अनुदेशकों को समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई मतलब नहीं है । आंगनवाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं है । आपकी आशा बहुएं, रसोइयां महिलाएं, आंगनवाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं कि यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का डेलीगेशन इनसे जरूर मिलता होगा । वह यह मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए । ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर का टाइम कम करके मेरा टाइम बढ़ा दीजिए । कोई भी मेंबर मेरे लिए टाइम दे देगा । इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए । अगर

समाधान नहीं करेंगे, अभी तो बिहार और आंध्र को पैकेज देकर बैसाखी पर बंध गए, देखें फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाएंगे?

वित्त राज्य मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं । इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार भी उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता । अयोध्या से इतनी नफरत हो गई । अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया । मैं इस मौके पर देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापरियों, बुनकरों, इत्यादि सभी की ओर से कहना चाहता हूं कि यह बजट देश विरोधी बजट है । कोर समस्याओं के लिए संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा कि सरकार को विचार करना चाहिए । श्रद्धेय नेता जी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए, उनको ससम्मान, उनके घरों पर जाकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो । मैं उन्हीं की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं कि जो हमारे शहीद हैं, उनका अंत्येष्टि स्थल जहां कहीं भी बना हो, जिस भी परम्परा से बना हो?(व्यवधान) आपको कुछ नहीं पता है । सैनिकों के लिए यही आपका भाव है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि अग्निवीर की योजना खत्म की जाए । चार साल के सैनिकों से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती है । केवल चार साल, उन्हें आप साठ साल पर रिटायरमेंट दीजिए । चार सालों के बाद वे कहां नौकरियां ढूंढेंगे? मेरी मांग है कि अग्निवीर की योजना खत्म की जाए । साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों का शहादत स्थल है, उनको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केन्द्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए ।

महोदय, बातें बहुत लम्बी-लम्बी की जाती हैं । मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में कहूँगा । हमारे आदरणीय नेता माननीय लाल जी वर्मा जी ने भी कहा है । जो बाढ़ की समस्या है, जो समस्या बिहार में है नेपाल से पानी छोड़ने की, वही समस्या उत्तर प्रदेश की भी है । विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप चलिए तो खीरी से शुरू करेंगे, पीलीभीत, खीरी से लेकर पूरा आप चले जाइए और एकदम कुशीनगर बॉर्डर तक, बिहार बॉर्डर तक सभी जगह यही समस्या है । जब घाघरा आती है, तो मैं समझता हूँ कि इन जिलों के लाखों लोगों को तहस-नहस करके चली जाती है । जितना विकास होता है, बरसात के समय वह सारा का सारा विकास पूरी तरह से खत्म हो जाता है । मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि आप बजट पास कर रहे हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत न करिए । दो बार आप उत्तर प्रदेश के दम पर ही बैठे थे । वित्त राज्य मंत्री जी हंस रहे हैं, इनके यहाँ भी बाढ़ आती है, महाराजगंज बचता तो नहीं होगा, कुशीनगर बचता नहीं होगा, मऊ बचता नहीं है, आजमगढ़ बचता नहीं है, अम्बेडकर नगर बचता नहीं है, बहराइच बचता नहीं है, खीरी बचता नहीं है, श्रावस्ती बचता नहीं है, पीलीभीत बचता नहीं है, बलिया बचता नहीं है, कुशीनगर बचता नहीं है, गोरखपुर बचता नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के इतने जिले प्रभावित हैं । बिहार की तरह से एक विशेष पैकेज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी दे दीजिए । कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत रखिए, केवल सब के सब चीखने के लिए बैठे हैं ।

महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमसे पूर्व जो हमारे आजमगढ़ के सांसद रहे हैं, उन्होंने बड़ी लंबी-लंबी बातें कीं, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए बनारस तक की हमने रेलवे लाइन स्वीकृत करा दी । मैंने जब अधिकारियों से पता किया तो सच्चाई यह है कि अभी उस पर एक भी पैसे के बजट का आबंटन नहीं हुआ है ।?(व्यवधान) बजट का आवंटन नहीं है ।?(व्यवधान) हाँ, आज आप ही ने तो बजट पेश किया है ।? (व्यवधान) आप ही ने तो साइन किया है ।? (व्यवधान) निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा, आप ही ने किया होगा ।? (व्यवधान) उस पर भी बजट आना चाहिए ।

दूसरा, जो बाढ़ वाली समस्या है, मैं समझता हूँ यह कोई मेरे अकेले क्षेत्र की समस्या नहीं है, जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, वह इस पर जरूर गंभीरता से सोचेगा । इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस जन विरोधी बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** श्री सुखदेव भगत जी ।

श्री अजय भट्ट **(**नैनीताल-ऊधमसिंह नगर**) :** मान्यवर, कार्यवाही में *?* शब्द दो-तीन बार आया है, *? ** शब्द पूरी तरह से असंसदीय है । मेरा निवेदन है कि हम सभी को भाषा शैली ठीक करनी चाहिए, लेकिन अगर यह शब्द कहीं आ गया हो, अगर कहीं यह शब्द कार्यवाही में आ गया हो तो मेरा निवेदन है कि उसे हटा दिया जाना चाहिए ।

माननीय सभापति: इसे देख लेंगे ।

श्री सुखदेव भगत जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** अगली बार आप और अच्छा बोलेंगे ।

श्री सुखदेव भगत जी ।

श्री सुखदेव भगत **(**लोहरदगा**) :** सर, मेरी मेडन स्पीच है, माननीय सदस्य बैठेंगे तो बोलूंगा ।

श्री धर्मेन्द्र यादव **:** महोदय, अगर *?* शब्द असंसदीय है तो उसे जरूर हटा दीजिए, उसकी जगह भ्रष्टाचार जोड़ लीजिए ।

माननीय सभापति: प्लीज धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री सुखदेव भगत **(**लोहरदगा**) :** सभापति जी, यह मेरी पहली स्पीच है । मैं पहली बार निर्वाचित होकर आया हूं । वित्त मंत्री जी कल बजट पेश कर रही थीं, मैं बहुत उत्सुक था, एक्साइटेड भी था कि सर्वोच्च पंचायत में जिस प्रकार का बजट आना चाहिए, लेकिन कल दो-तीन बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगीं कि बजट का संबंध वित्त से होता है, लेकिन मैंने देखा कि बजट का संबंध कुर्सी से है । दूसरी बात, यह बजट देश की 140 करोड़ जनता के लिए नहीं है, यह सत्ता के लिए बजट है । कल जो बजट प्रस्तुत हुआ, वह सत्ता के लिए है इसलिए मैंने कहा कि इस बजट का संबंध वित्त से नहीं, कुर्सी से है ।

सामान्यत: हम लोगों को अच्छी चीजें पसंद आती हैं । यही कारण है कि मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की पांच गारंटी योजना की कॉपी की है । न्यायपत्र गारंटी, पहली नौकरी पक्की, लेकिन यह यथार्थ से कोसों दूर है । इसलिए कोसों दूर है कि बजट का प्रावधान इन्होंने 10 हजार करोड़ रुपये रखा है और शेष राशि कंपनियों के सीएसआर फंड से जुटाने की बात की है । न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी । एक करोड़ इंटनर्शिप की इन्होंने बात की है, हर कंपनी को 20 हजार इंटनर्शिप सृजित करने पडेंगे ।

महोदय, अच्छी चीजें ग्रहण की जाती हैं, अच्छी चीजें चुरायी नहीं जाती हैं । भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुराया है इसलिए इसमें खामियां या त्रुटि होना स्वभाविक है । भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे कुर्सी प्रधान देश बना दिया है । मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वर्ष 2019-20 में बजट में कृषि का हिस्सा 5.44 परसेंट था । अभी 3.15 परसेंट है, यह डाउन किया जा रहा है ।

वर्ष 2022-23 में कृषि की विकास दर 4.7 प्रतिशत था, लेकिन वर्ष 2023-24 में 1.4 प्रतिशत है । हमारे सदस्यों ने भी कहा, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात है, उसके बारे में मौन, ऋण माफी के बारे में मौन, जिस प्रकार मणिपुर के बारे में मोदी जी मौनी बाबा बन जाते हैं, इस मसले पर भी सरकार मौन धारण कर लेती है । एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन बजट के माध्यम से यह सरकार छोड़ो, छोड़ो, राज्यों को छोड़ो की बात करती है ।

मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि फंड एलोकेशन की जो बात आई है, जिस प्रकार आपने दरियादिली दिखायी है, लेकिन फेडरल कैरेक्टर की बातें आयी हैं, जब मैं राज्यों की बात करता हूं, सूखाग्रस्त कर्नाटक है, तमिलनाडु में साइक्लोन आया था, आपने उनके साथ कितनी नाइंसाफी की थी, मैं इस भेदभावपूर्ण रवैये को स्मरण कराना चाहता हूं । अचानक माननीय मोदी जी का बिहार प्रेम दिखा । झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी बड़ी घोषणाएं की थीं । स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी की धरती से मोदी जी ने, देश के प्रधान मंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी से 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की बात कही थी । क्या हुआ? यहां हमारे सीनियर सहयोगी निशिकान्त जी बैठे हैं, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि मोदी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं । मैं बिहार के सारे सहयोगियों को बताना चाहता हूं कि 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये देने का वादा किया था और 26 हजार करोड़ का हश्र भी वही होने जा रहा है । मैं इसलिए यह बात एमपी के मित्रों से कह रहा हूं, जिन्होंने 29 सीटें दी हैं, दिल्ली में सात सीटें दी हैं, वे छले गए हैं । यह रवैया इनके साथ है ।

दूसरी बात, सपा के एक सहयोगी कह रहे थे कि यह गरीब विरोधी बजट है । हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 वां है और इन्होंने खाद्य सब्सिडी घटा दी है । जहां तक परीक्षा और शिक्षा की बात करें, शिक्षा का बजट सात फीसदी डाउन कर दिया है ।

महोदय, संसदीय लोकतंत्र में दो विधायी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं ? विधि का निर्माण और लोक धन पर विधायिका का नियंत्रण । अगर विधि का निर्माण हो जाता है तो इस पर कभी-कभी न्यायायल हस्तक्षेप करता है लेकिन लोक धन के संबंध में संसद का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि सरकार द्वारा किए गए खर्च एवं प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नियंत्रण रखे । भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में व्यक्तिगत टैक्स की हिस्सेदारी 19 फीसदी है और कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 17 फीसदी है । यह तब है जब कॉरपोरेट टैक्स में वर्ष 2019 में भारी राहत दी गई थी और इससे सरकारी खजाने में 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये राजस्व नुकसान प्रति वर्ष हो रहा है । यह रियायत इसलिए दी गई थी ताकि रोजगार का सृजन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । रियायत के बावजूद न तो निजी निवेश बढ़ा और न ही रोजगार का सृजन हुआ । कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बजाय कन्जम्पशन बूस्ट पर एक-चौथाई राशि सालाना लगा देते तो घरेलू खपत खर्च में कमी नहीं आती और निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती । आज घरेलू खपत खर्च में गिरावट आई है जो इनकम स्टेटस को कहीं न कहीं परिलक्षित होती है । हम जानते हैं कि इकोनामी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के परिणाम ज्यादा रिटर्न देने वाले होते हैं । ? (व्यवधान) आपको तो सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम नए सदस्य हैं । यहीं से आपकी

गंभीरता पता चलती है और यह पता चलता है किस प्रकार आप सबसे तोड़ो-तोड़ो कर रहे हैं, आपके संस्कार और व्यवहार से परिलक्षित होता है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं क्षमा चाहता हूं । 11 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का आउटले जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये था जिसे घटाकर 0.5 लाख करोड़ कर दिया गया था । मुझे नहीं मालूम कि बजट की राशि क्यों घटाई गई? क्या फंड की कमी हो गई थी या क्रियान्वयन में शिथिलता बढ़ती गई थी? दोनों ही परिस्थितियां चिंताजनक हैं ।

सभापति महोदय, बजट का सबसे बड़ा खर्च इंट्रेस्ट के पेमेंट पर होता है, जो कुल एक्सपेंडिचर का 25 फीसदी होता है । इसीलिए, हमें उधार लेने के पहले दस बार सोचना चाहिए ।

सभापति महोदय, हमारे सहयोगी सत्तापक्ष लोगों ने बड़ी-बड़ी बातें की हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन पिछली बार 1 फरवरी का जो अंतरिम बजट था, वह 47.65 लाख करोड़ रुपये का था, इस बार यह 48.21 लाख करोड़ रुपये का है । मूल बजट अभी केवल 56 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है । ? (व्यवधान) यह तो वैसा ही हुआ कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह बातें हो रही हैं । ? (व्यवधान) इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अंतरिम बजट और मूल बजट में केवल 56 हजार करोड़ का ही अंतर है । आपने जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं । ? (व्यवधान) यह बजट मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह है । 15 लाख रुपये देने जैसे जुमले की तरह है ।

सभापति महोदय, इसीलिए मैंने कहा कि यह बजट का संबंध वित्त से नहीं है, इस बजट का संबंध कुर्सी से है । ? (व्यवधान) यह बजट देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं है, यह सत्ता के लिए है । यह बजट कुर्सी के लिए है । धन्यवाद ।

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY (TAMLUK): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in the Parliament of this country. I express my thanks to our leader Shri Narendra Modi ji, all other senior leaders, and all my friends here.

This is my maiden speech in this House. I was hearing the discussion for the whole day since the debate on the Budget has started today, but I never understood how the Opposition Members who are attacking this Budget, could say such superficial words in respect of the Budget. This is, after all, a Budget of a country that is a sovereign country as also a democratic country. They should have noted this first that in this Budget there is an increase in the standard deduction in income tax. None of them have indicated it, and the reason that I understand is that in any Budget the Opposition will never praise the Budget and whatever be the foolishness in their speech, they will say it all. But after all, we all are seasoned leaders unlike me who is coming from a judicial career for the last nearly 30 years or more.

This standard deduction, when it has been done, will bring a huge quantity of money in the coffers of the employed persons. Why am I saying ?employed

persons?? It is because the standard deduction is applicable only to the employed persons who are mostly middle-class and lower middle-class people. It is not applicable to the businessmen. So, when a large amount of money will be infused in the market, a huge demand will arise for goods. I do not want to compare it with the Bottled Demon because some persons want to keep the demon in the bottle again. However, this is a hugely powerful wave which will come in this market. Pumping money into the industries and then to the agricultural sector will raise demand.

What I have not heard from the Opposition is any single sentence on economy or economics. They are all strewn with the data, data and data. When some amount of money comes in the hands of the general people, then a question arises: which part of it will be saved by the person and which part of it will be spent for consumption of goods? In economics, it is called MPA and MPC. MPA means Marginal Propensity to Save and MPC means Marginal Propensity to Consume. It has been proved time and again in the economics of all the countries that Marginal Propensity to Consume is always higher than the Marginal Propensity to Save which means if a person gets Rs. 100 extra monthly or annually ? we are talking about people from the service sector, who are not wealthy, unless they take huge bribe ? he will spend more than Rs. 50 out of this extra disposable income which can be shown to the tax officials. The smaller part, for example, Rs. 40 or sometimes only Rs. 10 out of this extra Rs. 100 will be saved.

Now, this is the question of microeconomics. The concept of macroeconomics says savings are equal to investment. So, a part of the money will be pumped into the market by way of standard deduction of taxes for the service sector people, and they will start demanding and purchasing more goods and services. Services include tourism, treatment, and other intangible things which a person can get. The savings part will naturally go to his banker. Their savings equal to investment conception will show that the banker will have huge amount of money for giving loans to the industrialists. So, how did my learned friends from the Opposition miss this point? Neither they were seeing the woods nor they are seeing the trees. They are only rebuking the Budget proposal. When the banking sector will get the extra money, they will definitely ? (*Interruptions*) brother, please try to learn. ? (*Interruptions*) Yes, please try to learn. ? (*Interruptions*) You do not know, please try to learn. ? (*Interruptions*) Shout, shout ? (*Interruptions*) That is the only thing you know. ? (*Interruptions*) howling, howling and howling ? (*Interruptions*) That is the only thing you know. ? (*Interruptions*) I understand.

HON. CHAIRPERSON: You please carry on.

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: So, I must ignore the shouting. ? (*Interruptions*) I will request them to learn if it is not known to them. When a huge amount of money will come to the market in the form of investment, new industries will be grown, will be set up for serving the extra demand. This demand-supply equation, which will come into the market from the unleashed huge amounts of money pumped from the lower middle-class section, will definitely change the face of the economy which point my learned friends were missing. As I have said, they were missing the woods and also missing the tree.

Now, I will go to some part of Budget proposals.

HON. CHAIRPERSON: Gangopadhyay Ji, please conclude within one minute.

? (*Interruptions*)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: Who wants me to conclude? I have not told anybody to stay here. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): What is your view on Gandhi and Godse?

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY : Do not talk like a … Sir. ? (*Interruptions*) You neither know Gandhi nor Godse ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us see the proceedings.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will see the proceedings.

? (*Interruptions*)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: Please keep your … than to open it ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Gaurav Ji, we will see the word.

? (*Interruptions*)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: I will request my very learned friends, ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** प्लीज**,** आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैंने बोल दिया है ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: I will request my learned friends to understand? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister.

? (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री**;** तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**) :** ऐसा है कि अगर कोई असंसदीय शब्द हुआ तो चेयर को अधिकार है । उन्हें बोलने दीजिए । आपने क्वेश्चन ठीक नहीं पूछा है । गौरव जी**,** आपने क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा है। अभी आपको यह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था । ? (व्यवधान) अभी वह बजट पर बात कर रहे थे, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है? अगर कोई असंसदीय हुआ तो चेयर को अधिकार है । आप इनको बोलने तो दीजिए । आप इनको रोक कैसे सकते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अगर कोई अनपार्लियामेंटरी वर्ड यूज़ हुआ है तो उसको प्रोसिडिंग्स से निकाल देंगे ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: The Budget also proposes support for MSMEs. ? (*Interruptions*) Our Government has stated, the Finance Minister has stated that special attention will be given to MSMEs and manufacturing, particularly labour-intensive manufacturing, which has been taken care of. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** आसन से बोल दिया गया है । आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: Why is it labour intensive? This is because it is the labour-intensive technique which gives maximum employment to the unemployment people. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** मैंने ऑलरेडी बोल दिया है ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: So, when it comes to the question of giving employment, then the very popular way to establish and to encourage the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** मैंने बोल दिया है ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: Sir, let them shout. They only know that. ? (*Interruptions*) I would also draw the attention of this House to point No.42 at page No.8 that the MSMEs help in growth and also compete globally as mentioned in the Interim Budget. ? (*Interruptions*)

<u>19.51 hrs</u> (Hon. speaker *in the chair*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप लोग कृपया बैठ जाइए । मैं आपकी बात को अभी सुनता हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप लोग कृपया बैठ जाइए । मैं आपकी बात को समझता हूं ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** सर, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम यहां गाली सुनने नहीं आए हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप कृपया बैठ जाइए ताकि मैं आपके विषय को समझ सकूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** क्या विषय था? इन्होंने कौन-सा शब्द बोला था?

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** सर, आप सदस्य से पूछिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बताइए, इन्होंने ऐसा क्या बोला है?

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** सर, यह आप इनसे पूछिए या आप रिकॉर्ड देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द यहां कहा गया है तो उस अनपार्लियामेंटरी शब्द को दोहराकर इस सदन और आपकी गरिमा को मैं धूमिल नहीं करना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अगर कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द है तो मैं उसे देख लूंगा ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** जिस अनपार्लियामेंटरी शब्द को यहां बोला गया है, उसके लिए पहली बार चुने गए सांसद को खेद प्रकट करना चाहिए । अगर मार्शल ने आपको वह शब्द दिखा दिया है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मुझे नहीं दिखाया है ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर खेद प्रकट करना चाहिए । ? (व्यवधान) मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं अर्जुन मेघवाल जी से उम्मीद करता हूं कि सदन का वरिष्ठ सदस्य और मंत्री होने के नाते, अगर उनके सांसद से गलती हुई है तो मैं मंत्री महोदय से भी अपेक्षा करता हूं कि वे खेद प्रकट करेंगे ।? (व्यवधान) मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता हूं, लेकिन आप बड़े हैं और सदन में भी हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं पूरे विषय को देख लूंगा । माननीय सदस्यगण, मैं सभी की भावनाओं का आदर करता हूं । हम ऐसे कई विषय चर्चा में लाते हैं, जिनको किसी पक्ष को नहीं लाना चाहिए । विशेष रूप से, मैं आग्रह करता हूं, हमें सदन के नेता के बारे में या सदन के किसी भी माननीय सदस्य के बारे में कोई भी बात बिना प्रमाणिकता के नहीं कहनी चाहिए । आप जिस विषय को मेरे ध्यान में लाए हैं, मैं उसे देख लूंगा ।

श्री गौरव गोगोई **:** सर, अगर यह सब ऐसे में ही चला गया तो यह बहुत गलत संदेश जाएगा ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: Now, I will come to paragraph no. 51 of the Budget Speech. ? (*Interruptions*) Here, ?Internship in Top Companies? has been mentioned. ? (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई **:** आप संरक्षक होने के नाते इन्हें समझाते कि संसद के अंदर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है ।? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: An internship allowance of Rs. 5,000 per month along with a one-time assistance of Rs. 6,000 will be given to interns. This will again boost up the market. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप एक मिनट रुकिए । वे पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं ।

? (व्यवधान)

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: When this extra amount again will come to the market, it will again create demand and investment. ? (*Interruptions*)

Now, I again draw the attention of this House to point no. 46 on page no. 9 which is regarding Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to Rs. 20 lakh from the current Rs. 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the ?Tarun? category. These loans will again be invested in manufacturing sector, or service sector, or agriculture sector, which will enhance market demand and supply. So, this budget proposal is fully for the common man. ? (*Interruptions*)

The other day one gentleman was playing with the picture of Lord Shiva. Instead of taking shelter under Lord Shiva, he should take the side of this common man. ? (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, please, do not show it.

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: Instead of playing under the picture of Lord Shiva, their leader, Mr. Spaghetti, should learn how to be beside the common man ? (*Interruptions*) This is a common man?s Budget. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप उनको समझा रहे हैं तो आपके नेता को भी समझाइए । वे भी फोटो लेकर बहुत आते हैं । मैंने उनको भी टोका है और इस तरफ के सदस्यों को भी टोकेंगे ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: It is a common man?s Budget.

माननीय अध्यक्ष **:** नो, ऐसा नहीं है । मैंने उनको भी रोका है और इधर भी रोकेंगे । ऐसा नहीं चलेगा । किसी को भी पोस्टर लेकर आने की इजाजत नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आठ बजने वाले हैं और समय खत्म होने वाला है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने उसको कार्यवाही से निकाल दिया है ।

? (व्यवधान)

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY: When this Budget announced that there are four castes ?Garib? ?Mahilayen?, ?Yuva? and ?Annadata?, I do not think that there should be anybody who can say that this caste system, as has been indicated in the Budget proposal, will be removed, and is to be removed. ? (*Interruptions*)